मेरी खेती

PAGE NO. 1-74, APRIL 2023

किसान समाचार

खेत खलियान
सरकारी नीतियां
मौसम व अन्य कृषि सुझाव
सब्ज़ी
फूल
औषधीय खेती
पशुपालन - पशुचारा
प्रगतिशील किसान

MERIKHETI

सम्पादकीय

खुशखबरी: यूपी में निजी नलकूपों के बिजली बिल में 100 प्रतिशत की छूट

योगी सरकार की तरफ से किसान भाइयों के लिए एक अच्छी खबर आई है। यूपी में बहुत वक्त से प्रतीक्षा कर रहे किसान भाइयों को इस समाचार से बड़ी राहत मिलगी।

बतादें, कि निकाय चुनाव आने वाले हैं। इससे पूर्व ही यूपी की योगी सरकार ने पूरे यूपी के लिए बड़ा उपहार प्रदान किया है। निकाय चुनाव से पूर्व यूपी सरकार द्वारा किसानों के लिए बड़ी घोषणा कर दी गई है। इसके चलते उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने जानकारी देते समय कहा है, कि योगी सरकार किसानों के निजी नलकूपों के बिजली बिल को माफ करेगी। दरअसल, योगी सरकार ने यूपी चुनाव के समय बिजली बिल माफ करने का एलान किया था। वहीं, वित्तीय वर्ष 2022-2023 में निजी नलकूप उपभोक्ताओं के बिजली बिल में 50 प्रतिशत की छूट प्रदान की थी। फिलहाल, एक बार पुनः योगी सरकार किसान भाइयों को राहत देने जा रही है।

किसान भाइयों हेतु 15000 करोड़ की व्यवस्था

योगी सरकार द्वारा आने वाले वित्तीय वर्ष में कृषकों के लिए बिजली बिल में 100 फीसद छूट प्रदान करने के लिए बजट में 15000 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। इसी कड़ी में यह कहा गया था, कि यूपी में किसानों को निजी नलकूपों के जरिए से सिंचाई हेतु बिजली बिल में 100 फीसद की छूट दी जाएगी। इसके अंतर्गत किसान भाइयों को योगी सरकार छूट प्रदान करने जा रही है। किसानों को निःशुल्क बिजली प्रदान करने का वादा बीजेपी द्वारा स्वयं के लोक कल्याण संकल्प पत्र में भी किया गया था।

यूपी में किसानों को एक अप्रैल से दी जाएगी निशुल्क बिजली
कुछ दिन पहले यूपी के उपमुख्यमंत्री सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने बाराबंकी में एक जन चौपाल में ऐलान करते हुए कहा था, कि एक अप्रैल से कृषकों को नलकूप द्वारा सिंचाई करने हेतु बिजली मुफ्त में दी जाएगी। यानी कि स्पष्ट है, कि फिलहाल उत्तर प्रदेश के किसानों को नलकूप द्वारा सिंचाई करने पर विघुत शुल्क नहीं देना पड़ेगा। योगी सरकार द्वारा किसान भाइयों को यूपी निकाय चुनाव से पूर्व यह बड़ा उपहार दिया गया है। क्योंकि बहुत सारे किसान मंहगाई के वक्त में विद्युत बिल को लेकर परेशान हैं।

-दिलीप यादव

खेत खलियान

लाखों किसानों को सिखाए जाएंगे उन्नत खेती के गुण, होगा फायदा

उत्तर प्रदेश में किसानों की आर्थिक मदद के लिए अब उन्हें उन्नत खेती के गुण सिखाए जाएंगे. इतना ही नहीं इंटरनेशनल मिलेट ईयर को सफल बनाने के लिए यूपी की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होने वाली है.

साल 2023 में पूरी दुनिया इंटरनेशनल मिलेट ईयर पूरी दुनिया मना रही है. यह आयोजन भारत की पहल पर हो रहा है. इस आयोजन को सफल बनाने के लिए जोरों पर तैयारियां की जा रही हैं. हालांकि खेती उत्तर प्रदेश में ज्यादातर लोगों की रोजी रोटी का साधन है.

उत्तर प्रदेश में दुनिया की सबसे ज्यादा उर्वरतम जमीन है. जोकि गंगेटिक बेल्ड का अधिकांश हिस्सा भी है. इतना ही नहीं उत्तर प्रदेश में ना तो पानी की कमी है, और ना ही मानव संसाधन की, जिसके चलते यहां पर खेती की संभावना भी अच्छी है.

उत्तर पदेश मात्र एक ऐसा राज्य है, जिसमें सिर्फ मात्र 11 रकबे का है, और 20 फीसद खाद्यान पैदा करता है. राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भी खेती बाड़ी में ज्यादा रूचि है. जिस वजह से अंतरराष्ट्रीय मिलेट को सफल बनाने के लिए यूपी की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है.

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर तैयारियां

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्र निर्देश के हिसाब से तैयारियां की जा रही हैं. इसके अलावा कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही के निर्देशों का पालन भी किया जा रहा है, उत्तर प्रदेश मिलेटस पुनरोद्धार कार्यक्रम को चलाने के पीछे की मंशा यही है कि, मिलेट्स से जुड़ी पोषण सम्बंधी खूबियों को लोगों तक पहुंचाएं. अच्छे स्वास्थ्य और पोषण सुरक्षा के लिए ज्यादा से ज्यादा लोग इनका किसी ना किसिया रूप से उपयोग उपभोग कर सकें.

इस योजना के तहत मिलेट्स फसलों में जैसे ज्वार, बाजरा, कोदो, सवा की खेती को बड़े पैमाने में बढ़ावा देने के लिए उचित प्रयास किये जा रहे हैं. यूपी सरकार मिलेट्स पुनरोद्धार कार्यक्रम में करीब 186.27 करोड़ रुपये खर्चा कर रही है.
साल 2021 से 2022 में कुल 10.83 लाख हेक्टेयर की एरिया में खास मिलेट्स फसलों का उत्पादन किया जाता है. इसमें बाजरा , ज्वार, कोदो और सावा का रकबा क्यों लाख हेक्टेयर में फैला हुआ है. यूपी की योगी सरकार ने साल 2026 से 2027 तक इनकी बुवाई का रकबा बढाकर तकरीबन 25 लाख हेक्टेयर करने का लक्ष्य तय किया है.

सरकार देगी फ्री में बीज

यूपी सरकार ने आने वाले चार सैलून में ढ़ाई लाख किसानों को फ्री में बीज देने का फैसल किया है. जिसके लिए वो 11.86 करोड़ रुपये भी खर्च करने वाली है. इतना ही नहीं मिलेट्स बीजों के उत्पादन के लिए सरकार की तरफ से साल 2023 से 2024 और साल 2026 से 2027 तक कुल 180 कृषक उत्पादक संगठनों को चार लाख रुपये प्रति एफपीओ (FPO) के हिअब से सीड मनी दी जाएगी. जिससे भविष्य में राज्य में मिलेट्स की तरह तरह की फसलों के बीज को स्थानीय स्तर पर किसानों को उपलब्ध करवा सकेंगे. इतना ही नहीं इस कार्यक्रम के लिए चार सालों में 7 करोड़ से भी ज्यादा की धन राशि खर्च की जाएगी.

बॉलीवुड के ये दिग्गज ढलती उम्र में कर रहे खेती, ऑर्गेनिक खेती को दे रहे बढ़ावा

क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि, बॉलीवुड के जो सितारे दुनियाभर के दिलों में राज करते हैं, वो अपनी ढलती उम्र में खेती बाड़ी भी कर सकते हैं? अगर नहीं, तो आपको बता दें ये बिलकुल सच है.

बॉलीवुड में खूबसूरत सितारों का भी अपना एक दौर था. उनपर फिल्माई गयी कहानियों और उनके किरदारों के लोग दीवाने हुआ करते थे. हालांकि आज की जनरेशन की जुबां पर बॉलीवुड के पुराने से पुराने दिग्गजों के गाने हैं. जो कभी पुराने नहीं हो सकते. समय बीतने के साथ साथ दौर भी बदल चुका है. कुछ सितारों की उम्र ढलने के साथ अब वो बड़े पर्दे को अलविदा कह चुके हैं. अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि, बॉलीवुड के ये सितारे लाइम लाइट में ना होकर आखिर कर क्या रहे हैं? तो आपको बता दें कि काफी सितारे अब खेती बाड़ी में जुट चुके हैं. साथ ही ऑर्गेनिक खेती (ORGANIC FARMING) को बढ़ावा भी दे रहे हैं.

बीते काफी समय में ऑर्गेनिक खेती का चलन काफी बढ़ गया है. जो लोगों को काफी ज्यादा पसंद भी आ रही है. जहां आम लोगों और किसानों का रुझान फार्मिंग की ओर बढ़ चुका है, तो वहीं बॉलीवुड भी इस तरफ इंटरेस्ट दिखा रहा है. बॉलीवुड के कई दिग्गज अपनी ढ़लती उम्र या रिटायरमेंट के बाद खेती बाड़ी में अपना समय बिता रहे हैं. इन नामों में जितेन्द्र और राखी जैसे बॉलीवुड के सितारों के नाम भी शामिल हैं. तो चलिए हम आपको कुछ ऐसे ही सितारों के बारे में बता रहे हैं, जो खेती बाड़ी का काम सम्भाल रहे हैं.

ये फ़िल्मी सितारे कर रहे खेती बाड़ी

राखी

मशहूर और बेहद खूबसूरत अदाकारा राखी एक समय में दर्शकों के दिल की धड़कन हुआ करती थीं. उनके बेमिसाल किरदार और अभिनय ने देश दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाई. अगर राखी को बॉलीवुड की जान कहा जाए तो गलत नहीं होगा. राखी ने अनगिनत फिल्मों में मुख्य अभिनय निभाया और लगबग हर मेल दिग्गज एक्टर के साथ काम भी किया. राखी ज्यादातर फिल्मों में मां के किरदार में भी नजर आई हैं. जो सुपर डुपर हिट हुईं हैं. मशहूर गीतकार गुलजार की पत्नी राखी अब बॉलीवुड से अलविदा कह चुकी हैं. इस वख राखी अपने पनवेल वाली फार्म हाउस (FARMHOUSE) में रहती हैं, और वहीं पर रहकर खेती का काम करती हैं.

लकी अली

बॉलीवुड के मशहूर सिंगरों में लकी अली का नाम भी शामिल है. लकी अली ने एक से एक गाने गाकर लोगों को अपना फैन बना लिया. लकी अली के गाये हुए गाने लोगों कि जुबां पर आज भी हैं.

हालांकि अब लकी अली बॉलीवुड में नजर नहीं आते और ना ही बॉलीवुड में काम कर रहे हैं. आजकल लकी अली ऑर्गेनिक खेती (ORGANIC FARMING) कर रहे हैं. सोशल मीडिया पर अक्सर लकी अली खेती बाड़ी से जुड़े वीडियो भी शेयर करते नजर आते रहते हैं.

धर्मेंद्र

धर्मेंद्र का नाम बॉलीवुड में सबसे ऊपर है. 87 साल के धर्मेंद्र बॉलीवुड से अभी भी जुड़े हुए हैं. धर्मेंद्र की फ़िल्में और डायलोग ज्यादातर लोगों को मुंह जुबानी याद हैं. प्रकृति से धर्मेंद्र के काफी ज्यादा प्यार है. लोनावाला स्थित फार्महाउस में रहकर धर्मेंद्र अपनी खेती बाड़ी का वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर करते रहते हैं. धर्मेंद्र जानवरों की देखभाल के साथ साथ ऑर्गेनिक खेती (ORGANIC FARMING) भी करते हैं. धर्मेंद्र के फार्महाउस में कई गाय हैं. धर्मेंद्र खुद ही सब्जियां उगाते हैं, और खाते भी हैं. इसलिए वो काफी फिट हैं. यहां तक उनका यह भी कहना है कि, जब तक मैं गोबर नहीं उठाता तब तक मेरे दिन की शुरुआत नहीं होती. धर्मेंद्र को इन सब कामों को करने में काफी मजा आता है.

जूही चावला

बॉलीवुड दीवा जूही चावला आजकल बड़े पर्दे पर सक्रिय नहीं हैं. उन्होंने इसके अलावा एक टीवी सीरियल भी किया है. आईपीएल में कोलकाता नाईट राइडर्स के सह मालिकों में से एक जूही चावला का भी नाम है. हालांकि इसके अलावा जूही चावला खेती का भी काम कर रही हैं. महाराष्ट्र के वाडा में जूही अपने फार्महाउस में खेती का काम कर रही हैं. बता दें जब से जूही के पिता का निधन हुआ है, तब से वह ऑर्गेनिक खेती (ORGANIC FARMING) का काम कर रही हैं.

प्रीटी जिंटा

प्रीटी जिंटा के डिंपल का हर कोई कायल है. इस खूबसूरत अदाकारा ने लाखों दिलों में अपनी जगह बेहतरीन अभिनय के जरिये बनाई है. हालांकि लंबे समय से प्रीटी जिंटा बॉलीवुड से कोसों दूर हैं. लेकिन आईपीएल में वह पंजाब किंग्स इलेवन टीम की सह मालकिन के तौर पर काम कर रही हैं. जब आईपीएल नहीं होता तो प्रीटी खेती करके अपना समय बिताती हैं. पिछले दो सालों से प्रीटी जिंटा खेती बाड़ी में लगी हुई हैं. जहां वो अपने सोशल अकाउंट पर ऑर्गेनिक खेती (ORGANIC FARMING) का वीडियो भी शेयर करती रहती हैं.

आर माधवन

बॉलीवुड में अभी भी नजर आने वाले आर माधवन अपनी डिसेंसी के लिए जाने जाते हैं. आज भी आर माधवन के गाने लोग गुनगुनाते हुए दिख जाते हैं. बॉलीवुड में सक्रिय रहने के बाद भी आर माधवन खेती बड़ी करते हैं. उन्होंने कुछ समय पहले नारियल की खेती के लिए जमीन खरीदी थी. लेकिन अब आर माधवन आर्गेनिक खेती (ORGANIC FARMING) भी कर रहे हैं.

फैजल खान

नवाजुद्दीन सिद्दीकी को बॉलीवुड का फैजल खान भी कहा जाता है. इनके बेहतरीन अभिनय ने बड़े पर्दे में एक से एक हिट फिल्में दी हैं. हालांकि आजकल नवाजुद्दीन सिद्दीकी अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर खासा चर्चा में हैं. इसके अलावा उन्हें खेती बाड़ी से भी काफी प्यार है. मौका मिलने पर वह यूपी में स्थित अपने गांव मुज्जफरनगर में खेती करने चले जाते हैं.

आलू का समुचित मूल्य ना मिलने पर लागत निकाल पाना भी हुआ मुश्किल

आलू की कीमत बेहद कम होने से सपा नेता शिवपाल सिंह यादव ने राज्य सरकार पर सीधा निशाना साधा है। उन्होंने एक ट्वीट के जरिए से कहा है, कि "सरकार का 650 रुपये प्रति क्विंटल की दर से आलू खरीदने का फरमान नाकाफी है"।

बेहतरीन पैदावार होने की वजह से इस बार उत्तर प्रदेश के साथ-साथ विभिन्न राज्यों में आलू के भाव में काफी गिरावट देखने को मिली है। इससे किसानों को लाभ तो दूर की बात है, फसल पर किया गया खर्च निकालना भी असंभव सा हो गया है। साथ ही, बहुत सारे किसान भाई कीमतों में आई गिरावट की वजह से आलू कोल्ड स्टोर में रखना सही समझ रहे हैं। भाव में बढ़ोतरी होने पर वह आलू बेचेंगे। ऐसी स्थिति में कोल्ड स्टोर के अंदर भी जगह का अभाव हो गया है। फिलहाल, किसान आलू की कीमत को निर्धारित करने के लिए सरकार से मांग की जा रही है। साथ ही, आलू का निर्यात शुरू करने के लिए भी स्वीकृति देने की गुहार की जा रही है।

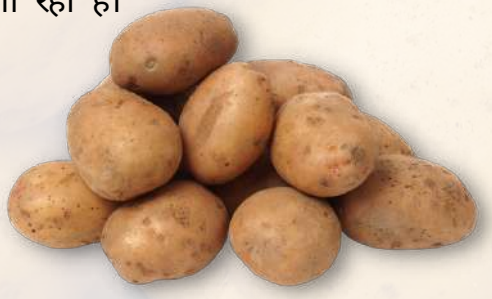

आलू की लागत तक नहीं निकाल पा रहे किसान

मीडिया खबरों के मुताबिक, पश्चिम बंगाल और बिहार में आलू की मांग में गिरावट होने की वजह से भी उत्तर प्रदेश में आलू के भाव में कमी देखने को मिली है। साथ ही, निर्यात ना होने की वजह से राज्य के कोल्ड स्टोर के अंदर आलू को रखने के लिए समुचित जगह का भी अभाव हो गया है। इन परिस्थितियों में किसान भाई सरकार से आलू का न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करने की मांग कर रहे हैं। किसानों ने बताया है, कि आलू का भाव कम होने की वजह से फसल पर किया गया खर्च निकालना भी कठिन सा हो रहा है। मुख्य रूप से कर्ज लेकर कृषि करने वाले किसान काफी घाटा सहकर आलू बेच रहे हैं। क्योंकि उनके पास कोल्ड स्टोर का किराया तक वहन करने की आर्थिक स्थिति नहीं है।

बाजार में फिलहाल आलू का क्या भाव है

हालांकि, उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से आलू का भाव निर्धारित कर दिया गया है। सरकार द्वारा ऐलान किया गया है, कि फिलहाल राज्य में 650 रुपये प्रति क्विंटल के भाव से आलू की खरीद की जाएगी।

परंतु, इसके उपरांत भी किसानों के चेहरे मायूस दिखाई दे रहे हैं। किसानों ने बताया है, कि प्रति क्विंटल आलू पर किया गया खर्च 800 रुपये के करीब है। अब इस परिस्थिति में हम आलू का विक्रय 650 रुपये क्विंटल किस तरह कर सकते हैं। बतादें, कि उत्तर प्रदेश की मंडियों में फिलहाल आलू का भाव 400 रुपये से 500 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से चल रहा है, जो किसान भाइयों के सिर दर्द की वजह बना हुआ है।

सरकार का 650 रुपये प्रति क्विंटल की दर से आलू खरीदने का फरमान नाकाफी है : शिवपाल यादव

साथ ही, 650 रुपये प्रति क्विंटल आलू का भाव निर्धारित करने पर सपा नेता शिवपाल सिंह यादव ने राज्य सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने ट्वीट के माध्यम से कहा है, कि "सरकार का 650 रुपये प्रति क्विंटल के मूल्य से आलू खरीदने का फरमान नाकाफी है। उन्होंने कहा कि 2500 रुपए प्रति क्विंटल की दर से बीज खरीदने वाले किसानों के लिए यह समर्थन मूल्य मजाक है। ऐसे में सरकार को न्यूनतम 1500 रुपए प्रति पैकेट की दर से आलू की खरीद करनी चाहिए।"

आलू का समुचित भाव ना मिलने पर निराश किसान ने सड़क पर फेंके आलू

बतादें कि इस वर्ष बिहार और पश्चिम बंगाल में भी आलू का बेहतरीन उत्पादन हुआ है। ऐसी स्थिति में ये दोनों राज्य उत्तर प्रदेश से आलू का आयात नहीं कर रहे हैं। आपको यह भी बतादें कि स्वयं बिहार के किसान भी आलू की कीमतों में आई गिरावट के चलते आलू सड़कों पर ही फेंक रहे हैं। शुक्रवार के दिन बिहार के बेगूसराय में एक हताश किसान ने आलू की समुचित कीमत न मिलने की वजह से 25 क्विंटल आलू को सड़क पर ही फेंक दिया था।

नुनहेम्स कंपनी की इम्प्रूव्ड नूरी है मोटल ग्रीन खीरे की किस्म

नुनहेम्स कंपनी की इम्प्रूव्ड नूरी है मोटल ग्रीन खीरे की किस्म

गर्मियों का सीजन शुरू हो चुका है. ऐसे में लोगों को गर्मी में कुछ रिफ्रेशिंग और नेचुरल चीजे खाने की सलाह दी जाती है. बात रोफ्रेशिंग और नेचुरल चीजों की हो तो कोई भला खीरे को कैसे भूल सकता है. जिसकी तासीर तो ठंडी होती ही है, साथ में शरीर के लिए भी बेहद फायदेमंद है.

पहले के समय में खीरे की खेती किसी ख़ास सीजन में हुआ करती थी. लेकिन पिछले कुछ सालों में उन्नत किस्मों के बीज और पाली हाउस जैसे जरिये की मदद से अब लोगों को साल भर तक खीरे खाने को मिलता है. तभी तो पूरी दुनिया भर में भारत खीरे के सबसे बड़ा निर्यातक बनकर उबर चुका है.

ज्यादातर मामलों में खीरे की बुवाई फरवरी से मार्च के महीने में की जाती है. खीरे की फसल गर्म और शुष्क वातावरण में की जाती है. साथ ही अच्छी जल निकाली वाली मिट्टी खीरे की फसल के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है. खीरा उन्हीं फसलों में से एक है, जिससे किसान भाइयों का अच्छा खासा मुनाफा हो सकता है.

कहां से हुई निर्यात की शुरुआत

भारत में खीरे का निर्यात साल 1990 के दशक में कर्नाटक से शुरू हुआ था. जिसका स्तर काफी छोटा था. बाद में तमिलनाडु के साथ आंध्र प्रदेश एयर तेलंगाना में भी निर्यात का काम शुरू हो गया. पूरी दुनिया भर में सिर्फ भारत में 15 फीसद खीरे का उत्पादन किया जाता है. भारत से लगभग 20 देशों से भी ज्यादा खीरे का निर्यात किया जाता है, जिसमें अमेरिका, फ्रांस, आस्ट्रेलिया, जर्मनी, स्पेन, दक्षिण कोरिया, कनाडा, जापान, चीन, रूस, श्री लंका और इजरायल जैसे देश हैं.

जानिए खीरे की उन्नत किस्मों के बारे में

वैसे तो खीरे की उन्नत किस्मों की भारत में भरमार है. जिनकी बुवाई से किसानों को भरपूर मुनाफा होता है. जिनमें पूसा संयोग और बरखा, स्वर्ण पूर्णिमा, स्वर्ण अनेति, पंजाब सलेक्शन जैसी ये सभी खीरे की अच्छी किस्मों में मानी जाती है. इनके अलावा खीरे की एक और किस्म भी है. जिसका नाम इम्प्रूव्ड नूरी है. जिसे नुनहेम्स कंपनी ने तैयार किया है. इस खास किस्म के चलते किसानों को डबल मुनाफा होता है.

किसानों को अच्छी और उपजाऊ फसलों के लिए बीज और नये नये किस्मों को उपलब्ध करवाने का काम नुनहेम्स कंपनी करती है. इसके अलावा यह कंपनी हरी सब्जियों और फलों की खेती के लिए बीज के साथ खेती करने का सही ढ़ंग भी किसानों को सिखाती है. ताकि उन्हें अच्छी और उन्नत फसलों का फायदा मिल सके. मोटल ग्रीन खीरे की किस्म इम्प्रूव्ड नूरी भी नुनहेम्स कंपनी की देन है. जिसकी उपज, आकार, परिपक्वता के साथ अन्य जानकारी भी जान लेनी चाहिए.

खीरे की किस्म है इम्प्रूव्ड नूरी

- नुनहेम्स कंपनी इस खीरे की किस्म की स्रोत है.
- लगभग 30 से 40 दिनों में यह पककर तैयार हो जाते हैं.
- इस किस्म के खीरे का आकार बेलनाकार होता है.
- इम्प्रूव्ड नूरी किस्म के खीरे की लम्बाई लगभग 18 से 22 सेंटीमीटर होती है.
- कुछ वायरस के लिए इस किस्म में प्रतिरोधी किस्म है.
- इस खीरे का रंग मीडियम हरा होता है.
- इस किस्म के खीरे में भी संतुलित पोषक तत्व होते हैं.
- इसकी उपज की बात की जाए तो इसमें काफी अच्छी उपज किसानों को मिलती है.

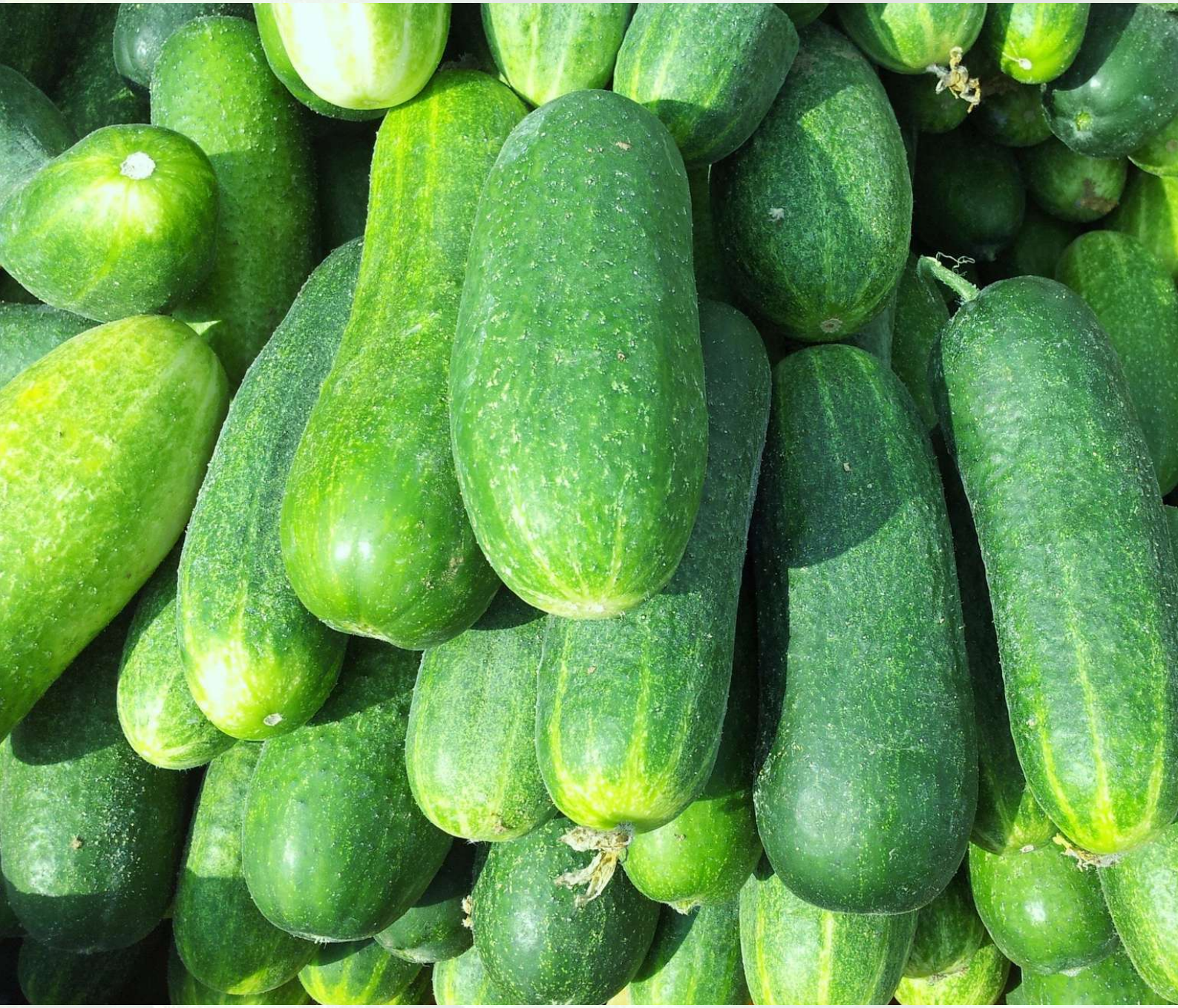

फल

आड़ू की खेती से किसान अच्छी आय कर सकते हैं, जानें विस्तृत जानकारी

भारतीय कृषक आजकल परिवर्तित होते जमाने में फिलहाल यह मानने लगे हैं, कि खेती केवल पारंपरिक फसलों की वजह बाकी फसलों का उत्पादन करना चाहिए। जिससे कि किसान खेती से बेहतरीन आमदनी हो पाए। कम वक्त के अंदर अधिक आय अर्जित की जा सके। इसी वजह से किसान आज धान, गेंहू की भांति पारंपरिक फसलों के स्थान पर फल, सब्जी एवं औषधीय पौधों पर भी जोर दिया जा रहा है। इस परिस्थिति में आपको आड़ू फल की कृषि की विधिवत प्रक्रिया बता रहे हैं।

आड़ू एक फलदार पर्णपाती वृक्ष है, जिसकी गिनती गुठली वाले वृक्षों में होती है। आड़ू के ताजे फलों का सेवन किया जाता है। साथ ही, आड़ू द्वारा कैंडी, जैम एवं जैली प्रकार की वस्तुऐं भी निर्मित की जाती हैं। इसके अतिरिक्त फल में शक्कर प्रचूर मात्रा में होती है। जिसकी वजह इसका फल खाने में खूब स्वादिष्ट एवं रसीला होता है। इसके अतिरिक्त आड़ू की गिरी के तेल का उपयोग विभिन्न प्रकार के कॉस्मेटिक उत्पाद एवं दवाईयां निर्माण में होता है। इसके अंदर लोहे, फ्लोराइड एवं पोटाशियम की प्रचूर मात्रा रहती है, आड़ू की मांग अत्यधिक होने की वजह से इसकी कृषि फायदेमंद है।

आड़ू की खेती के लिए कैसी जलवायु होनी चाहिए

आड़ू की खेती के लिए जलवायु ना तो ज्यादा ठंडी और ना ज्यादा गर्म रहनी चाहिए। इस फसल को कुछ निश्चित वक्त हेतु 7 डिग्री सेल्सियस से भी न्यूनतम तापमान की आवश्यकता होती है। ठंडों में देर में पाला पड़ने वाले क्षेत्रों में खेती उपयुक्त नहीं मानी जाती। आड़ू की कृषि घाटी, तराई, मध्य पर्वतीय क्षेत्र एवं भावर क्षेत्रों के सबसे अनुकूल मानी जाती है।

आड़ू की खेती के लिए भूमि कैसी होनी चाहिए

आड़ू की कृषि के लिए सर्वोत्तम मृदा बलुई दोमट है पर गहरी एवं उत्तम जल निकासी वाली होनी चाहिए। साथ ही, मृदा का PH मान 5.5-6.5 तक हो एवं काफी जीवांशयुक्त होना आवश्यक है।

आड़ू की खेती के लिए कैसी जलवायु होनी चाहिए

आड़ू की खेती के लिए जलवायु ना तो ज्यादा ठंडी और ना ज्यादा गर्म रहनी चाहिए। इस फसल को कुछ निश्चित वक्त हेतु 7 डिग्री सेल्सियस से भी न्यूनतम तापमान की आवश्यकता होती है। ठंडों में देर में पाला पड़ने वाले क्षेत्रों में खेती उपयुक्त नहीं मानी जाती। आड़ू की कृषि घाटी, तराई, मध्य पर्वतीय क्षेत्र एवं भावर क्षेत्रों के सबसे अनुकूल मानी जाती है।

आड़ू की खेती के लिए भूमि कैसी होनी चाहिए

आड़ू की कृषि के लिए सर्वोत्तम मृदा बलुई दोमट है पर गहरी एवं उत्तम जल निकासी वाली होनी चाहिए। साथ ही, मृदा का PH मान 5.5-6.5 तक हो एवं काफी जीवांशयुक्त होना आवश्यक है।

आड़ू की सिंचाई किस तरह करें

आड़ू के पौधरोपण के तुरंत बाद सिंचाई करनी चाहिए। फूलों के अंकुरण, कलम लगाने की स्थिति, फलों की प्रगति के वक्त फसल को सिंचाई की आवश्यकता होती है। आड़ू की कृषि में सिंचाई हेतु ड्रीप सिंचाई विधि बेहद ज्यादा फायदेमंद मानी जाती है।

अत्यधिक गर्मी होने से बाजार में फलों की उपलब्धता में आएगी कमी

अत्यधिक गर्मी होने से बाजार में फलों की उपलब्धता में आएगी कमी

आजकल गर्मी बढ़ने की वजह से भारत के विभिन्न क्षेत्रों में फलों एवं सब्जियों के उत्पादन में 10 से 30% फीसद तक की कमी देखने को मिलेगी। जैसे-जैसे गर्मी पास आ रही है। भारत में सब्जियों और फलों के उत्पादन का संकट बढ़ता दिख रहा है। विशेषज्ञों के अनुसार, आगामी दिनों में फल एवं सब्जियों के भाव सातवें आसमान पर हैं। इसका यह कारण है, कि वक्त से पूर्व गर्मी में बढ़ोत्तरी होने से फलों और सब्जियों के उत्पादन में करीब 30% प्रतिशत तक की गिरावट हो सकती है। नतीजतन इसका प्रभाव फलों के राजा आम पर वर्तमान से ही पड़ना शुरू हो गया है। किसानों के अनुसार, इस बार आम की बौर एवं फलों में काफी गिरावट देखने को मिली है। साथ ही, तापमान में अधिक वृद्धि होने की वजह से नींबू, तरबूज, केले, काजू और लीची की फसल भी प्रभावित हुई है।

(IIHR) के डायरेक्टर एसके सिंह ने इस विषय पर क्या कहा है

बेंगलुरु के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च (IIHR) के डायरेक्टर एसके सिंह के अनुसार, गर्मी में अचानक वृद्धि की वजह से भारत के विभिन्न क्षेत्रों में फलों एवं सब्जियों के उत्पादन में 10 से 30% तक की कमी हो सकती है। इसकी वजह समय से पहले गर्मी का होना है। इसकी वजह से आम, लीची, केले, अवाकाडो, कीनू, और संतरे की फसल प्रभावित हुई है। फरवरी माह का औसत तापमान भारत में 29.5 डिग्री सेल्सियस रहा था जो कि एक रिकॉर्ड है।

आपूर्ति में गिरावट आने की संभावना है

मौसम विभाग के जरिए मार्च से मई माह के मध्य भारत के नार्थ वेस्ट क्षेत्रों में गर्म हवा चलने की संभावना जताई गई है। वहीं, गर्मी में वृद्धि होने की वजह से सब्जियां वक्त से पूर्व पक रही हैं। इसी कारण से सब्जियों की आपूर्ति आवश्यकता से अधिक हो सकती है। लेकिन, कुछ समयोपरांत इसमें गिरावट भी हो सकती है। साथ ही, इसकी आपूर्ति में कमी आने से सब्जियों के भाव में वृद्धि देखने को मिलेगी।

भारत में अधिक आबादी होने से फलों व सब्जियों की होगी किल्लत

जैसा सा कि हम सब भली भाँति जानते हैं, कि भारत एक बड़ी आबादी वाला देश है। इसलिए यहां खाद्यान आपूर्ति को सुनिश्चित करने के लिए केंद्र व राज्य सरकारें काफी सजग और जागरूक रहती हैं। इसके साथ ही भारत एक कृषि प्रधान देश भी है। उपरोक्त में सब्जिओं और फलों के विषय में जैसा वर्णन किया गया है। उसका एक कारण यहां की घनी आबादी भी है। यदि अनाज और बागवानी फसलों में कमी आती है, तो इसका प्रत्यक्ष रूप से इसका असर आम जनता पर पड़ता है।

स्ट्रॉबेरी का फल देखने में काफी अच्छा लगता है, इसके लिए ऐसा मौसम होना चाहिए

स्ट्रॉबेरी एक ऐसा फल है, जो कि ना सिर्फ दिखने में बेहतरीन होता है, बल्कि स्वाद में भी उत्कृष्ट होता है। इसका उत्पादन शरद जलवायु वाले क्षेत्रों में किया जाता है। हमारे भारत देश में स्ट्रॉबेरी की कृषि ऐसे तो हिमाचल प्रदेश, कश्मीर और उत्तराखंड के उचाई वाले पहाड़ी इलाकों में की जाती है। दरअसल, फिलहाल समय परिवर्तन सहित बाकी प्रदेशों में भी इसकी कृषि की जा रही है। स्ट्रॉबेरी का पौधा थोड़े ही दिनों में फल देने हेतु तैयार हो जाता है। फिलहाल, किसान भाई पारंपरिक कृषि को दर किनार करके फलों व सब्जियों का उत्पादन कर रहे हैं। इसी क्रम में फिलहाल हम कृषकों को स्ट्रॉबेरी की कृषि के विषय में बताने जा रहे हैं।

स्ट्रॉबेरी की फसल कब उगाई जाती है

स्ट्रॉबेरी फल की प्रजातियाँ

हालाँकि यदि हम नजर डालें तो पूरे विश्व में स्ट्रॉबेरी की 600 से ज्यादा प्रजातियाँ उपस्थित हैं। जिनमें से देश में विशेष रुप से एलिस्ता, चांडलर, कमारोसा, फेयर फॉक्स, ओफ्रा और स्वीड चार्ली प्रजातियों का उत्पादन किया जाता है।

स्ट्रॉबेरी के उत्पादन के लिए खेत को किस तरह तैयार करें

स्ट्रॉबेरी के उत्पादन करने हेतु मृदा की गुणवत्ता बेहतर रहनी चाहिए। कृषि में पाटा लगाके मृदा को सूक्ष्म किया जाता है, जिसके उपरांत क्यारियां निर्मित की जाती हैं। स्ट्रॉबेरी के उत्पादन हेतु ध्यान रहे कि क्यारियों की उंचाई तकरीबन 15 सेंमी ऊंची रहनी चाहिए। साथ ही, पौधे से पौधे की दूरी एवं कतार से कतार की दूरी 30 सेमी रहनी चाहिए।

स्ट्रॉबेरी के पौधरोपण करने के कुछ वक्त उपरांत इसमें फूल आने चालू हो जाएंगे। इस दौरान आपको मंल्चिग विधि का उपयोग करना चाहिए। मल्चिंग का उपयोग करने से फसल में खरपतवार और फल खराब होने की आशंका बेहद कम रहती है। वहीं, उत्पादन भी अच्छा होता है।

स्ट्रॉबेरी की खेती के लिए कौन-सा इलाका अच्छा होता है

पहाड़ी राज्यों में जलवायु में ठंडक होने की वजह से स्ट्रॉबेरी का उत्पादन बेहद अच्छा होता है। परंतु, इसके साथ-साथ पहाड़ी क्षेत्रों में वर्षा होती रहती है, इसको ध्यान में रखते हुए किसानों को स्ट्रॉबेरी की खेती पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होती है। कृषि विशेषज्ञ वर्षा के दौरान स्ट्रॉबेरी के पौधों को पॉलीथीन द्वारा ढकने की राय देते हैं, जिससे कि फसल में सड़न – गलन ना आए। सिंचाई हेतु स्ट्रॉबेरी के पौधरोपण के उपरांत खेत में स्प्रिंकलर अथवा ड्रिप विधि द्वारा सिंचाई करनी चाहिए। स्ट्रॉबेरी के फल का पौधरोपण करने के 1.5 माह के समयोपराँत इसमें फल लगना चालू हो जाते हैं। ध्यान रहे कि फल लाल होने की स्थिति में किसान भाई इसकी तुड़ाई कर लें।

मशीनरी

इन कृषि यंत्रों पर सरकार दे रही है भारी सब्सिडी, आज ही करें आवेदन

सरकार लगातार किसानों कि आय बढ़ाने पर काम कर रही है। इसके लिए सरकार समय-समय पर किसानों को बहुत सारी मदद प्रदान करती है। इसमें सीधे तौर पर आर्थिक सहायता और सब्सिडी भी होती है, जिससे देश के किसान भाई लगातार लाभान्वित हो रहे हैं और सरकार द्वारा चलाई जा रही स्कीमों के माध्यम से अपनी आय बढ़ा रहे हैं।

कृषि की मशीनरी पर इस राज्य की सरकार दे रही है बम्पर सब्सिडी

केंद्र सरकार के साथ-साथ अब राजस्थान की सरकार अपने राज्य के किसानों को खेती की मशीनरी पर बम्पर सब्सिडी दे रही है। किसान भाई आवेदन करके बहुत आसानी से सीड ड्रिल/सीड कम फर्टीलाइजर ड्रिल, डिस्क प्लाऊ/ डिस्क हैरो, रोटोवेटर, मल्टी क्रॉप थ्रेसर, रिज फरो प्लांटर/ मल्टी क्रॉप प्लांटर/ ट्रेक्टर ऑपरेटेड रिपर, चिजल प्लाऊ जैसी मशीनों पर 50 प्रतिशत तक की सब्सिडी प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए किसान के नाम खुद की कृषि योग्य भूमि होनी चाहिए, साथ ही यदि कृषि यंत्र ट्रैक्टर द्वारा संचालित होता है तो ट्रैक्टर का रजिस्ट्रेशन किसान के नाम होना चाहिए।

राजस्थान के कृषि विभाग के अधिकारियों ने बताया है कि राज्य सरकार के द्वारा एक प्रकार के कृषि यंत्र पर 3 साल में सिर्फ एक बार ही सब्सिडी दी जाएगी। साथ ही एक किसान एक साल में अधिकतम 3 कृषि यंत्रों पर ही सब्सिडी प्राप्त कर सकेगा। साथ ही किसानों को सब्सिडी तब प्रदान की जाएगी जब किसान राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित निर्माता या विक्रेता से कृषि यंत्र की खरीदी करेंगे। राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित कृषि यंत्रों निर्माता या विक्रेताओं की सूची 'राज किसान साथी' पोर्टल पर उपलब्ध है।

सब्सिडी प्राप्त करने के लिए ऐसे करें आवेदन

किसान भाई कृषि यंत्रों पर सब्सिडी प्राप्त करने के लिए अपने नजदीकी ई-मित्र केंद्र पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इसके साथ ही किसान भाई सब्सिडी प्राप्त करने के लिए 'राज किसान पोर्टल' में भी आवेदन कर सकते हैं। आवेदनकर्ता के पास आवेदन के लिए आधार कार्ड, बैंक खाता, पासपोर्ट साइज़ फोटो, मोबाइल नंबर, जमाबंदी की नकल, जाति प्रमाण पत्र, जमीन के कागजात, ट्रैक्टर का पंजीयन प्रमाण पत्र जैसे दस्तावेज होना जरूरी हैं। आवेदन करते समय इन सभी दस्तावेजों की स्कैन कॉपी किसान को लगानी होगी।

कृषि विभाग के अधिकारियों द्वारा बताया गया है कि आवेदन करने के उपरांत कृषि पर्यवेक्षक/सहायक कृषि अधिकारी द्वारा कृषि उपकरण का सत्यापन किया जाएगा। साथ ही किसान को उपकरण खरीदी का बिल अधिकारियों को दिखाना होगा। इसके बाद यदि अधिकारी पूर्ण रूप से संतुष्ट होते हैं तो वो किसान का नाम आगे भेज देंगे। जिसके कुछ दिनों बाद किसान के बैंक खाते में सब्सिडी की राशि आ जाएगी।

सब्सिडी की इस योजना का लाभ उठाकर किसान भाई खेती बाड़ी में काम आने वाले कृषि यंत्र बेहद आसानी से और कम दामों में खरीद सकते हैं। यह कृषि यंत्र किसानों को खेती में सहूलियत प्रदान करेंगे, साथ ही इससे किसानों को कृषि कार्य में मेहनत भी कम करनी पड़ेगी, जिससे उत्पादकता बढ़ेगी और किसानों की आय में भी इजाफा होगा।

भारत में लॉन्च हुए ये 7 दमदार नए ट्रैक्टर

ट्रैक्टर एक ऐसी मशीन है जिसके बिना आज के युग में खेती कर पाना लगभग नामुमकिन सा हो गया है। इसलिए केंद्र के साथ-साथ राज्य सरकारें भी किसानों के लिए टैक्टर खरीदवाने का प्रयास कर रही हैं जिसके लिए कई राज्य सरकारें नई-नई योजनाएं लॉन्च करती रहती हैं। जिनमें ट्रैक्टर से लेकर कृषि उपकरण खरीद पर किसानों को भारी सब्सिडी प्रदान की जाती है। सरकारों के साथ ही ट्रैक्टर निर्माता कंपनियां भी इस सेक्टर में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं। खेती किसानी के काम को और अधिक सुगम बनाया जा सके, इसके लिए कंपनियां नई रिसर्च को बढ़ावा दे रही हैं। साथ ही ट्रैक्टरों के अत्याधुनिक तकनीक वाले नए मॉल्ड्स लांन्च कर रही हैं। जिनको देखकर किसान नया ट्रैक्टर खरीदने के लिए आकर्षित हो रहे हैं। इस साल कई कंपनियों ने अपने नए ट्रैक्टर लॉन्च किए हैं, जिनकी जानकारी हम आपको दे रहे हैं।

महिंद्रा नोवो 755 डीआई ट्रैक्टर

महिंद्रा नोवो 755 डीआई ट्रैक्टर चार सिलेंडर के साथ आने वाला 75 एचपी का ट्रैक्टर है। अगर इसके इंजन रेटेड आरपीएम की बात करें तो यह 2100 आरपीएम आता है। इसके साथ ही इस ट्रैक्टर की पीटीओ क्षमता 66 एचपी है। महिंद्रा के इस ट्रैक्टर में कंपनी ने 3500 सीसी का इंजन दिया है। इसमें कंपनी ने ड्यूल एक्टिंग पावर स्टीयरिंग भी दी है। इसके साथ ही ट्रैक्टर को ड्यूल-क्लच के साथ लॉन्च किया गया है। यह ट्रैक्टर मल्टी डिस्क ब्रेक के साथ आता है जिससे फिसलन की समस्या नहीं रहती।

महिंद्रा के इस ट्रैक्टर में 60 लीटर का फ्यूल टैंक आता है। यह ट्रैक्टर 2WD और 4WD दोंनों वेरियंट में उपलब्ध है। ट्रैक्टर का वजन 2600 किलोग्राम है। साथ ही इस ट्रैक्टर की कीमत 12.30 लाख रुपए से लेकर 12.90 लाख रुपये (एक्स शोरूम) है।

जॉन डियर 3036 ईएन ट्रैक्टर

जॉन डियर 3036 ईएन एक मिनी ट्रैक्टर है। जो 1500 सीसी इंजन के साथ आता है। यह तीन सिलेंडर इंजन के साथ आता है जो 2800 इंजन रेटेड आरपीएम जनरेट करता है। इस ट्रैक्टर में फ्यूल टैंक की क्षमता 32 लीटर है। साथ ही इसमें पीटीओ पावर 30.6 एचपी है। इस ट्रैक्टर की बाजार में कीमत 7.20 लाख रुपये से लेकर 7.80 लाख रुपये (एक्स शोरूम) तक है। जिसके कारण भारतीय बाजार में इसकी मांग तेजी से बढ़ रही है।

न्यू हॉलैंड एक्सेल 5510 ट्रैक्टर

न्यू हॉलैंड एक्सेल 5510 ट्रैक्टर 3 सिलेंडर वाला 50 एचपी का ट्रैक्टर है। इसकी पीटीओ पावर 46 एचपी है। यह 2931 सीसी इंजन के साथ आता है, जिसमें कंपनी की तरफ से सिंक्रोमेश ट्रांसमिशन दिया गया है। यह ट्रैक्टर हाइड्रोस्टेटिक स्टीयरिंग के साथ आता है, जिसमें 100 लीटर का फ्यूल टैंक दिया गया है। ट्रैक्टर 2500 किलोग्राम तक का वजन उठाया सकता है। इसके साथ ही ट्रैक्टर में कंपनी ने कई एडवांस फीचर्स दिए हैं जो अन्य ट्रैक्टरों में नहीं आते हैं। इस ट्रैक्टर की बाजार में कीमत 9.97 लाख रुपये से लेकर 11.65 लाख रुपये (एक्स शोरूम) तक है।

मैसी फर्ग्यूसन 8055 मैग्नाट्रैक ट्रैक्टर

इस ट्रैक्टर को हाल ही में मैसी ने लॉन्च किया है। जो 3 सिलेंडर के बेहद शक्तिशाली 3300 सीसी के इंजन के साथ आता है। यह ट्रैक्टर 50 एचपी के साथ आता है, जिसमें पीटीओ पावर 46 एचपी है। इस ट्रैक्टर में कंपनी ने ड्यूल क्लच ऑफर की हैं। इस ट्रैक्टर में 8 फॉरवर्ड और 2 रिवर्स गियर दिए गए हैं। इस ट्रैक्टर की बाजार में कीमत 6.80 लाख रुपये से लेकर 7.40 लाख रुपये (एक्स शोरूम) है।

फार्मट्रैक 60 ट्रैक्टर

फार्मट्रैक 60 ट्रैक्टर एक शानदार ट्रैक्टर है जो 3 सिलेंडर इंजन के साथ आता है। यह 50 एचपी का ट्रैक्टर है जो 2200 आरपीएम जनरेट करता है। फार्मट्रैक 60 ट्रैक्टर में 3147 सीसी का इंजन आता है। जो 2200 इंजन रेटेड आरपीएम जनरेट करता है। इस ट्रैक्टर में फ्यूल टैंक की क्षमता 50 लीटर आती है। इसके गियर बॉक्स में 8 फॉरवर्ड और 2 रिवर्स गियर आते हैं। यह ट्रैक्टर 1400 किलोग्राम तक वजन उठा सकता है। इस ट्रैक्टर की कीमत 7.10 लाख रुपये से लेकर 7.40 लाख रुपये (एक्स शोरूम) है।

प्रीत 6049 सुपर ट्रैक्टर

प्रीत 6049 सुपर एक शक्तिशाली ट्रैक्टर है जो 3 सिलेंडर के 4087 सीसी इंजन के साथ आता है। इसमें कंपनी पावर स्टीयरिंग के साथ ड्यूल क्लच ऑफर करती है। इस ट्रैक्टर में 60 लीटर का फ्यूल टैंक आता है। साथ ही यह ट्रैक्टर 2200 किलोग्राम तक का भार उठा सकता है।

वीएसटी 929 डीआई, ईजीटी ट्रैक्टर

कंपनी ने इस ट्रैक्टर को शानदार डिजाइन के साथ लॉन्च किया है। यह 28 एचपी का ट्रैक्टर है जो तीन सिलेंडर के साथ आता है। इस ट्रैक्टर का इंजन रेटेड 2400 आरपीएम है। इसके साथ ही इसके गियर बॉक्स में 8 फॉरवर्ड और 2 रिवर्स हैं। साथ ही यह पावर स्टीयरिंग के साथ आता है जो 750 किलोग्राम तक का वजन उठाने में सक्षम है। इस ट्रैक्टर की बाजार में कीमत 4.80 लाख रुपये से लेकर 6.10 लाख रुपये (एक्स शोरूम) तक है।

मौसमी व अन्य कृषि सुझाव

अमेरिकी चिया बीज की खेती से किसान भाई कमा रहे हैं जबरदस्त मुनाफा

अमेरिकी चिया बीज की खेती से किसान भाई कमा रहे हैं जबरदस्त मुनाफा

महाराष्ट्र के किसान इन दिनों प्याज और कपास की खेती में बढ़ती हुई लागत और कम होते मुनाफे को देखते हुए परेशान हैं। मंडी में अब इन फसलों के ठीक-ठाक रेट मिलना लगभग मुश्किल सा हो गया है। ऐसे में महाराष्ट्र के नांदेड जिले के किसानों ने अमेरिकी चिया बीज की खेती शुरू की है। इस खेती से स्थानीय किसान जबरदस्त मुनाफा कमा रहे हैं, जिससे किसान भाइयों की आर्थिक स्थिति तेजी से बदल रही है।

बाजार में है जबरदस्त मांग

इन दिनों अमेरिकी चिया बीज की बाजार में जबरदस्त मांग है। जिसके कारण ये फसल हाथों हाथ बिक जाती है और किसानो को फसल का उचित दाम भी मिलता है। चिया बीज का उपयोग ज्यादातर दवाइयां बनाने में किया जाता है इसलिए कई बार व्यापारी सीधे किसान के खेत से ही ऐसी फसलें खरीद ले जाते हैं, जिससे किसानों को बाजार में जाकर अपनी फसल को बेंचने में मेहनत नहीं करनी पड़ती।

हाल ही में नादेड़ में एक किसान ने ढाई एकड़ में अमेरिकी चिया बीज की फसल बोई थी जिसमें उन्हें 11 क्विंटल तक की उपज मिली है। उन्होंने बताया है कि उनकी यह फसल प्रति क्विंटल 70 हजार रुपये के भाव से बिकी है। जिससे उन्हें जबरदस्त मुनाफा हुआ है। किसान ने बताया है कि यह एक ऐसी फसल है जो बेहद कम लागत में ज्यादा उपज देती है, साथ ही इसका दाम भी अन्य फसलों की अपेक्षा ज्यादा रहता है।

मात्र इतनी आती है इस फसल में लागत

किसान ने बताया कि उन्होंने मध्य प्रदेश से साढ़े सात किलो बीज मंगवाया था, जिसके लिए उन्हें 20 हजार रुपये चुकाने पड़े थे। इसके बाद उन्होंने इन बीजों को ढाई एकड़ जमीन में बोया था। किसान ने बताया कि इस फसल पर किसी भी प्रकार के कीट का प्रकोप नहीं पड़ता, साथ ही न इस फसल को किसी भी प्रकार के जानवर खाते हैं। इसलिए इस फसल में अन्य फसलों की अपेक्षा मेहनत भी कम लगती है। चिया बीज की फसल में 7-8 बार सिंचाई करना बेहद जरूरी होता है। इसके अलावा बुवाई के बाद फसल पर किसी भी प्रकार के खाद का छिड़काव करने की जरूरत भी नहीं होती।

किसान ने बताया है कि उन्हें इस फसल की खेती करने पर जबरदस्त मुनाफा हुआ है। उन्हें फसल बेंचने पर एक क्विंटल बीजों पर 70 हजार रुपये मिले हैं। उन्हें इस बार 11 क्विंटल उपज हांसिल हुई है, इस हिसाब से उन्होंने अभी तक 7 लाख रुपये से ज्यादा की कमाई कर ली है। चिया बीज का उपयोग विशेषकर वजन घटाने के लिए किया जाता है। इसके अलावा मधुमेह, रक्तचाप, हृदय रोग और सौंदर्य उपचार में भी इसका बहुतायत से उपयोग किया जाता है इसलिए दवा निर्माता कंपनियों के बीच इसकी जबरदस्त मांग बनी रहती है।

किसान ने बताया है कि उसने अन्य फसलों की खेती में घाटा लगने के कारण अमेरिकी चिया बीज की खेती शुरू की थी। जिसके उन्हें अच्छे परिणाम प्राप्त हुए हैं। अब वो अपने अलावा क्षेत्र के दूसरे किसानों को भी अमेरिकी चिया बीज की खेती करने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं, जिसके सकारात्मक परिणाम देखने को मिल रहे हैं।

आलू के बाद अब गेहूं का समुचित मूल्य ना मिलने पर किसानों में आक्रोश

उत्तर प्रदेश में आलू का बेहद कम दाम मिलने की वजह से किसानों में काफी आक्रोश है। ऐसी हालत में फिलहाल गेहूं के दाम समर्थन मूल्य से काफी कम प्राप्त होने पर शाजापुर मंडी के किसान काफी भड़के हुए हैं, उन्होंने सरकार को चेतावनी देते हुए परेशानियों पर ध्यान देने की बात कही गई है।

आलू के उपरांत फिलहाल यूपी के किसान गेहूं के दाम कम मिलने से परेशान हैं। प्रदेश के किसान गेहूं का कम भाव प्राप्त होने पर राज्य की भारतीय जनता पार्टी की सरकार से गुस्सा हैं। प्रदेश की शाजापुर कृषि उत्पादन मंडी में उपस्थित किसानों ने सरकार के विरुद्ध प्रदर्शन व नारेबाजी की है। किसानों ने बताया है, कि कम भाव मिलने के कारण उनको हानि हो रही है एवं यदि गेहूं के भाव बढ़ाए नहीं गए तो आगे भी इसी तरह धरना-प्रदर्शन चलता रहेगा।

कृषि उपज मंडी में जब एक किसान भाई अपना गेहूं बेचने गया, जो 1981 रुपये क्विंटल में बिका। किसान भाई का कहना था, कि केंद्र सरकार द्वारा गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2125 रुपये क्विंटल निर्धारित किया गया है। इसके बावजूद भी यहां की मंडी में समर्थन मूल्य की अपेक्षा में काफी कम भाव पर खरीद की जा रही है। उन्होंने चेतावनी देते हुए बताया है, कि सरकार को अपनी आंखें खोलनी होंगी एवं मंडियों पर कार्रवाई करनी चाहिए। उन्होंने बताया है, कि सरकार किसानों की दिक्कत परेशानियों को समझें।

आक्रोशित एवं क्रोधित किसानों का नेतृत्व किसानों के संगठन भारतीय किसान संघ के जरिए किया जा रहा है। संगठन का मानना है कि, सरकार को किसानों की मांगों की ओर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। खून-पसीना एवं कड़े परिश्रम के उपरांत भी किसानों को उनकी फसल का समुचित भाव नहीं मिल पा रहा है।

आलू किसानों की परिस्थितियाँ काफी खराब हो गई हैं

उत्तर प्रदेश में आलू उत्पादक किसान भाइयो की स्थिति काफी दयनीय है। आलू के दाम में गिरावट आने की वजह से किसान ना कुछ दामों में अपनी फसल बेचने पर मजबूर है। बहुत से आक्रोशित किसान भाइयों ने तो अपनी आलू की फसल को सड़कों पर फेंक कर अपना गुस्सा व्यक्त किया है। ऐसी परिस्थितियों में विरोध का सामना कर रही उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 650 रुपये प्रति क्विंटल के मुताबिक आलू खरीदने का एलान किया है। परंतु, किसान इसके उपरांत भी काफी गुस्सा हैं। कुछ किसानों द्वारा आलू को कोल्ड स्टोर में रखना चालू कर दिया है। दामों में सुधार होने पर वो बेचेंगे, परंतु अब कोल्ड स्टोर में भी स्थान की कमी देखी जा रही है। ऐसी स्थितियों के मध्य किसान हताश और निराश हैं।

राज्य में शुरू हुई ब्लू मशरूम की खेती, आदिवासियों को हो रहा है बम्पर मुनाफा

विश्व में मशरूम की खेती हजारों सालों से की जा रही है लेकिन भारत में इसकी खेती मात्र 3 दशक पहली ही शुरू हुई है। अगर हाल ही के कुछ वर्षों में गौर करें तो भारत में लोगों के बीच मशरूम खाने का चलन बढ़ा है, जिसके कारण बाजार में मशरूम की लगातार मांग बढ़ती जा रही है। प्रकृति में मशरूम की हजारों किस्में मौजूद हैं, इनमें से कुछ किस्में ही खाने योग्य होती हैं। इन दिनों मशरूम से बने व्यंजन उच्च श्रेणी के माने जाते हैं, जिसके कारण लोगों के बीच इसकी लोकप्रियता बढ़ती जा रही है।

मशरूम की बढ़ती हुई मांग को देखते हुए हाल ही कुछ वर्षों में मशरूम की खेती को लेकर भी देश के किसानों के बीच इसकी लोकप्रियता बढ़ती जा रही है। चूंकि मशरूम का भाव भी अच्छा रहता है इसलिए किसानों का इसकी खेती की तरफ रुझान तेजी से बढ़ रहा है। अब कई राज्यों में अन्य किसानों के साथ-साथ आदिवासी लोग भी मशरूम की खेती की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। जिसके कारण अब राज्यों के आदिवासी इलाकों में भी मशरूम की खेती बड़े पैमाने पर की जाने लगी है।

इन दिनों महाराष्ट्र के सतपुड़ा जंगल के अंतर्गत आने वाले नंदुरबार जिले में मशरूम की खेती की जा रही है। इस खेती में ज्यादातर आदिवासी सक्रिय हैं। पहले यहां इस खेती को असंभव माना जाता था लेकिन यहां के लोगों ने सरकार द्वारा चलाई जा रही स्कीमों के अंतर्गत प्रशिक्षण लेकर इस खेती को संभव बनाया है। मशरूम की खेती के प्रशिक्षण की वजह से अब बहुत से बेरोजगार लोग इसकी खेती करने में लग गए हैं जिससे जिले में बेरोजगारी कम हुई है। साथ ही जिले के युवा मशरूम की खेती करके अच्छा खास मुनाफा कमा रहे हैं।

महाराष्ट्र का नंदुरबार जिला आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से काफी पिछड़ा हुआ है। जिसके कारण यहां के लोगों के लिए आमदनी के स्रोत बेहद सीमित हैं। ऐसे में ब्लू मशरूम की खेती आदिवासी युवाओं के लिए वरदान साबित हो रही है। इसकी खेती से युवा जमकर पैसा काम रहे हैं, जिससे उन्हे अपना परिवार चलाने में काफी मदद मिल रही है।

देखा गया है कि मशरूम की खेती करने वाले ज्यादातर युवा किसान बेहद छोटी सी जगह में ब्लू ऑयस्टर मशरूम की खेती कर रहे हैं। यह बेहद तेजी से विकसित होने वाला मशरूम की किस्म है जो मात्र 15 दिनों के भीतर ही तुड़ाई के योग्य हो जाता है। इससे महीने में 2 से 3 बार तक युवा किसान इसकी फसल को बाजार में बेंच रहे हैं और पैसे कमा रहे हैं। 10 बाय 10 की छोटी सी जगह में खेती करने वाले किसान भी हर महीने 10 से 12 हजार रुपये तक कमा लेते हैं। मशरूम की खेती में बम्पर कमाई को देखते हुए अब अन्य युवा भी इसकी खेती की तरफ तेजी से आकर्षित हो रहे हैं।

सरकारी नीतियां

'सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम प्रतियोगिता' में अपने गांव को शामिल करने के लिए ऐसे करें आवेदन

शहरों और प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों के साथ-साथ अब गावों में पर्यटन तेजी से बढ़ा है। पिछले कुछ सालों से ग्रामीण संस्कृति और ग्रामीण जीवन का पता लगाने के लिए बहुत सारे सैलानी हर साल गावों में पहुंच रह हैं। हाल ही में भारत सरकार ने भी ग्रामीण इलाकों को पर्यटन के रूप में प्रोत्साहित करना शुरू कर दिया है। इसके तहत भारत सरकार का पर्यटन मंत्रालय ने एक प्रतियोगिता आयोजित कर रहा है, जिसे 'सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम प्रतियोगिता' का नाम दिया गया है। यह प्रतियोगिता स्थानीय कला, संस्कृति और जीवन शैली को संरक्षित करने एवं उन्हें बढ़ावा देने वाले गावों के बीच आयोजित की जाएगी।

सरकार को आशा है कि उनके प्रयास गावों में सकारात्मक परिवर्तन, विकास और सामुदायिक कल्याण के लक्ष्य को पूरा करेंगे। साथ ही ग्रामीण इलाकों में भी पर्यटन का विस्तार होगा जिससे लोग भारत के ग्रामीण परिवेश को अच्छे से समझ सकेंगे। इसके साथ ही पर्यटन बढ़ने से ग्रामीण स्तर पर लोगों की आय में इजाफा होगा।

ये हैं प्रतियोगिता में शामिल होने के लिए योग्यता एवं चयन मापदंड

'सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम प्रतियोगिता' में शामिल होने के लिए भारत सरकार के आधीन काम करने वाले पर्यटन मंत्रालय नें देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से आवेदन आमंत्रित किए हैं। इस प्रतियोगिता में शामिल होने के लिए गांव की जनसंख्या का घनत्व बेहद कम होना चाहिए। यह किसी भी हालात में 25,000 लोगों से ज्यादा नहीं होना चाहिए। साथ ही गांव आकर्षक पर्यटन स्थलों के दायरे में भी स्थित होना चाहिए। मंत्रालय ने कहा है कि यदि गांव में कृषि, शिल्प, व्यंजन और सामुदायिक मूल्यों के इतिहास सहित पारंपरिक गतिविधियां होती है तो यह भी उस गांव के लिए पात्रता का एक मापदंड माना जाएगा।

इच्छुक ग्रामवासी पर्यटन मंत्रालय की वेबसाइट पर ऑनलाइन माध्यम से 15 अप्रैल, 2023 के पहले अपने गांव का आवेदन जमा कर सकते हैं। ऑफलाइन आवेदन मान्य नहीं होंगे। इसके साथ ही सिर्फ अंग्रेजी में लिखे गए आवेदन ही मान्य किए जाएंगे।

मंत्रालय ने बताया है कि इन बिंदुओं पर प्रतियोगिता में गावों को विजेता घोषित किया जाएगा

सांस्कृतिक और प्राकृतिक संसाधन, सांस्कृतिक संसाधनों का संवर्धन और संरक्षण, आर्थिक स्थिरता, सामाजिक स्थिरता, पर्यावरणीय स्थिरता, पर्यटन विकास और मूल्य श्रृंखला एकीकरण, शासन और पर्यटन की प्राथमिकता, इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी, स्वास्थ्य, सुरक्षा और सुरक्षा। इस प्रतियोगिता के अंतर्गत हर जिले से तीन सर्वश्रेष्ठ गांवों का चयन किया जाएगा। इसके लिए आवेदन की जांच जिला पर्यटन अधिकारियों द्वारा की जाएगी। इसके बाद इसे राज्य स्तर पर भेजा जाएगा। इसके बाद हर राज्य से 3 गांवों का चयन करके राष्ट्रीय स्तर पर भेज दिया जाएगा। जहां किसी एक गांव को इस प्रतियोगिता में विजेता घोषित किया जाएगा।

पीएम नरेंद्र मोदी का हमेशा से प्रयास रहा है कि देश में पर्यटन को बढ़ावा दिया जाए, क्योंकि पर्यटन बेहतर अर्थव्यवस्था के लिए उपयोगी सेक्टर साबित हो सकता है। पर्यटन उद्योग में बड़ी संख्या में रोजगार निर्मित होने की संभावनाएं हैं, साथ ही यह देश की जीडीपी में बाद योगदान दे सकता है। इसके अलावा यह उद्योग अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश की सॉफ्ट पावर को भी बढ़ता है।

इस राज्य में 3000 महिलाएं होंगी सशक्त 1705 आंगनबाड़ी केंद्रों को मिलेगा पौष्टिक आहार

आपकी जानकारी के लिए बतादें कि बांदा जिले में चलने वाले 1705 आंगनबाड़ी केंद्रों पर वर्तमान में पोषाहार की आपूर्ति बाहर से की जा रही है। हालाँकि, अब शीघ्र ही बुंदेलखंड में तैयार किए जा रहे पोषाहार के माध्यम से बच्चे, महिलाएं एवं किशोरियों का स्वास्थ्य काफी बेहतर होगा।

उत्तर प्रदेश राज्य के बांदा जनपद में स्वयं सहायता समूह की करीबन 3000 महिलाएं वर्तमान में पोषाहार तैयार करके उड़ान भरेंगी। इन महिलाओं के माध्यम से स्वयं अपना धन खर्चकर 9000000 रुपए की लागत से टीएचआर इकाई की स्थापना की है। इसी माह से इसमें पोषाहार तैयार होने लग जाएगा एवं महिलाएं समस्त आंगनबाड़ी केंद्रों में इसकी आपूर्ति किया करेंगी।

इन उद्योगों से जिले के 300 समूह जोड़े जाएंगे

इसी प्रकार महुआ एवं बबेरू ब्लॉक में भी टीएचआर प्लांट निर्माणाधीन है, जहां पर मई माह से पोषाहार तैयार होना चालू हो जाएगा। इन उद्योगों से जिले के 300 समूह प्रत्यक्ष रूप से जुड़ेंगे एवं रोजगार के माध्यम से स्वयं आय में बढ़ोत्तरी करेंगे। आपकी जानकारी के लिए बतादें कि शासन नारी सशक्तिकरण के अंतर्गत ग्रामीण महिलाओं को योजनाओं से जोड़के उनको रोजगार देने के पथ पर अग्रसर है। विशेष बात तो यह है, कि पशुपालन, मनरेगा, आपूर्ति विभाग एवं जिला कार्यक्रम विभाग की योजनाओं को महिलाओं के द्वारा संचालित किए जाने पर जोर दिया जा रहा है।

एक समूह से 30000 रुपये इकट्ठे किए जाएंगे

खबरों के अनुसार, जिले में सुचारू 1705 आंगनबाड़ी केंद्रों पर वर्तमान में पोषाहार की आपूर्ति बाहर से की जाती है। परंतु, फिलहाल अति शीघ्र ही बुंदेलखंड में निर्मित पोषाहार से बच्चे, किशोरियां और महिलाओं का बेहतरीन स्वास्थ्य बनेगा। प्रदेश ग्रामीण आजीविका मिशन की तरफ से जिले के 3 ब्लॉक बबेरू, महुआ एवं बड़ोखर खुर्द में टेक होम राशन टीएचआर प्लांट स्थापित किया जाएगा। जरुरी बात यह है, कि एक प्लांट का खर्च तकरीबन 9000000 रुपए है। यह धनराशि स्वयं सहायता समूह की महिलाएं निजी फंड से लगा रही हैं। प्रत्येक समूह से 30000 रुपये इकट्ठे किए गए हैं।

जानें कितने खाद्य पदार्थ तैयार किए जाएंगे

टीएचआर प्लांटों के माध्यम से जिले की 3000 महिलाओं की आजीविका के लिए रोजगार का अवसर प्राप्त होगा। इस प्लांट में बच्चों के लिए आंगनवाड़ी केंद्रों में बटने वाला पोषाहार तैयार किया जाएगा। एक प्लांट के अंतर्गत 100 समूह मतलब कि लगभग 1000 महिलाओं को जोड़ा जाएंगा। महिलाओं द्वारा प्लांट में बर्फी, एनर्जी हलवा, प्रीमिक्स मूंग, दाल, खिचड़ी, आटा, बेसन, हलवा निर्मित किया जाएगा। यह खाद्य पदार्थ खाद्यान हेतु तैयार होगें, जो कि पैकेट में बिल्कुल बंद रहेंगे।

अप्रैल से खाद्यान सामग्री की आपूर्ति करेंगे

खाद्यान सामग्री की आपूर्ति 1 अप्रैल से आंगनवाड़ी केंद्र में करने की योजना है। दूरस्थ एड़ी में विशिष्ट मंडी स्थल के समीप निर्मित किए टीएचआर प्लांट में लगभग कार्य पूर्ण हो गया है। मुख्य विकास अधिकारी वेद प्रकाश मौर्या ने इसके संदर्भ में सोमवार को निरीक्षण किया था एवं 1 हफ्ते में इसकी शुरूआत करने के निर्देश भी दिए गए हैं। इससे महिलाओं के सशक्तिकरण को काफी प्रोत्साहन मिलेगा।

यह राज्य सरकार पानी बचाने के लिए दे रही है पैसा, 85 प्रतिशत तक मिल सकती है सब्सिडी

ग्लोबल वार्मिंग और भूमिगत जल के अत्याधिक दोहन के कारण धरती का भूजल स्तर तेजी से गिर रहा है, ऐसे में लोगों के साथ ही किसानों के सामने भी भविष्य में बड़ी परेशानी सामने आ सकती है। जहां लोगों के लिए पेयजल एवं किसानों के लिए सिंचाई के लिए जल की उपलब्धता में कमी आ सकती है। क्योंकि इन दिनों खेती किसानी में पानी का बहुतायत में उपयोग किया जा रहा है। खेती किसानी में अब नए यंत्रों का इस्तेमाल भी किया जा रहा है जो पानी की बेतहासा बर्बादी करते हैं। खेतों में पानी की सिंचाई करके किसान भाई अच्छी खासा उत्पादन करते हैं जिनसे उन्हें मुनाफा होता है। लेकिन भूमिगत जल के कम होने की समस्या बेहद विकराल रूप ले चुकी है।

गिरते हुए भूमिगत जल को देखते हुए अब सरकार ने दूसरी सिंचाई पद्धतियों को अपनाना शुरू कर दिया है जिससे पानी की खपत को कम किया जा सके। इसमें ड्रिप सिंचाई एक बेहतरीन तकनीक है जिससे किसान भाई भारी मात्रा में पानी की बचत कर सकते हैं। इसके साथ ही सूक्ष्म सिंचाई मॉडल ने भी कम होते पानी की चिंता को दूर किया है। इसके लिए सरकार किसानों को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत सूक्ष्म सिंचाई सिस्टम लगवाने के लिए सब्सिडी प्रदान कर रही है।

इसी को देखते हुए अब हरियाणा की सरकार भी आगे आई है और हरियाणा की सरकार ने कहा है कि ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई पद्धति अपनाने और रिचार्जिंग बोरवेल इंस्टॉल करवाने वाले किसानों को सब्सिडी प्रदान की जाएगी। सरकारी अधिकारियों का कहना है कि इससे क्षय होते भूमिगत जल को रोका जा सकता है साथ ही पानी के संचयन में विशेष मदद मिलने वाली है। इससे भूमिगत जल को तेजी से रिकवर किया जा सकता है।

किसानों को इतनी मिल सकती है सब्सिडी

इन दिनों अगर सिंचाई की बात करें तो भूमि के एक बहुत बड़े हिस्से की सिंचाई भूमिगत जल के द्वारा की जाती है। जिसके कारण भूमिगत जल का लगातार इस्तेमाल किया जा रहा है। जो पर्यावरण में नकारात्मक प्रभाव डाल रहा है। हालांकि इससे बागवानी फसलों को प्रोत्साहन मिल रहा है लेकिन इससे फायदे होने की जगह नुकसान ज्यादा हैं। इसको देखते हुए अब हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने घोषणा की है कि सूक्ष्म सिंचाई मॉडल अपनाने के लिए अब किसानों को 85% तक की सब्सिडी दी जाएगी। इस मॉडल में किसानों को ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई को अपनाना होगा। ये किसानों के लिए बेहद सस्ता और सुविधाजनक भी है।

पहले चरण में इतने लोगों को दी जाएगी सब्सिडी

सरकार ने बताया है कि सूक्ष्म सिंचाई मॉडल के अंतर्गत गिरते भूजल स्तर को वापस रिकवर करने के लिए सरकार रीचार्जिंग बोरवेल लगाने की योजना पर काम कर रही है। जिससे बरसात के पानी का संचयन करके उसे वापस जमीन में पहुंचाया जा सके। सरकार ने बताया है कि रीचार्जिंग बोरवेल लगाने के लिए किसान को मात्र 25 हजार रुपये खर्च करने होंगे। इसके बाद जो भी खर्च आता है वो हरियाणा की सरकार वहन करेगी। पहले चरण में राज्य में सरकार ने 1 हजार रीचार्जिंग बोरवेल लगाने का लक्ष्य रखा है।

सब्सिडी प्राप्त करने के लिए इस प्रकार करें आवेदन

हरियाणा सरकार की ओर से कहा गया है कि अब आवेदन करने के लिए किसान भाइयों को किसी भी प्रकार से परेशान होने की जरूरत नहीं है। इस पूरी प्रक्रिया को ऑनलाइन कर दिया गया है। इसके लिए इच्छुक किसान भाई हरियाणा सरकार के सिंचाई और जल संसाधन विभाग की वेबसाइट HID.GOV.IN पर जाकर बेहद आसानी से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा किसान भाई अधिक जानकारी के लिए अपने जिले के कृषि विभाग में भी संपर्क कर सकते हैं और इस योजना का लाभ ले सकते हैं।

मध्य प्रदेश में

बरसात और ओलावृष्टि का कहर, 3800 गांवों में 1.5 लाख हेक्टेयर फसल हुई नष्ट

मध्य प्रदेश में बरसात और ओलावृष्टि का कहर, 3800 गांवों में 1.5 लाख हेक्टेयर फसल हुई नष्ट

मध्य प्रदेश में पिछले एक सप्ताह से तेज बारिश-आंधी और ओलावृष्टि का कहर जारी है। जिसके कारण अब तक लाखों हेक्टेयर फसल नष्ट हो चुकी है। प्रदेश के लगभग हर जिले में ओलावृष्टि हुई है। कई जगहों पर किसानों की फसलें पूरी तरह से चौपट हो गई हैं। किसानों का कहना है कि बिना मौसम वाली बरसात के कारण अभी तक गेहूं, चना और सरसों की फसलें सबसे ज्यादा प्रभावित हुई हैं। इसके साथ ही संतरा, लहसुन, धनिया, मसूर, इसबगोल, अलसी की फसलें भी बुरी तरह से बर्बाद हो गई है।

प्रदेश में फसलों की बर्बादी को देखते हुए मध्य प्रदेश सरकार ने सर्वे करने के आदेश दिए हैं। यह सर्वे दो फेज में करवाया जा रहा है। पहले फेज के सर्वे में जानकारी निकलकर सामने आई है कि 6 से 9 मार्च के बीच जो बरसात और ओलावृष्टि हुई थी उसमें प्रदेश के 16 जिले बुरी तरह से प्रभावित हुए थे। इन जिलों के 3280 गांव में 1.09 लाख किसानों की 1.25 लाख हेक्टेयर की फसल नष्ट हो चुकी है। दूसरे फेज का सर्वे 16 से लेकर 19 मार्च तक किया जा रहा है। सर्वे में अब तक कहा गया है कि इस दौरान 27 जिलों के किसान प्रभावित हुए हैं। जिसमें अभी तक 33884 किसानों की 38985 हेक्टयर फसल के खराब होने की जानकारी सामने आई है। यह आंकड़ा भविष्य में बढ़ सकता है क्योंकि दूसरे फेज का सर्वे अब भी जारी है।

सर्वे में बताया गया है कि जिन जिलों में खराब मौसम की वजह से नुकसान हुआ है वहां पर 50 से 85% तक फसलें तबाह हो चुकी हैं। अब तक प्रदेश में कुल 1.5 लाख हेक्टेयर की फसल तबाह हो चुकी है। जिसमें अब तक प्रदेश के 3500 से ज्यादा गांव सीधे तौर पर प्रभावित हुए हैं। अभी तक खराब मौसम का सबसे ज्यादा प्रभाव विदिशा जिले में देखने को मिला है। विदिशा में सर्वाधिक 49883 हेक्टेयर फसल तबाह हो चुकी है। इसके साथ ही सबसे ज्यादा विदिशा जिले के किसान प्रभावित हुए हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आदेश जारी करके 25 मार्च तक सभी प्रकार के सर्वे को पूरा करने के लिए कहा है।

फसलों की तबाही को देखेते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सर्वे में किसी भी प्रकार की लापरवाही न हो। उन्होंने इसके लिए अधिकारियों के साथ मीटिंग की है। उन्होंने कहा कि सर्वे में ईमानदारी होना जरूरी है, सर्वे में होने वाली किसी भी प्रकार की गलती को स्वीकार नहीं किया जाएगा। साथ ही उन्होंने आदेश दिया है कि रेवेन्यू, कृषि और पंचायत विकास के अमले को सर्वे में शामिल किया जाए। सर्वे के बाद प्रभावितों की लिस्ट को पंचायत भवन में चस्पा कर दी जाए ताकि सभी लोग अपना नाम लिस्ट में देख सकें। उन्होंने कहा कि यदि किसान सर्वे से असंतुष्ट नजर आते हैं तो उसका जल्द से जल्द निराकरण किया जाए। इसके साथ ही पशु हानि की भरपाई करने के लिए भी मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं।

फसल बर्बाद होने के सदमे में किसान की हुई मौत

प्रदेश के रायसेन जिले के पहरिया गांव में एक किसान की सदमें में मौत हो गई। बताया जा रहा है कि किसान ने अपनी 8 एकड़ जमीन पर चने की फसल लगाई थी। बिना मौसम तेज बरसात और ओले गिरने के कारण किसान टेंशन में आ गया था। जिससे सोते समय उसकी मौत हो गई। रायसेन जिले में 40 प्रतिशत से ज्यादा फसलें तबाह हो गई हैं। पिछले 24 घंटों में मंडला जिले में सबसे ज्यादा 1.57 नीच बरसात दर्ज की गई है। जिससे जिले की फसलें बुरी तरह से प्रभावित हुई हैं।

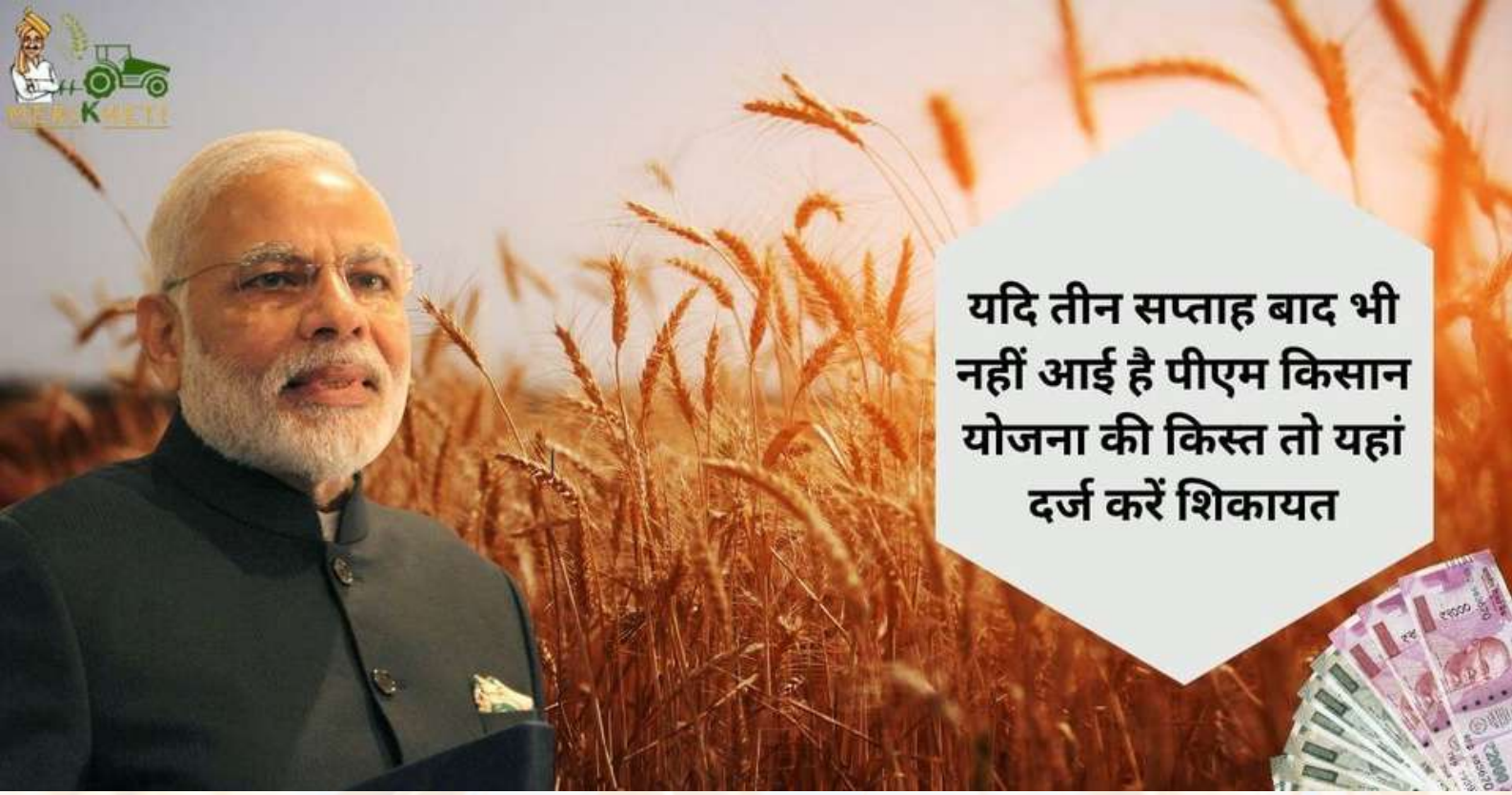

यदि तीन सप्ताह बाद भी नहीं आई है प्रधानमंत्री किसान योजना की किस्त तो यहां दर्ज करें शिकायत

देश के किसानों को सशक्त करने के लिए केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना लागू की है। जिसके अंतर्गत हर साल किसानों को 6 हजार रुपये की सहायता राशि प्रदान की जाती है। यह राशि तीन किस्तों में दी जाती है। अब तक केंद्र सरकार प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 13 किस्तें किसानों के बैंक खातो में ट्रांसफर कर चुकी है। आखिरी किस्त 27 फरवरी को ट्रांसफर की गई थी। जिसे पीएम मोदी ने डीबीटी के माध्यम से सभी किसान भाइयों के बैंक खातों में सीधे राशि पहुंचाई थी।

सरकार के सूत्रों ने बताया है कि इस दौरान 8,000 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खातों में 16,000 करोड़ से अधिक की राशि ट्रांसफर की गई थी। लेकिन अभी भी बहुत सारे किसान भाई ऐसे हैं जिन्हें 13वीं किस्त प्राप्त नहीं हुई है। यह सभी किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत सहायता राशि पाने के हकदार हैं, लेकिन कुछ तकनीकी खामियों के चलते तीन सप्ताह बीत जाने के बाद भी किसानों को किस्त नहीं मिल पाई है। जिन भी किसानों को अभी तक राशि नहीं मिली है वो पीएम किसान योजना के ऑनलाइन हेल्प डेस्क नंबर पर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं साथ ही इन अन्य विकल्पों से भी मदद प्राप्त कर सकते हैं।

पीएम किसान की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपनी गलतियां सुधारें किसान

ऐसे किसान जिनकी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 13वीं किस्त नहीं आई है वो योजना की आधिकारिक वेबसाइट PMKISAN.GOV.IN पर जाकर फॉर्म भरते समय की गई गलतियों को सुधार लें। कई बार ऐसा होता है कि किसान आवेदन करते समय गलत जानकारियां भर देते हैं जिससे किसानों के दस्तावेजों का मिलान करने में कठिनाई होती है, जिससे समय पर सही अपडेट नहीं मिल पाता।

कई बार आवेदन में गलत मोबाइल नंबर की वजह से किसानों को पता ही नहीं चलता कि उनके बैंक खाते में किस्त का पैसा जमा हो चुका है। किसानों को समय पर मैसेज नहीं मिल पाता जिसके कारण किसान यह समझते हैं कि उनका पैसा अभी तक बैंक खाते में जमा नहीं किया गया है। ऐसे में सभी वांछित जानकारियां आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपडेट कर दें। साथ ही वेबसाइट के माध्यम से किसान भाई अपने लाभार्थी स्टेटस की जानकारी भी बेहद आसानी से ले सकते हैं।

लिस्ट में नाम जरूर चेक करें

इस साल प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से 1.86 लाख किसानों के नाम हटाए गए हैं। क्योंकि कई फर्जी किसान इस योजना का गलत तरीके से लाभ ले रहे थे।

इसलिए लिस्ट में अपना नाम जरूर चेक करें ताकि यह पता लग पाए कि अन्य किसानों के साथ कहीं आपका नाम भी तो लिस्ट से नहीं कट गया। अपना नाम चेक करने के लिए पीएम किसान की ऑफिशियल वेबसाइट pmkisan.gov.in पर जाएं। वहां पर Farmers Corner के सेक्शन में जाएं। इसके बाद नीचे दिए गए Beneficiary Status के विकल्प पर क्लिक करें। इसके बाद आपसे अकाउंट नंबर, आधार नंबर और फोन नंबर मांगा जाएगा। इन सभी चीजों को उचित स्थान पर दर्ज करें। इसके बाद Get Data पर क्लिक करते ही लाभार्थी के स्टेटस की जानकारी मिल जाएगी।

यहां पर संपर्क करें किसान भाई

बहुत सारे कारण होते हैं जिनकी वजह से कई बार प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की किस्त किसानों के बैंक खाते में समय पर नहीं पहुंच पाती। इससे किसान भाइयों को किसी भी प्रकार की चिंता करने की जरूरत नहीं है। किसान भाई चाहें तो इस समस्या के निराकरण के लिए अपने जिले के कृषि विभाग के कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं। साथ ही अधिक जानकारी के लिए pmkisan-ict@gov.in पर अपनी समस्या लिखकर भेज सकते हैं। साथ ही हेल्पलाइन नंबर- 155261, 1800115526 या फिर 011-23381092 पर कॉल करके जानकारी हासिल कर सकते हैं।

महिला सशक्तिकरण हेतु हुनर से रोजगार समारोह को MERIKHETI की टीम ने किया कवर

महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए केंद्र सरकार और बहुत सारी संस्थाएं अपने अपने स्तर से भरपूर प्रयास कर रही हैं। इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदी बेन पटेल ने सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय में 19 मार्च दिन रविवार को हुनर से रोजगार समारोह को संबोधित किया है। इसके अंतर्गत महिलाओं ने वहां अपने-अपने हुनर का प्रदर्शन किया।

आपको बतादें कि मिल्लेट्स से बने उत्पादों को कार्यक्रम के दौरान महिलाओं द्वारा प्रस्तुत किया गया। साथ ही, उन्होंने सफल हुई महिलाओं की जीवन कहानी को भी बताया। वहां आई बहुत सी महिला किसानों ने खुद से बनाई गई बहुत से उपयोगी उत्पादों को समारोह के दौरान माननीय राज्यपाल जी को दिखाया और अपने हुनर व कला का प्रदर्शन भी किया था। महिला किसानों ने राज्यपाल जी के सामने अपनी प्रदर्शनी की है। MERIKHETI की टीम ने वहां पहुँचकर पुरे समारोह की प्रत्येक गतिविधि को कवर किया।

सरदार वल्लभभाई पटेल प्रौद्योगिकी एवं कृषि विश्वविद्यालय में हुआ समारोह

उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदी बेन पटेल जी ने मेरठ में उपस्थित सरदार वल्लभभाई पटेल प्रौघोगिकी एवं कृषि विश्वविद्यालय में महिलाओं के लिए हुनर से रोजगार कार्यक्रम का समारोह किया गया। इस पूर्वनियोजित महिला किसान सशक्तिकरण समारोह के दौरान कृषि विश्वविद्यालय के उच्च अधिकारी उपस्थित रहे। राज्यपाल आनंदी बेन ने कृषि विश्वविद्यालय की क्षात्राओं को भी संबोधित किया है।

मेरीखेती की टीम ने मेरठ में हुए हुनर से रोजगार समारोह को कवर किया

मेरीखेती की टीम ने समारोह में जाकर महिला किसानों के द्वारा की गई प्रदर्शनी को कवर किया। जिसमें अगरबत्ती निर्माता, मोमबत्ती निर्माता, मसालों की पैकिंग, मशरूम उत्पादक आदि महिलाओं की कलाकृतियां एवं उत्पादों को कवर किया है। साथ ही, महिलाओं ने मोटे अनाज को सरकार द्वारा प्रोत्साहन मिलने से प्रेरित होकर मोटे अनाजों से निर्मित उत्पादों को भी प्रदर्शनी में रखा था। महामहिम राज्यपाल आनंदी बेन पटेल ने इन सभी महिलाओं द्वारा की गई प्रदर्शनी को देखा और उनका उत्साहवर्धन भी किया।

महिला सशक्तिकरण हुनर से रोजगार समारोह में कई दिग्गज हस्तियां मौजूद रही

महिला सशक्तिकरण के लिए आयोजित किए गए इस समारोह में उत्तर प्रदेश की महामहिम राज्यपाल आनंदी बेन पटेल, उत्तर प्रदेश के राज्य कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही, पशुपालन दुग्ध व मत्स्य पालन राज्यमंत्री संजीव बाल्यान, सरदार वल्लभभाई पटेल प्रौद्योगिकी एवं कृषि विश्वविद्यालय के वाईस चांसलर केके सिंह, पूसा के कृषि वैज्ञानिक डॉ विपिन कुमार आदि कृषि क्षेत्र की दिग्गज हस्तियां उपस्थित रहीं। समारोह में मौजूद महानुभावों ने महिला सशक्तिकरण और उनके परिश्रम व रचनात्मक सोच के बारे में अपने विचार साझा किये।

अब नहीं रिसेगा पानी, प्लास्टिक फार्म पॉन्ड योजना से खेतों में बनेगा तालाब

किसानों की आमदनी को बढ़ाने के लिए राज्य सरकार पुरजोर कोशिश में है। जिसके चलते कई तरह की योजनाओं पर भी काम किया जा रहा है। जिसमें से एक है प्लास्टिक फार्म पॉन्ड योजना। इस योजना के अंतर्गत सरकार अनुदान भी दे रही है।

बारिश का पानी इकट्ठा करके खेती के लिए इस्तेमाल करने के हिसाब से राजस्थान सरकार ने एक नई योजना पेश की है। इस योजना का नाम प्लास्टिक फार्म पॉन्ड है। प्लास्टिक फार्म पॉन्ड योजना के तहत किसानों एक लाख से भी ज्यादा का अनुदान राजस्थान सरकार की ओर से दिया जा रहा है। आपको बता दें की पहली बार गंगापुर सिटी एरिया में रेतीली जमीन पर प्लास्टिक लाइन फार्म पॉन्ड को बनाया गया है। इस पॉन्ड में आने वाले दिनों में बारिश के पानी को इकट्ठा करने में मदद मिलेगी। साथ ही, पानी जमीन में नहीं रिस पाएगा। जिसके बाद किसान भाई बारिश के पानी को जल संरक्षण के तौर पर खेती या फिर मछली पालन में इस्तेमाल कर पाएंगे।

दो साल से थी बड़ी चुनौती

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गंगा सिटी का यह सबसे रेतीला इलाका है। जहां फार्म पॉन्ड बनाना कृषि अधिकारियों के लिए करीब दो साल से चुनौती से भरा हुआ था। इसके अलावा इस विभाग के अंतर्गत लगभग दो दर्जन गांव स्थित हैं। जिनकी जमीन रेतीली है। पानी की किल्लत के चलते यहां की फसलों की सिंचाई के लिए किसान को बारिश पर ही निर्भर रहना पड़ता है।

सरकार की स्कीम पर किसानों को नहीं था इंटरेस्ट

आपको बतादें कि किसानों की इस समस्या को देखते हुए प्रदेश की सरका ने रेतीली जमीन में खेती किसानी करने वाले किसानों के लिए दो साल पहले ही प्लास्टिक फार्म पॉन्ड की स्कीम दी थी। लेकिन इस तरफ किसानों का कोई खास इंटरेस्ट नहीं था, जिसे देखते हुए विभागीय अधिकारीयों ने भी अपने कदम पीछे ले लिए।

नये सहायक कृषि अधिकारी ने किया प्रेरित

प्रदेश के गंगा सिटी इलाके में नये सहायक कृषि अधिकारी ने इस समस्या को चुनौती की तरह लिया और किसानों को सरकार की इस योजना के प्रति प्रेरित किया। जिसके कुछ दिनों के बाद ही उनकी मेहनत रंग लाने लगी और सलेमपुर गांव में किसानों ने फार्म पॉन्ड बनवा दिया। जिसके लिए करीब 20 मीटर की लम्बाई और चौड़ाई के साथ तीन मीटर की गहराई की गयी।

किसान कैसे उठा सकते हैं लाभ?

अगर किसान प्लास्टिक फार्म पॉन्ड योजना का फायदा उठाना चाहते हैं, तो उनके पास करीब 0.3 हेक्टेयर की जमीन और खेत का नक्शा होने के साथ ट्रेस और जन आधार कार्ड बैंक अकाउंट डिटेल सहित मोबाइल नंबर अपडेट होना चाहिए। इसके साथ ही किसानों को विभाग की तरफ से करीब एक लाख या उससे ज्यादा का अनुदान भी दिया जाता है। अगर किसानों ने इसके लिए आवेदन नहीं किया है, तो वह फार्म पॉन्ड योजना का फायदा भी नहीं उठा पाएंगे।

क्या कहते हैं कृषि अधिकारी?

कृषि अधिकारी के मुताबिक प्लास्टिक फार्म पॉन्ड बनाने के लिए सितंबर से अक्टूबर महीने में किसानों से संपर्क करके उन्हें शार्टलिस्ट किया गया है। इसके लिए किसानों को लगातार प्लास्टिक फार्म पॉन्ड बनाने के लिए प्रेरित भी किया जा रहा है। राज्य सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने के लिए प्लास्टिक फार्म पॉन्ड में मछली पालन की परमिशन भी दे रखी है। इससे पहले प्लास्टिक फार्म पॉन्ड में किसान मछली पालन का काम नहीं कर सकते थे। अगर वो ऐसा करते भी थे तो, सख्त कारवाई भी की जाती थी। लेकिन किसानों की इनकम बढ़े इसके लिए राज्य सरकार नया प्रोविजन ला चुकी है।

Narendra Modi @narendramodi · 3h
India government official
भोजपुर का मिलेट महोत्सव श्री अन्न के प्रति लोगों की जागरूकता तो बढ़ाएगा ही, साथ ही इसे खानपान में भी शामिल करने के लिए प्रेरित करेगा।
pib.gov.in/PressReleasePa...

Pashupati Kumar Paras @PashupatiParas · Feb 28
मिलेट महोत्सव कार्यक्रम के अवसर पर लगाई गई प्रदर्शनी का दौरा किया व प्रदर्शित उत्पादों के बारे में विस्तृत जानकारी ली। #MilletMahotsav #PMFMEScheme #WorldFoodIndia2023 @PMOIndia @PIB_Patna @IYM2023 @PMFMEScheme

पीएम मोदी ने बिहार के भोजपुर में हुए मिलेट्स आयोजन को लेकर किया ट्वीट

बिहार राज्य के भोजपुर में दो दिवसीय मिलेट महोत्सव कार्यक्रम आयोजित हुआ। इसके संबंध में प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट के जरिए से बताया है, कि भोजपुर का मिलेट महोत्सव लोगों के अंदर श्री अन्न के लिए जागरूकता को बढ़ावा देगा। बिहार में दो दिवसीय बाजरा महोत्सव आयोजित किया गया था। इस महोत्सव का आयोजन बिहार राज्य के भोजपुर जनपद में 28 फरवरी से लेकर 1 मार्च 2023 तक किया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस महोत्सव के लिए आज ट्वीट कर दिया है।

केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री पशुपति कुमार पारस जी के एक ट्वीट के जवाब में प्रधानमंत्री ने ट्वीट करते हुए कहा है, कि भोजपुर का मिलेट महोत्सव लोगों में श्री अन्न के प्रति जागरूकता को बढ़ायेगा। इसके साथ ही यह देशवासियों में श्री अन्न को उनके खान-पान में शामिल करने हेतु प्रोत्साहित भी करेगा।

बिहार राज्य में मोटे अनाज की पैदावार अधिक होती है

आपको बतादें कि केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री पशुपति कुमार पारस जी ने इस मिलेट महोत्सव का उद्घाटन किया था। इसी बीच उन्होंने कहा है, कि बिहार राज्य रागी,ज्वार, बाजरा एवं छोटे बाजरा की पैदावार के लिए जाना जाता है। वर्ष 2021-22 के चलते, बिहार राज्य ने 5.92 मिलियन अमेरिकी डॉलर भाव के 21,187.60 मीट्रिक टन बाजरा को विदेश भेजा है एवं भोजपुर सोरघम व छोटे बाजरा के स्त्रोतों का केंद्र है।

भोजपुर में आयोजित हुए दो दिवसीय कार्यक्रम के अंतर्गत कई सारे बाजरा-आधारित उत्पादों की प्रदर्शनी एवं बिक्री, बाजरा प्रसंस्करण पर सूचनात्मक सत्र, उद्योग के जानकारों व सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों, एसएचजी, भोजन में लगे एफपीओ के मध्य इंटरैक्टिव सत्र की भाँति गतिविधियों की एक विस्तृत श्रृंखला शम्मिलित थी। इसमें प्रचंड प्रतिक्रिया देखी गई, जिसमें 1,000 से ज्यादा प्रतिभागियों ने हिस्सेदारी दर्ज की। जिसके अंतर्गत सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम, स्वयं सहायता समूह, किसान-उत्पादक संगठन, उत्पादक सहकारी समितियाँ आदि शामिल हैं।

भारत के इन राज्य और जनपदों में होगा मिलेट्स महोत्सव का आयोजन

केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री पशुपति कुमार पारस ने ट्वीट में लिखा है, कि इस साल भारत के 20 राज्यों व 30 जनपदों में मिलेट महोत्सव का आयोजन किया जाना है। बतादें, कि इसी क्रम में आगामी मिलेट महोत्सव का आयोजन आगरा, उत्तर प्रदेश में किया जा रहा है। इस दो दिवसीय मिलेट महोत्सव का आयोजन 3 व 4 मार्च को आगरा के आरबीएस कॉलेज ऑडिटोरियम में संपन्न किया जायेगा।

इस राज्य के किसानों को ग्रीन हाउस के लिए मिल रहा है, 70 फीसद तक अनुदान

बागवानी फसलों को मौसमिक प्रभाव से संरक्षित करने हेतु राष्ट्रीय बागवानी मिशन के अंतर्गत राजस्थान राज्य के कृषकों को ग्रीन हाउस के निर्माण के व्यय पर 50 से 70 फीसद तक अनुदान प्रदान किया जा रहा है। आधुनिक तकनीकों द्वारा फिलहाल कृषि को बहुत गुना सुगम कर दिया है। विगत समय में किसान खेतों में मौसमिक आधार पर बागवानी फसल यानी सब्जियां-फलों का उत्पादन किया करते थे। परंतु फिलहाल ग्रीन हाउस, लो टनल एवं पॉलीहाउस जैसे संरक्षित ढांचों में गैर-मौसमी सब्जियों का उत्पादन करके सामान्य से ज्यादा पैदावार ली जा सकती है।

यदि हम बात करें ग्रीनहाउस की तब इस संरक्षित ढांचे में उत्पादित की जा रही बागवानी फसलें जैसे सब्जियां-फल सर्दियों में पाले एवं गर्मियों में धूप के भयंकर ताप से सुरक्षित रहती है। इसकी सहायता से मौसमिक मार एवं कीट-रोग से उत्पन्न समस्याओं को काफी हद तक कम कर सकते हैं। यही कारण है, कि फिलहाल सरकार भी कृषकों को ग्रीन हाउस तकनीक को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित कर रही हैं। इसी क्रम में राजस्थान के किसान भाइयों के लिए भी ग्रीन हाउस निर्मित करने हेतु अनुदान प्रदान किया जा रहा है।

किसानों के लिए कितने फीसद अनुदान प्रदान किया जा रहा है

- राष्ट्रीय बागवानी मिशन के अंतर्गत राजस्थान के किसान भाइयों को ग्रीनहाउस के लिए किए जाने वाले निर्माण व्यय पर 50 से 70 फीसद तक अनुदान प्रदान किया जा रहा है।
- सामान्य वर्गीय कृषकों को ग्रीन हाउस के इकाई व्यय पर 50 फीसद अनुदान दिया जाएगा।
- लघु, सीमांत, एससी, एसटी वर्ग के किसान भाइयों को इकाई व्यय पर 20 फीसद ज्यादा मतलब 70% अनुदान प्रदान किया जाएगा।
- इस अनुदान योजना का फायदा उठाने के लिए किसान भाइयों को न्यूनतम 4000 वर्ग मीटर का ग्रीन हाउस निर्मित करना पड़ेगा।

जानें किन किसानों को मिल पाएगा लाभ
ग्रीन हाउस पर अनुदान योजना का फायदा प्रति पात्र किसान तक पहुंच पाए। इस वजह से योजना की पात्रता तय की गई है, जिसके अंतर्गत किसान के पास स्वयं की कृषि लायक भूमि का होना अति आवश्यक है। ध्यान रहे कि आवेदन करते वक्त कृषकों को स्वयं का मूल निवास प्रमाण पत्र भी लगाना होगा। किसान भाई खेत में सिंचाई संबंधित उत्तम व्यवस्था रखें। मृदा-जलवायु की जांच रिपोर्ट एवं एससी-एसटी की पहचानने हेतु जाति प्रमाण पत्र भी जोड़ना होगा।

अब बंजर जमीन से किसानों की होगी भारी कमाई, हर एकड़ में मिल सकते हैं एक लाख रुपये

देश की केंद्र सरकार किसानों की आय बढ़ाने का लगातार प्रयास कर रही है, जिसके लिए कई योजनाएं लागू की गई है जो किसानों को प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से लाभ प्रदान कर रही हैं। इसी तरह की एक योजना है प्रधानमंत्री कुसुम योजना। इस योजना के अंतर्गत सरकार किसानों को अपने खेत में सोलर पंप लगवाने के लिए भारी सब्सिडी दे रही है। इस योजना के अंतर्गत किसान भाई अपने खेत पर या बंजर जमीन पर सोलर पंप लगवा सकते है। जिसके लिए सरकार 60 फीसदी का अनुदान दे रही है। इस योजना को साल 2019 में शुरू किया गया था और अब इस योजना पर लगातार काम किया जा रहा है ताकि किसानों को इस योजना का लाभ पहुंचाया जा सके। इस योजना का मुख्य उद्देश्य प्रदूषण से मुक्त और बेहद कम दामों में किसानों को सिंचाई उपलब्ध करवाना है।

सरकार ने अपनी इस योजना के बारे में बताया है कि इस योजना के अंतर्गत किसानों को सोलर पैनल फ्री मिलते हैं, जिससे वो आसानी से बिजली बना सकते हैं। उस बिजली को अपनी अवश्यकतानुसार उपयोग कर सकते हैं तथा बाकी बची बिजली को बेंचकर अतिरिक्त आमदनी हासिल कर सकते हैं। बची हुई बिजली को विद्युत वितरण कंपनी खरीद लेती है, साथ ही अगले 25 सालों तक इनकम की गारंटी भी देती है।

लेकिन किसान को ध्यान रखना होगा कि सोलर प्लांट लगवाने के लिए किसान की जमीन विद्युत सब-स्टेशन से 5 किलोमीटर तक दायरे में होनी चाहिए। नवीनीकृत स्रोतों से बनाई जाने वाली बिजली प्रदूषण रहित होती है जिससे पर्यावरण को नुकसान नहीं होता। इसके साथ ही इसको बनाने में लागत भी कम आती है।

प्रति एकड़ एक लाख रुपये तक की हो सकती है कमाई

सरकार की कोशिश है कि किसान भाई इस योजना का लाभ उठाकर अपने खेतों में लगे डीजल पंपों को बंद कर दें और सौर ऊर्जा से चलित पंपों का इस्तेमाल करें। इससे एक ओर प्रदूषण में कमी आएगी वहीं दूसरी ओर डीजल की खपत भी कम होगी। जिससे केंद्र सरकार के ऊपर कच्चे तेल के आयात का बोझ कम होगा। इसके अलावा किसान भाईयों को बची हुई बिजली विद्युत वितरण कंपनी को बेंचने पर हर माह प्रति एकड़ 1 लाख रुपये तक का मुनाफा हो सकता है। यह आमदनी किसान को आगामी 25 वर्षों तक होती रहेगी।

इस प्रकार उठा सकते हैं सब्सिडी का फायदा

केंद्र सरकार ने कहा है कि इस योजना के अंतर्गत सोलर पैनल लगवाने पर किसान को कुल राशि का सिर्फ 10 प्रतिशत ही भुगतान करना होता है। इसके अलावा सरकार किसान को कुल राशि का 60 प्रतिशत देती है, जो सब्सिडी के रूप में होता है। इस राशि में से 30 प्रतिशत केंद्र सरकार की तरफ से तथा 30 प्रतिशत राशि राज्य सरकार की तरफ से वहन की जाती है। बाकी बची हुई 30 प्रतिशत राशि किसान को बैंक लोन के रूप में प्रदान की जाती है, जिसे किसानों को समय पर किस्तों के माध्यम से वापस करना होता है।

प्रधानमंत्री कुसुम योजना से किसान भाइयों को होंगे ये फायदे

- इस योजना के माध्यम से बिना एकमुश्त राशि दिए आसानी से किसान की भूमि में सोलर पैनल लगाए जाते हैं। जिन्हें बेकार पड़ी जमीन में भी लगवाया जा सकता है।
- इससे किसानों को फ्री बिजली मिलेगी जिससे सिंचाई में आसानी होगी। फ्री बिजली मिलने से किसानों का सिंचाई में होने वाला व्यय घटेगा।
- इस योजना से किसानों की डीजल पर से निर्भरता कम होगी।
- अतिरिक्त बिजली को आगामी 25 सालों तक बेंचकर किसान भाई अपने लिए अतिरिक्त आमदनी कर सकते हैं।
- इस योजना के माध्यम से पर्यावरण में प्रदूषण कम किया जा सकेगा।

इनको मिलेगा प्रधानमंत्री कुसुम योजना का लाभ

देश में प्रधानमंत्री कुसुम योजना का लाभ किसानों के साथ-साथ सहकारी समितियों को, पंचायतों को, किसानों के समूहों को, किसान उत्पादक संगठनों को और जल उपभोक्ता एसोसिएशनों को भी मिलेगा।

इस योजना का लाभ पाने के ये डाक्यूमेंट्स होंगे जरूरी

इस योजना का लाभ पाने के लिए लाभार्थी के पास आधार कार्ड, आवेदन करने वालों की पासपोर्ट साइज़ की फोटो, पहचान पत्र, राशन कार्ड, रजिस्ट्रेशन की कॉपी, बैंक खाते की डिटेल, जमीन के दस्तावेज और मोबाइल नंबर होना अनिवार्य है। ये सभी डाक्यूमेंट्स आवेदन करते समय लगाने अनिवार्य हैं।

प्रधानमंत्री कुसुम योजना का लाभ पाने के लिए इस प्रकार से करें आवेदन

आवेदनकर्ता प्रधानमंत्री कुसुम योजना का लाभ पाने के लिए योजना की आधिकारिक वेबसाइट MNRE.GOV.IN पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त योजना की विस्तृत जानकारी प्राप्त करने के लिए अपने नोडल ऑफिसर से सम्पर्क कर सकते हैं।

रेशम की खेती

कर लातूर का यह किसान कमाता है सालाना 10 लाख रुपए

रेशम की खेती कर लातूर का यह किसान कमाता है सालाना 10 लाख रुपए

अब वह समय नहीं रहा जबकि किसान सिर्फ पारंपरिक फसलें उगा कर ही अपनी जीविका चलाते थे. आज कल खेती में भी अलग-अलग तरह के प्रयोग हो रहे हैं और साथ ही किसान अलग-अलग किस्म की फसलें उगा कर अच्छा खासा मुनाफा कमा रहे हैं.

रेशम का कीट पालन सेरीकल्चर के नाम से भी जाना जाता है. लोगों के बीच में रेशम बहुत ज्यादा चलन में हैं और इसे वस्त्रों की रानी के नाम से भी जाना जाता है. कई सालों से रेशम हमारी सभ्यता और संस्कृति का हिस्सा रहा हैऔर आज भारत चीन के बाद विश्व में दूसरा सबसे बड़ा रेशम उत्पादक देश बन चुका है.

हाल ही में लातूर से आई एक जानकारी से पता चला है कि वहां पर एक किसान रेशम की खेती करते हुए सालाना 10 लाख रुपए कमा रहा है. सिद्धेश्वर भगवान नाम के लातूर के एक किसान ने अपनी डेढ़ एकड़ जमीन पर यह खेती करना शुरू किया और अब वह सालाना लाखों कमा रहे हैं. इसके लिए रेशम के कीट को पालना पड़ता है.

हर 3 महीने में क्रॉप किया जाता है रेशम

सिद्धेश्वर भगवान ने आगे बताया कि उन्होंने डेढ़ एकड़ जमीन पर यह खेती शुरू की थी और रेशम को हर 3 महीने में क्रॉप करना पड़ता है. उन्होंने बताया कि लगभग हर 3 महीने में उन्हें ढाई से ₹3 लाख की आमदनी हो जाती है. इस फसल पर आने वाली लागत लगभग ₹25000 पड़ती है. इस तरह साल खत्म होते-होते लागत आदि निकाल कर रहे सालाना ₹10 लाख कमा लेता है.

रेशम की खेती के लिए शहतूत का पेड़ है बहुत जरूरी

सिद्धेश्वर भगवान ने अपने डेढ़ एकड़ जमीन में शहतूत के बहुत से पेड़ लगाए हैं और उन्होंने जानकारी दी कि शहतूत के पत्ते खाकर ही रेशम के कीट रेशम उत्पन्न करते हैं. जिस जाली में रेशम के कीट पालन गए हैं वहां पर शहतूत की पत्तियों बिखेर दी जाती हैं और यह रेशम कीट का पसंदीदा खाना. इन्हें खाकर वह अन्य भोजन के मुकाबले ज्यादा रेशम का उत्पादन करते हैं.

किसान समाचार

बाजार में मिलावटखोर लाल मिर्च में कर रहे मिलावट ऐसे करें मिलावटयुक्त मिर्च की जाँच

सरकार देश के किसानों की आय को बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। इसके लिए सरकार समय-समय पर किसानों के लिए नई योजनाएं लॉन्च करती रहती है, जिनसे बड़ी संख्या में किसान लाभान्वित हो रहे हैं।

इसी कड़ी में मध्य प्रदेश की सरकार ने एक कदम आगे बढ़ाते हुए प्रदेश के जनजातीय किसानों को पशुपालन से जोड़ने का बेड़ा उठाया है। सरकार का मानना है कि इस पहल से प्रदेश में बेरोजगारी कम होगी और जनजातीय युवाओं को रोजगार भी मिल सकेगा। प्रदेश सरकार की नई स्कीम के तहत बैगा, भारिया और सहरिया समाज के लोगों को पशुपालन से जोड़ा जाएगा। इसके लिए सरकार गाय या भैंस मुफ़्त में देगी। सरकारी अधिकारियों ने बताया है कि इस स्कीम के तहत 1500 गायें-भैंसें किसानों को दी जाएंगी। जिनका 90 प्रतिशत खर्च सरकार वहन करेगी।

सरकारी अधिकारियों ने बताया है कि प्रदेश सरकार ने साल 2022 से लेकर साल 2024 तक 1500 दुधारू पशु वितरित करने का लक्ष्य रखा है।

इसके लिए 29 करोड़ 18 लाख रुपये राशि को भी स्वीकृत कर दिया गया है। इसमें से प्रत्येक गाय को खरीदने के लिए एक लाख 89 हजार 250 रुपये की राशि निर्धारित की गई है, जबकि भैंस खरीदने के लिए 2 लाख 43 हजार रुपये की राशि निर्धारित की गई है। गाय क्रय करने में 70 हजार 325 रुपये सरकार की तरफ से दिए जाएंगे जबकि शेष 18 हजार 925 रुपये खुद किसान को देने होंगे। इसी तरह भैंस की खरीदी में 2 लाख 18 हजार 700 रुपये सरकार की तरफ से दिए जाएंगे जबकि बकाया 24 हजार 300 रुपये की राशि को हितग्राही को खुद वहन करना होगा।

एमपी स्टेट कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन के अधिकारियों ने बताया है कि सरकार इस फैसले से राज्य में दूध उत्पादन को बढ़ाना चाह रही रही है। कुछ महीनों पहले ही एमपी स्टेट कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने एक एमओयू साइन किया था जिसके मुताबिक अब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया प्रदेश में दुधारू पशुओं को खरीदने के लिए 10 लाख रुपये तक का लोन बिना किसी गारंटी के प्रदान करेगा। इसके लिए हर जिले में बैंक की 3 से 4 शखाओं का चयन किया गया है जो किसानों को लोन उपलब्ध करवाएंगी। इस राशि से किसान 2 से लेकर 8 दुधारू पशु तक खरीद सकते हैं। सरकार का मानना है कि इस पहल से राज्य में दुग्ध उत्पादन में बढ़ावा होगा, साथ ही किसानों की भी आय तेजी से बढ़ेगी।

बिहार के वैज्ञानिकों ने विकसित की आलू की नई किस्म

बिहार के वैज्ञानिकों ने विकसित की आलू की नई किस्म

बिहार के लखीसराय में कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों ने आलू की एक नई किस्म विकसित की है। आलू की इस किस्म को "पिंक पोटैटो" नाम दिया गया है। वैज्ञानिकों का कहना है कि आलू की इस किस्म में अन्य किस्मों की अपेक्षा रोग प्रतिरोधक क्षमता ज्यादा है। साथ ही आलू की इस किस्म में बरसात के साथ शीतलहर का भी कोई खास असर नहीं पड़ेगा। फिलहाल इसकी खेती शुरू कर दी गई है। वैज्ञानिकों को इस किस्म में अन्य किस्मों से ज्यादा उपज मिलने की उम्मीद है।

आलू की खेती के लिए ऐसे करें खेत का चयन

ऐसी जमीन जहां पानी का जमाव न होता हो, वहां आलू की खेती आसानी से की जा सकती है। इसके लिए दोमट मिट्टी सबसे ज्यादा उपयुक्त मानी जाती है। साथ ही ऐसी मिट्टी जिसका पीएच मान 5.5 से 5.7 के बीच हो, उसमें भी आलू की खेती बेहद आसानी से की जा सकती है।

खेती की तैयारी

आलू लगाने के लिए सबसे पहले खेत की तीन से चार बार अच्छे से जुताई कर दें, उसके बाद खेत में पाटा अवश्य चलाएं ताकि खेत की मिट्टी भुरभुरी बनी रहे। इससे आलू के कंदों का विकास तेजी से होता है।

आलू कि बुवाई का समय

आलू मुख्यतः साल में दो बार उगाया जाता है। पहली बार इसकी बुवाई जुलाई माह में की जाती है, इसके बाद आलू को अक्टूबर माह में भी बोया जा सकता है।

आलू की बुवाई कतार में करनी चाहिए। इस दौरान कतार से कतार की दूरी 60 सेंटीमीटर होनी चाहिए जबकि पौधे से पौधे की दूरी 20 सेंटीमीटर होनी चाहिए।

आलू की फसल में सिंचाई

आलू की खेती में सिंचाई की जरूरत ज्यादा नहीं होती। ऐसे में पहली सिंचाई फसल लगने के 15 से 20 दिनों के बाद करनी चाहिए। इसके बाद 20 दिनों के अंतराल में थोड़ी-थोड़ी सिंचाई करते रहें। सिंचाई करते वक्त ध्यान रखें कि फसल पानी में डूबे नहीं।

आलू की खुदाई

आलू की फसल 90 से लेकर 110 दिनों के भीतर तैयार हो जाती है। फसल की खुदाई के 15 दिन पहले सिंचाई पूरी तरह से बंद कर देनी चाहिए। खुदाई से 10 दिन पहले ही आलू की पतियों को काट दें। ऐसा करने से आलू की त्वचा मजबूत हो जाती है। खुदाई करने के बाद आलू को कम से कम 3 दिन तक किसी छायादार जगह पर खुले में रखें। इससे आलू में लगी मिट्टी स्वतः हट जाएगी।

भूजल स्तर में गिरावट को देखते हुए इस राज्य में 1000 रिचार्जिंग बोरवेल का निर्माण किया जाएगा

भूजल स्तर में गिरावट को देखते हुए इस राज्य में 1000 रिचार्जिंग बोरवेल का निर्माण किया जाएगा

भारत के विभिन्न राज्यों से भूजल स्तर में गिरावट आने की खबर सामने आ रही है। फलस्वरूप फसल की पैदावार पर इसका दुष्प्रभाव पड़ रहा है। इस समस्या का निराकरण करने के लिए हरियाणा सरकार द्वारा प्रथम चरण में 1000 रीचार्जिंग बोरवेल की स्थापना करने का लक्ष्य निर्धारित किया है।

कृषि क्षेत्र में जल के प्रभावी उपयोग को प्रोत्साहित किया जा रहा है। जिसके तहत विभिन्न राज्यों में ड्रॉप मोर क्रॉप योजना जारी की जा रही है। आपकी जानकारी के लिए बतादें कि न्यूनतम जल में सिंचाई करके नकदी एवं बागवानी फसलों से काफी अधिक पैदावार मिल रही है। भारत के बहुत सारे क्षेत्रों में भूमिगत जल संकट भी एक बड़ी चुनौती थी। हालाँकि, फिलहाल सूक्ष्म सिंचाई मॉडल द्वारा इन समस्त समस्याओं को दूर कर दिया है। यह सिंचाई पद्धति को उपयोग में लाना किसान भाइयों के लिए और भी सस्ता हो गया है। केंद्र सरकार के माध्यम से प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के चलते सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली स्थापित कराने के लिए किसान भाइयों को सब्सिडी का प्रावधान दिया गया है।

हरियाणा सरकार द्वारा दिया जा रहा है अनुदान

इसी कड़ी में अब हरियाणा सरकार ने भी ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई पद्धति को बढ़ावा देने और रिचार्जिंग बोरवेल मुहैय्या कराने हेतु किसान भाइयों को सब्सिड़ी दी जा रही है। इस संबंध में सरकार का यह कहना है, कि हमारे इस प्रयास से जल संरक्षण एवं इसका संचयन करने में विशेष सहायता मदद प्राप्त होगी। साथ ही, यह घटते भूमिगत जल स्तर के संकट को भी दूर करने में सहायता करेगा।

किसानों को सूक्ष्म सिंचाई हेतु 85% अनुदान का प्रावधान

कृषि क्षेत्र में सिंचाई हेतु सर्वाधिक निर्भरता भूमिगत जल पर ही रहती है। जल की उपलब्धता को निरंतर स्थिर बनाए रखने के लिए जल की अधिक खपत वाली फसलों को हतोत्साहित किया जा रहा है। इसकी अपेक्षा बागवानी फसलों की कृषि को बढ़ावा दिया जा रहा है। साथ ही, सूक्ष्म सिंचाई मॉडल को प्रचलन में लाने के लिए किसानों को रीचार्जिंग बोरवेल पर सब्सिड़ी दी जा रही है। हिसार में आयोजित कृषि विकास मेले में हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने कहा है, कि वर्तमान हालात को ध्यान में रखते हुए हमें जल की खपत को कम करने की आवश्यकता है। इसके लिए ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई को उपयोग में लाना होगा। क्योंकि यह किसानों के लिए सस्ता और सुविधाजनक होता है। साथ ही, राज्य सरकार सूक्ष्म सिंचाई को उपयोग में लाने के लिए किसान भाइयों को 85% अनुदान भी प्रदान कर रही है।

1,000 रीचार्जिंग बोरवेल लगाने का लक्ष्य तय किया गया है

भारत में फिलहाल भूजल स्तर में आ रही गिरावट को पुनः ठीक करने के लिए वर्षा जल संचयन को भी प्रोत्साहन मिल रहा है। इसी संबंध में राज्य सरकार रीचार्जिंग बोरवेल के निर्माण की योजना बना रही हैं, जिसके माध्यम से वर्षा के जल को पुनः भूमि के अंदर पहुंचाया जा सके। इस कार्य हेतु किसान भाइयों को 25,000 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। इसके अतिरिक्त जो भी खर्चा होगा उसको हरियाणा सरकार द्वारा वहन किया जाएगा।

इस तरह किसान आवेदन कर सकते हैं

हरियाणा सरकार द्वारा रीचार्जिंग बोरवेल पर आवेदन की प्रक्रिया को ऑनलाइन माध्यम से भी कर दिया गया है। अगर आप भी हरियाणा राज्य के किसान हैं और स्वयं के खेत में जल संचयन हेतु बोरवेल स्थापित कराना चाहते हैं, तब आप सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, हरियाणा की वेबसाइट HID.GOV.IN पर जाकर आवेदन किया जा सकता है। इसके बारे में विस्तृत रूप से जानकारी प्राप्त करने के लिए स्वयं के जनपद के कृषि विभाग के कार्यालय में भी संपर्क कर फायदा उठा सकते हैं।

किसान क्रेडिट कार्ड शिविर का आयोजन, सैकड़ों किसानों ने कराया आवेदन

रायगढ़ जिले के सभी जनपद पंचायत में किसान क्रेडिट कार्ड बनाने के शिविर का आयोजन किया गया. क्रेडिट कार्ड बनवाने के लिए सैंकड़ों किसानों की भीड़ उमड़ी साथ ही कई आवेदन भी जमा किये.

शिविर में अधिकारीयों और कर्मचारियों ने किसानों से आवेदन फार्म जमा करवाए. बता दें लगभग 143 किसानों ने शिविर के पहले दिन किसान क्रेडिट कार्ड के लिए आवेदन जमा किया. गौ पालन के लगभग 37, मछली पालन के लगभग 37, उद्यानिकी के 48 और कृषि के 21 आवेदन फार्म भरे गये. 31 मार्च तक हर सोमवार, बुधवार, शुक्रवार को इस शिविर का आयोजन किया जाएगा. इतना ही नहीं कुछ दिन पहले क्लेकात्र ने शिविर के माध्यम से केसीसी बनाने की आदेश दिए थे.

- किसानों को मिल सकेगा सस्ता ऋण

हालांकि खेती बाड़ी के लिए हर कसिान को ऋण की जरूरत होती है. जिसे देखते हुए राज्य शासन ने किसान क्रेडिट कार्ड धारक किसानों को सहकारी बैंकों से काफी सस्ते में ऋण दिलाया जाएगा. आपको बता दें कि अभी तक केसीसी बनाने का काम किया जा रहा है. जिसके लिए शिविर भी लगाये जा रहे हैं. यहं से किसान क्रेडिट कार्ड आसानी से बनवाया जा सकता है.

- शिविर को बताया जा रहा अच्छी पहल

शिविर के जरिये किसान क्रेडिट कार्ड बनाने के लिए लगातार आवेदन लिया जा रहे हैं. किसान क्रेडिट कार्ड के जरिये किसानों के लिए गाय, मछली, सब्जी से जुड़े कामों के लिए जीरो फीसद ब्याज दर पर ऋण दिया जाता है. ज्यादातर मामलों में पैसों की कमी की वजह से फसल, बीज या फिर खाद की खरीद में मुश्किल हो जाती है. अगर किसी किसान को इस योजना के तहत फायदा मिलता है, तो मिली हुई रकम से वह बीज या खाद खरीद सकेंगे. इतना ही नहीं अलग अलग कामों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड जारी किया जा रहा हैम जिसमें खेती से भी ज्यादा फायदा उद्यानिकी फसलों को मिलेगा.

इन बातों का रखना होगा ख्याल

- जो भी किसान किसान क्रेडिट कार्ड बनवाना चाहते हैं, तो पस्ट साइज़ फोटो साथ में रखनी होगी.
- इसके आलवा आधार कार्ड और बी 1 की कॉपी भी किसानों को साथ में लानी होगी.
- अगर हितग्राही किसी सहकारी समिति का सदस्य नहीं है तो लगभग 110 रुपये का शुक्ल किसानों को देना होगा.

कलेक्टर सिन्हा के आदेश पर कार्यालय में शिविर का आयोजन किया जा रहा है. इतना ही नहीं शिविर में किसानों को उपस्थित रखकर ही किसान क्रेडिट कार्ड बनवाना होगा. कलेक्टर के मुताबिक इस योजना के तहत किसान बेहद कम ब्याज दरों में किसानी से जुड़े कामों के लिए बैंकों से ऋण ले सकते हैं. साथ ही किसानों को अपनी खेती और किसानों के लिए जरूरी कामों के लिए अच्छी खासी रकम मिल सकती है.

आ गया पीएम किसान की 14वीं किस्त पर बड़ा अपडेट, इस महीने आएंगे अकाउंट में पैसे

किसानों के लिए केंद्र सरकार पीएम किसान सम्मान निधि योजना चला रही है. सीमांत किसानों की आर्थिक मदद करने के लिए इसे योजना की शुरुआत की गयी है. इस योजना के अंतर्गत किसानों के खातों में अब तक 13 किस्ते जा चुकी हैं. जिसके बाद अब 14वीं किस्त को लेक्ट भी बड़ा अपडेट आ चुका है.

27 फरवरी को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत 13वीं किस्त को जारी किया था. जिसके लिए केंद्र सरकार की ओर से कुल 16 हजार करोड़ रूपये की राशि खर्च की गयी. बताया जा रहा है कि, केंद्र सरकार की इस योजना का फायदा देश के करीब 8 करोड़ से भी ज्यादा किसानों को मिला है. जिसके बाद अब किसान अगली यानि की 14वीं किस्त को लेकर काफी उत्साहित हैं. उनके मन में अब सिर्फ एक ही सवाल है, कि 14वीं किस केंद्र सरकार कब और कौन से महीने में जारी करेगी.

- **नहीं करना होगा ज्यादा इंतज़ार**

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पीएम किसान सम्मान निधि योजना से जुड़ी 14वीं किस्त के लिए किसान भाइयों को अब ज्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा. अगर किसान इसका फायदा उठाना चाहते हैं, तो अपने बैंक से जुड़े सारे प्रोसेस को पहले पूरा कर लें. काफी किसानों ने अब तक अपना केवाईसी भी अपडेट नहीं किया है, और अकाउंट नंबर को आधार से भी लिंक नहीं करवाया है.

ऐसे में किसानों को पहले इन सब कामों को पूरा करना जरूरी होगा. वरना जो किसान 13वीं किस्त से वंचित रह गये हैं, वो 14वीं किस्त से भी वंचित रह जाएंगे.

- **केंद्रीय योजना है पीएम किसान सम्मान निधि**

केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही पीएम किसान सम्मान निधि योजना सीमांत किसानों की आर्थिक मदद के लिए है. जिसमें सरकार हर साल किसानों को 6 हजार रुपये की राशि देती है. इस राशि को दो-दो हजार रुपये की तीन समान किस्तों में किसनों के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है. इस योजना की सबसे ख़ास बात यह ही कि, इसके लिए किसानों को भाग दौड़ नहीं करनी पड़ती. इस योजना के लिए केंद्र सरकार अब तक ढ़ाई लाख करोड़ रूपये से भी ज्यादा की राशि खर्च कर चुकी है.

- **अप्रैल से जुलाई के बीच जारी हो सकती है 14वीं किस्त**

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अप्रैल से जुलाई के बीच केंद्र सरकार पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 14वीं किस को जारी कर सकती है. आपको बता दें ऑफिसियल तौर पर इस मामले में अभी तक कोई ऐलान नहीं किया गया है.
ऐसे कई किसान हैं, जिनके बैंक अकाउंट में अब तक 13वीं किस्त नहीं पहुंच पायी है. ऐसे में किसान हेल्पडेस्क पर भी अपनी शिकायत कर सकते हैं. इसके अलावा 011-24300606 और 155261 पर फोन करने किसान अपनी शिकायत को दर्ज कर सकते हैं. वहीं सरकार ने किसानों की मदद के लिए टोल फ्री नंबर भी जारी किये हैं. जो 18001155266 है. इसके साथ ही किसान भाई अपनी समस्या बताने के लिए PMKISAN-FUNDS@GOV.IN पर विजिट कर सकते हैं.

75 फीसद सब्सिडी के साथ मिल रहा ड्रिप स्प्रिंकलर सिस्टम, किसानों को करना होगा बस ये काम

अगर आप भी चावल में मिलावट कर उसे बेच रहे हैं तो सावधान हो जाइए

गर्मियों के मौसम में किसानों को सिंचाई में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है. ऐसे में राजस्थान सरकार ने किसानों की इस समस्या का हल खोज निकाला है.

राजस्थान के किसानों को गर्मियों के मौसम में सिंचाई से जुड़ी कोई समस्या ना उठानी पड़े, इसके लिए सरकार ने सूक्ष्म सिंचाई योजना का शुभारम्भ किया है. इस योजना के तहत रजस्थान राज्य के किसानों को ड्रिप और स्प्रिंकलर सेट पर 75 फीसद तक की सब्सिडी देने का फैसला किया है.

भारत के ऐसे कई क्षेत्र हैं, जहां का तापमान धीरे धीरे बढ़ रहा है. गर्मियों की आहट के बीच किसानों के दिमाग में सिंचाई को लेकर चिंता भी पनपने लगी है. क्योंकि गर्मियों के मौसम में किसानों को सिंचाई के लिए काफी संघर्ष करना पड़ता है. हालांकि कई इलाकों के भूजल स्तर काफी गिर चुका है, जिसके वजह से सिंचाई नहीं हो पाती और फलस्वरूप फसलें भी सूख जाती हैं. जिसे देखते हुए कई राज्य सरकारों ने चिन्तन करना भी शुरू कर दिया है, और सूक्ष्म सिंचाई को बढ़ावा देने के लिए तरह तरह के कार्यक्रमों की भी शुरुआत कर दी है.

• राजस्थान सरकार ने चलाई स्कीम

राजस्था सरकार ने किसानों की परेशानी को देखते हुए एक खास स्कीम चलाई है. जिसमें किसानों को ड्रिप और स्प्रिंकलर सेट की क्रीड पर 75 फीसद तक की भारी सब्सिडी देने का ऐलान कर दिया है.

• लाखों किसानों को होगा फायदा

राजस्थान सरकार की इस स्कीम के तहत राज्य के हर तबके के किसानों को फायदा मिलेगा. इतना ही नहीं सरकार ने अपने नये साल के कृषि बजट मरीं लगभग 4 लाख किसानों को ड्रिप और स्प्रिंकलर पर भारी अनुदान देने का फैसला किया है. इतना ही नहीं लाखों किसानों को सूक्ष्म सिंचाई मिशन के जरिये लाभान्वित कराया जाएगा. इस स्कीम का लाभ लेने के लिए आवेदान करने वाले एससी एसटी, लघु सीमांत और महिला किसानों को 75 फीसद अनुदान मिलेगा वहीं अन्य वर्ग के किसानों को लगभग 70 फीसद तक की सब्सिडी दी जाएगी.

इन शर्तों का रखना होगा ख्याल

- इस योजना का लाभ राजस्थान के किसान ही ले सकते हैं.
- सूक्ष्म सिंचाई योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक किसान राजस्थान का स्थाई निवासी होना जरूरी है.
- किसान के बॉस 0.2 हेक्टेयर और 5 हेक्टेयर खेती के लायक जमीन होनी जरूरी है.
- अगर किसान के खेत में कुएं, नलकूप, बीजली, डीजल, सोलर पंप जैसे जल स्रोत लगे होने पर ही सूक्ष्म सिंचाई संयंत्र स्थापित किये जाएंगे.

जानिए कैसे करेंगे आवेदन?

- अगर किसान सूक्ष्म सिंचाई योजना के तहत इसका लाभ लेना चाहता है,न तो सबसे पहले राज किसान साथी पोर्टल पर विजिट करके ऑनलाइन आवेदन करना होगा.
- किसानों को अपनी पर्सनल डिटेल के साथ साथ बैंक की पासबुक की कॉपी और जमीन की जमाबंदी की कॉपी भी अपलोड करनी होगी.
- आदार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, बिजली कनेक्शन प्रमाण पत्र, आधार से लिंक हुआ मोबाइल नंबर आदि भी उपलोड करना होगा.

इस मामले में पहले पायदान पर है राजस्थान

राजस्थान को रेतीली, बंजर और अनुपजाऊ जमीन से पहचाना जाता था. लेकिन समय के साथ साथ स्थितियों में काफी सुधार किया गया, और यहां की बंजर जमीन से भी लोग खूब पैसा कमा रहे हैं. वहीं सोलर सिंचाई पंप ने भी राज्य के कृषि क्षेत्र को नये पंख लगा दिए. सोलर पंप की स्थापना में राजस्थान पहले पायदान पर है. वहीं सूक्ष्म सिंचाई योजना के तहत जल संरक्षण का काम भी बेहद आसान हो चुका है. रिपोर्ट्स के मुताबिक राजस्थान पूरे देश भर में मात्र के ऐसा राज्य है, जहां सबसे ज्यादा सिंचाई यंत्र स्थापित किये गये हैं.

राजस्थान में भले ही पानी का स्तर काफी नीचे क्यों ना हो, लेकिन नई सिंचाई तकनीक की वजह से पानी की बचत के साथ फसल की अच्छी उत्पादकता को बढ़ाने की कोशिशें की जा रही हैं.

नीति आयोग का मास्टर प्लान, गौशालाओं की होगी मदद, आवारा पशुओं से मिलेगा छुटकारा

देश में गौशालाओं को बनाने के लिए लोगों को हर तरह से जागरूक किया जा रहा है. बढ़ती जागरूकता को देखते हुए, नीति आयोग ने गौशालाओं की मदद के लिए मास्टर प्लान बना लिया है. बताया जा रहा है कि, इसका सीधा फायदा हमारे किसान भाइयों के साथ साथ खेती बाड़ी को भी होगा. जिससे स्वभाविक रूप से आवारा पशुओं से लोगों को छुटकारा मिल सकेगा. साथ ही उनसे होने वाली दिक्कतें भी कादी हद तक दूर हो जाएंगी.

जब से देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार बनी है, तभी से पूरे देश में गौशालाओं की स्थापना को लेकर काफी जागरूकता बढ़ गयी है. ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक आवारा पशुओं के साथ साथ आवारा गायों में भी लोगों को खूब परेशान कर दिया है. जहां एक तरफ इनकी वजह से खेत खलियानों में दिक्कते बढ़ रही हैं, वहीं दूसरी तरफ चाहे गांव हो या शहर, हर जगह गौशालाओं का भी निर्माण किया जा रहा है. जिसे देखते हुए नीति आयोग ने एक ओस मास्टर प्लान तैयार किया है, जिससे वो एक तीर से एक नहीं बल्कि दो-दो निशाने लगाएगी. इस मास्टर प्लान के तहत देशभर में बनी गौशालाओं की स्थिति और सूरत तो सुधरेगी ही, साथ ही वो न्य बिजनेस भी कर आसानी से पाएंगी.

- **गौशालाओं को वित्तीय मदद देने की सिफारिश**

नीति आयोग के सदस्य पड़ पर कार्यरत रमेश चंद की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गयी. जिसमें गौशालाओं को वित्तीय मदद देने की सिफारिश की गयी है. इसके अलावा उन्हें नये बिजनेस का भी आइडिया दिया गया है. जिसके तहत गाय का गोबर और गोमूत्र से बनी चीजों की मार्केटिंग कर सकें. हालांकि इन सभी चीजों का इस्तेमाल कृषि सेक्टर में खूब किया जाता है.

- **ऑनलाइन होगा गौशालाओं का रजिस्ट्रेशन**

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक समिति का एक और प्रस्ताव भी है. जिसमें सभी गौशालाओं के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की बात कही गयी. इसके लिए एक पोर्टल भी बनाया जाना चहिये. इस पोर्टल को नीति आयोग के दर्पण पोर्टल की तरह बनाने का सुझाव दिया गया है. जो पशु कल्याण बोर्ड सहायता हासिल करने के लायक बनाया जाएगा.

- **आवारा पशु नहीं बनेंगे परेशानी का सबब**

इतना ही नहीं समिति ने अपनी एक रिपोर्ट पेश की है. जिसके मुताबिक गौशालाओं को आर्थिक मदद देने की बात कही गयी है. जिससे लोगों को आवारा पशुओं की वजह से होने वाली परेशानियों का समाधान मिल सकेगा. समिति का कहना है कि, गौशालाओं को जो भी मदद दी जाएगी, उसको गायों की कुल संख्या से जोड़ना चाहिए. इसके अलावा आवारा और बिमारी से बचाई गयी गायों की स्थिति में सुधार किया जा सके.

- **रियायती ब्याज पर मिल सकता है फाइनेंस**

समिति के मुताबिक गौशालाएं आर्थिक रूप से सक्षम बनें. इसके लिए उन्हें वित्तीय मदद मिलनी चाहिए. जिससे उन्हें अपना बिजनेस चलाने और क्यादा मुनाफा कमाने में मिलने वाले अंतर के बराबर आर्थिक मदद को विअबले गैप फंडिंग के रूप में दिया जाना चाहिए.

इसके साथ ही गौशालाएं जो भी पूंजी निवेश करें, उसके लिए और वर्किंग कैपिटल के लिए रियायती ड्रोन पर फाइनेंस किया जाना चाहिए.

ये बिजनेस कर सकती हैं गौशालाएं

- गौशालाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए, उनकी पूंजीगत तरीके से मदद की जानी चाहिए.
- पूंजीगत तरीके से हुई मदद से गौशालाएं गोबर और गोमूत्र से बने उत्पादकों की मार्केटिंग आसानी से कर सकेंगी.
- गोबर और गोमूत्र से बने उत्पादकों का इस्तेमाल जैविक कृषि को आगे बढ़ाने में काफी हद तक कारगार हो सकता है.
- नीति आयोग के मास्टर प्लान से गौशालाओं को गोबर और गोमूत्र से बनी चीजों के प्रोडक्शन और पैकेजिंग के साथ साथ मार्केटिंग और वितरण करने में मदद मिल सकती है.
- अगर प्राइवेट सेक्टर मरीं निवेश किया जाएगा तो, जैविक उर्वरक का ज्यादा और भारी पैमाने पर उत्पादन हो सकेगा.

प्रोडक्शन एंड प्रमोशन ऑफ ऑर्गेनिक एंड बायो फर्टिलाइजर्स विथ स्पेशल फोकस ऑन इंप्रूविंग इकोनॉमिक वायबिलिटी ऑफ गौशाला की रिपोर्ट में समिति की ओर से ये सभी सुझाव दिए गये हैं.

प्रोडक्शन एंड प्रमोशन ऑफ ऑर्गेनिक एंड बायो फर्टिलाइजर्स विथ स्पेशल फोकस ऑन इंप्रूविंग इकोनॉमिक वायबिलिटी ऑफ गौशाला की रिपोर्ट में समिति की ओर से ये सभी सुझाव दिए गये हैं.

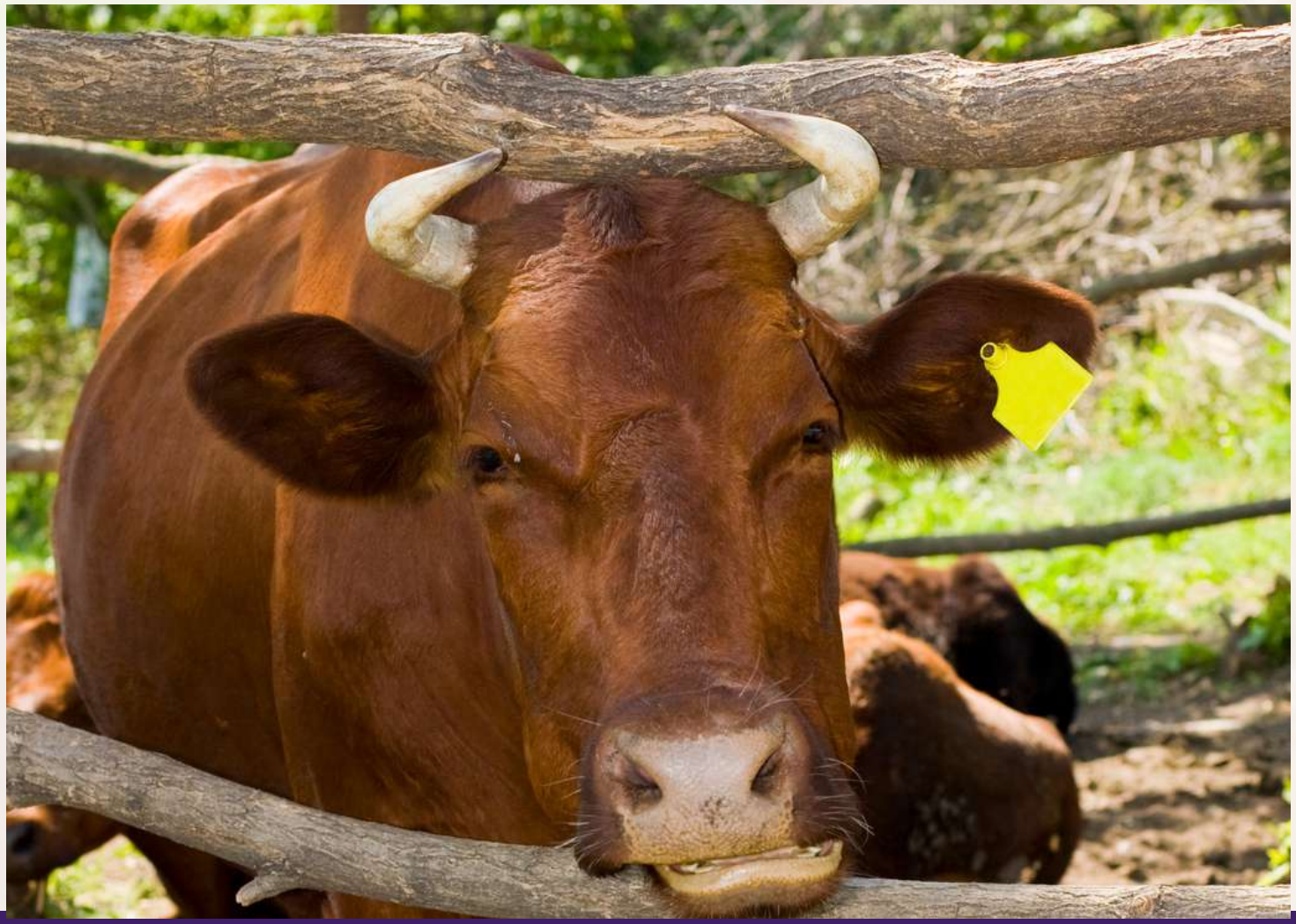

द्रौपदी मुर्मू के द्वारा स्वीकृत किए गए इस विधेयक से 11 हजार काश्तकारों को मिलेगा लाभ

राज्य सरकार के अनुसार, यह अधिनियम कृषि सुधार से जुड़ा कदम है। इससे कृषि क्षेत्र में निवेश को काफी प्रोत्साहन मिलेगा एवं पैदावार भी बढ़ेगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा पंजाब के एक विधेयक को स्वीकृति प्रदान करदी गई है। मंजूरी मिलते ही यह विधेयक फिलहाल कानून में परिवर्तित हो गया है। इस कानून के चलते प्रदेश के 4,000 एकड़ से ज्यादा भूमि पर कब्जा रखने वाले 11,200 से भी अधिक काश्तकारों को मालिकाना हक मिल पाएगा। एक अधिकारी का कहना है, कि सरकार को आशा है, कि यह कानून भूमि जोतने वालों को मजबूत करेगा। साथ ही, जो लोग समाज में आर्थिक एवं सामाजिक तौर से लाचार, उन्हें भी सशक्त बनाएगा।

जानकारी के अनुसार, यह काश्तकार बहुत सालों से जमीन के छोटे-छोटे हिस्सों पर काबिज हैं।साथ ही, पीढ़ी-दर-पीढ़ी उत्तराधिकारी के तौर पर स्वयं का अधिकार प्राप्त करते हैं। चूंकि, वह पंजीकृत स्वामी नहीं थे, इसलिए ना तो वह वित्तीय संस्थानों से ऋण प्राप्त कर सकते थे। साथ ही, किसी प्राकृतिक आपदा की स्थिति में उन्हें सहायता मिलती थी। लेकिन अब उन्हें अन्य भूस्वामियों की तरह सभी लाभ मिलेंगे।

कृषि क्षेत्र में निवेश और उत्पादकता में वृद्धि होगी

इस विधेयक से समुचित सहायक धनराशि का भुगतान करने के उपरांत 4,000 एकड़ से ज्यादा जमीन पर कब्जा रखने वाले 11,200 से ज्यादा काश्तकारों को संपत्ति के अधिकार की अनुमति देता है। साथ ही, एक आधिकारिक बयान में बताया गया है, कि यह अधिनियम कृषि सुधार से संबंधित कदम है। वहीं, इससे कृषि क्षेत्र में निवेश को प्रोत्साहन मिलेगा एवं पैदावार भी बढ़ेगी।

इन समुदायों को मिलेगा अधिकार

इस विधेयक को स्वीकृति मिलते ही पंजाब में मुकर्रीदार, मुंधिमार, पनाही कदीम, सौंजीदार, तारादादकर, भोंदेदार, बुटेमार, डोहलीदार, इंसार मिआदी समुदायों को संपत्ति का हक मिल गया है। इन समुदायों के व्यक्ति बहुत सालों से 4 हजार एकड़ भूमि के रकबे पर काबिज थे। वहीं, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा स्वीकृति मिलते ही इन समुदाय के लोगों के मध्य खुशियों की लहर चल रही है। इन लोगों द्वारा सरकार और राष्ट्रपति का शुक्रिया अदा किया है। दरअसल, इस विधेयक, वर्ष 2020 में पंजाब विधानसभा में उस समय पारित किया गया था जब राज्य में अमरिंदर सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार थी।

नवीन कृषि नीति जारी की जाएगी

बतादें कि पंजाब सरकार किसानों की प्रगति के लिए नवीन कृषि नीति पर भी कार्य चल रहा है। विगत माह पंजाब के कृषि मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल ने बताया था कि नवीन कृषि नीति तैयार करने हेतु कृषि विशेषज्ञों की 11 सदस्यीय समितियों का गठन कर दिया गया है। यह समिति 31 मार्च तक नवीन कृषि नीति निर्मित कर लेगी। विगत सरकार द्वारा भी इस पर कवायद की थी, परंतु नीति को कभी अधिसूचित नहीं किया था।

हरियाणा में 39 वें राज्य स्तरीय पशु मेले का आयोजन किया जा रहा है

हरियाणा में आयोजित होने वाले 39 वें पशु मेले में 50 लाख तक की ईनामी धनराशि रखी गई है। इस मेले में पशुओं की प्रर्दशनी समेत उनके रैंप वॉक का भी आयोजन किया गया है।

आज किसान भाई पशुपालन में भी प्रयाश कर रहे हैं। दूध एवं इससे निर्मित उत्पादों की माँग वृद्धि के मध्य फिलहाल किसान भी पशुपालन की तरफ रुख कर रहे हैं। इससे कृषि सहित अतिरिक्त आय की भी व्यवस्था हो जाती है। पशुपालन क्षेत्र के प्रगति-विस्तार हेतु केंद्र एवं राज्य सरकारें एकजुट होकर लगातार कोशिश कर रही हैं। जहां केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय पशुधन मिशन योजना जारी की गई है। साथ ही, राज्य सरकारें भी स्वयं के स्तर से पशुपालन को प्रोत्साहन देने के लिए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित करती रहती हैं।

हरियाणा में आयोजित किया जा रहा पशु मेला

हरियाणा पशुपालन विभाग चरखी दादरी में 11 से 13 मार्च तक 39वीं राज्य स्तरीय पशु मेले का आयोजन किया जा रहा है। जहां घोड़े एवं ऊंटों के शानदार करतबों का कार्यक्रम आयोजित भी होगा। इस पशु मेले के अंतर्गत 50 से भी ज्यादा पशु प्रतियोगिताएं भी आयोजित की जाएंगी। मेले में जीतने वाले पशुपालकों को 50 लाख रुपये के पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे।

पशुपालकों को 50 लाख रुपये का ईनाम

मीडिया खबरों के मुताबिक, हरियाणा के चरखी दादरी में आयोजित 39वां राज्य स्तरीय पशु मेले में खागड़, मेंढ़े, ऊंट, सूअर, गधों, गाय, भैंस, बैल, बकरी, भेड़, की उन्नत नस्लों की प्रदर्शनियां की जाएंगी। इसके अतिरिक्त, विश्वभर में प्रसिद्ध हरियाणा की पशु प्रजातियां मुर्रा एवं साहीवाल के साथ-साथ विदेशी नस्ल के मवेशियों के मध्य 50 से ज्यादा प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएँगी। इन प्रतियोगिताओं में जीतने वाले पशु पालकों को 50 लाख रुपये का पुरस्कार देने का नियोजन है। इन प्रतियोगिताओं में दूजा एवं तीजा स्थान पाने वाले पशुपालकों को भी निर्धारित मानकों के अनुसार से पुरस्कृत किया जाएगा।

उत्तर प्रदेश में स्टांप ड्यूटी को लेकर लिया जा रहा है सराहनीय फैसला

अगर आप उत्तर प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो यह खबर आपके लिए ही है. हाल ही में उत्तर प्रदेश में राजस्व विभाग ने सरकार को एक प्रस्ताव दिया है जिसमें खेती से जुड़ी हुई जमीन पर स्टांप ड्यूटी को पूरी तरह से खत्म करने की बात कही गई है. आगे चलकर आप चाहे तो इस जमीन पर घर बना सकते हैं या फिर से किसी बिजनेस के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं. किसी भी तरह से इस्तेमाल करने पर इसमें 1% लगने वाली स्टांप ड्यूटी नहीं ली जाएगी.

विभाग द्वारा दिए गए इस प्रस्ताव को अगर कैबिनेट से मंजूरी मिल जाती है तो यह उत्तर प्रदेश में निवेश करने वाले निवेशकों के लिए एक बहुत ही बड़ी खुशी की बात होगी. कहने को स्टांप ड्यूटी केवल 1% होती है लेकिन जब इन्वेस्टर बड़ी बड़ी जमीन खरीदते हैं तो यह ड्यूटी लाखों रुपए की होती है.

अभी क्या है निवेशक और स्टांप ड्यूटी को लेकर नियम

उत्तर प्रदेश में सरकार अभी से ही निवेशकों को यहां पर अलग-अलग यूनिट लगाने के लिए जमीन उपलब्ध करवाने की कोशिश में लगी हुई है. यहां पर कोई भी अगर औद्योगिक यूनिट बनाना चाहता है तो उन्हें कृषि भूमि को व्यवसायिक इस्तेमाल में तब्दील करवाना जरूरी है.

अभी राज्य की राजस्व संहिता की धारा 80 के अनुसार कोई भी अगर जमीन में इन्वेस्ट करता है तो उन्हें राजस्व विभाग को एक रजिस्ट्रेशन फीस देनी पड़ती है जैसे स्टांप ड्यूटी कहा जाता है. यह जमीन की कीमत का 1% तक होता है. इसके कारण कई बार लोग इन्वेस्ट करने से पीछे हट जाते हैं और इसी शुल्क को खत्म करने के लिए हाल ही में सरकार द्वारा कैबिनेट को प्रस्ताव भेजा गया है.

आंकड़ों की मानें तो नवंबर 2021 से फरवरी 2022 के बीच में उत्तर प्रदेश में रेरा के तहत लगभग 116 प्रोजेक्ट पंजीकृत किए गए हैं. माना जा रहा है कि NCR के साथ-साथ लोग नॉन NCR शहरों में भी निवेश कर रहे हैं और आजकल यह बिल्डर्स का रुझान अपनी ओर खींच रही है.

नोएडा और ग्रेटर नोएडा में जमीन से जुड़े हुए कुछ कारोबारियों से बात करते हुए पता चला है कि पिछले 3 से 4 साल में यहां पर जमीन काफी महंगी हो गई है और वह इससे ज्यादा मुनाफा भी नहीं कमा पा रहे हैं. इसके अलावा आजकल 2 BHK FLATS भी काफी चलन में है क्योंकि लोग अपने बजट के हिसाब से में निवेश कर सकते हैं.ऐसे में अगर स्टांप ड्यूटी खत्म हो जाए तो राहत जरूर मिलेगी.

क्या है स्टाम्प ड्यूटी

जब भी हम घर खरीदते हैं तो हमें उससे जुड़ी हुई कई तरह की वित्तीय कार्यवाही करनी पड़ती है. जैसे कि हो सकता है आपने अपने घर पर लोन लिया हो तो आपको लोन का आवेदन देने की जरूरत पड़ती है. साथ ही आपको घर के लिए डाउन पेमेंट आदि भी करना अनिवार्य है.

यह सब खत्म हो जाने के बाद जब अंत में जाकर घर का पंजीकरण आपके नाम पर होता है तो नगरपालिका रिकॉर्ड में घर को अपने नाम पर रजिस्टर करवाने के लिए आपको स्टांप ड्यूटी देने की जरूरत पड़ती है.सरल शब्दों में बताया जाए तो यह सरकार को दिया जाने वाला एक कर है जिसके बाद आपको अपनी संपत्ति का स्वामित्व मिल जाता है.
स्टांप ड्यूटी अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग हो सकती है और यह एक ऐसा भुगतान होता है जिसे आपको एक बार में ही देना होता है नहीं तो आप पर जुर्माना लगाया जा सकता है. यह है सरकार की तरफ से दिया जाने वाला एक कानूनी कागज है जिसे अदालत में सबूत के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है. यह आपकी संपत्ति की खरीद और बिक्री की पूर्ण जानकारी का एक कानूनी दस्तावेज माना गया है.

दूसरे राज्यों में भी दिए गए हैं ऐसे ही बस में

हाल ही में पश्चिम बंगाल सरकार ने स्टांप ड्यूटी और सर्कल रेट पर दी गई छूट को अगले 6 महीने के लिए बढ़ा दिया है. इसे करने का सबसे बड़ा कारण है कि वहां पर रियल एस्टेट बाजार में एक उछाल आ सके.

इससे होने वाले फायदे को समझिए

यहां पर राज्य सरकार का सबसे बड़ा मकसद था कि कोरोना वायरस स्टेट को झटका ना लगे. सरकार द्वारा लिए गए फैसले से रियल एस्टेट जगत को बहुत फायदा भी मिला है और यहां पर छोटे फ्लैट में इन्वेस्ट करने वाले लोगों की संख्या काफी ज्यादा बढ़ गई है.

उत्तर प्रदेश में भी अगर यह फैसला लिया जाता है तो यहां पर भी जमीन में लोगों का इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगा. इसके अलावा बिल्डर भी बड़ी बड़ी योजनाओं के लिए जमीन खरीदना पसंद करेंगे. राज्य सरकार को जमीन बिक्री से अतिरिक्त राजस्व मिलने की संभावना भी कहीं ना कहीं बढ़ जाएगी.

केंद्र द्वारा किसान भाइयों को दिया जायेगा 50 फीसद कम मूल्य पर DAP

कृषि में उपयोग होने वाला डीएपी (DAP) अब आधे मूल्य में उपलब्ध किए जाने से किसानों का खर्च अतिशीघ्र कम हो जाएगा। केंद्र सरकार इस दिशा में दीर्घ काल से कार्य कर रही थी एवं फिलहाल उसने इफ्को से विकसित किया गया नैनो डीएपी (NANO DAP) जारी कर दिया है।

जैसा कि हम सब जानते हैं, अच्छी पैदावार लेने के लिए किसानों को कृषि कार्यों में डीएपी (DAP) उर्वरक पर काफी मोटा धन खर्च करना पड़ता है। हालाँकि, भारत सरकार इस पर अच्छा खासा अनुदान प्रदान करती है। फिलहाल, मोदी सरकार दीर्घ काल से उस तरह की खाद तैयार करने पर जोर दे रही है। जो कि कृषकों एवं सरकार दोनों के खर्च को कम कर दिया है। फिलहाल, कृषि मंत्रालय द्वारा नैनो डीएपी को जारी कर दिया है। इसका भाव डीएपी (DAP) बोरी के वर्तमान भाव के तुलनात्मक आधे से भी कम है।

लिक्विड नैनो डीएपी (NANO DAP) को सहकारी क्षेत्र की खाद कंपनी इफ्को (IFFCO) द्वारा तैयार किया गया है। इफ्को के मैनेजिंग डायरेक्टर यू. एस. अवस्थी एवं केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्री मनसुख मंडाविया ने इस संबंध में ट्विटर पर जानकारी प्रदान की है। अवस्थी द्वारा जहां इसे मृदा एवं पर्यावरण सुरक्षा की दिशा में महत्वपूर्ण पहल बताया गया है, वहीं मंत्री मनसुख मंडाविया द्वारा इसको आत्मनिर्भर भारत निर्माण हेतु एक बड़ी उपलब्धि माना गया है।

आधा लीटर बोतल कितने मूल्य पर उपलब्ध हो जाएगी

आपको बतादें कि इफ्को द्वारा तैयार इस नैनो डीएपी (NANO DAP) का मूल्य 600 रुपये होगा। इस मूल्य पर किसान भाइयों को 500 मिली मतलब आधा लीटर लिक्विड डीएपी मिलेगा। यह डीएपी की एक बोरी के समरूप कार्य करेगी।

भारत में यूरिया के उपरांत डीएपी का उपयोग दूजी सर्वाधिक उपयोग होने वाला उर्वरक है। इसके पूर्व इफ्को द्वारा नैनो यूरिया (NANO UREA) भी तैयार किया है। बिना अनुदान के इस बोतल का भाव 240 रुपये है।

डीएपी खाद की एक बोरी का भाव फिलहाल 1,350 से 1,400 रुपये है। इस प्रकार किसानों का डीएपी (DAP) पर होने वाला व्यय आधे से भी कम आएगा। भारत में वार्षिक डीएपी (DAP) का अनुमानित उपयोग 1 से 1.25 करोड़ टन है। वहीं घरेलू स्तर पर केवल 40 से 50 लाख टन डीएपी (DAP) का ही उत्पादन किया जाता है। अतिरिक्त का आयात करना होता है।

नैनो डीएपी द्वारा केंद्र सरकार के डीएपी अनुदान पर आने वाली लागत में भी काफी गिरावट आएगी। साथ ही, आयात में कमी आने से भारत के विदेशी मुद्रा भंडार के संरक्षण में भी काफी सहायता मिलेगी।

इन उर्वरकों के नेंनो वर्जन आने की तैयारी

इफ्को नैनो यूरिया (NANO UREA) एवं नैनो डीएपी (NANO DAP) के जारी करने के उपरांत फिलहाल नैनो पोटाश, नैनो जिंक एवं नैनो कॉपर उर्वरक पर भी कार्य कर रहा है। आपको बतादें कि भारत डीएपी के अतिरिक्त बड़े स्तर पर पोटाश का भी आयात करता है।

इन 8 योजनाओं से बढ़ेगी किसानों की स्किल, सरकार दे रही है मौका

इन 8 योजनाओं से बढ़ेगी किसानों की स्किल, सरकार दे रही है मौका

सरकार की तरफ से किसानों के हित में कई काम किया जा रहे हैं. ताकि किसानों को फायदा मिल सके. इसी तर्ज पर सरकार अब किसानों को उनकी स्किल डेवलपमेंट (SKILL DEVELOPMENT) के कई मौके दे रही है. जिसके लिए सरकार 8 योजनाएं भी लायी है. इससे किसानों की आमदनी भी बढ़ेगी.

भारत के कृषि उत्पादन की बात करें, तो यह 310 मिलियन टन से भी ज्यादा का है. वहीं बागवानी उत्पादन भी 330 मिलियन टन से ज्यादा होने लगा है. ऐसा माना जा रहा है कि, यह अब तक के 50 सालों में सबसे बड़ी उपलब्धी है. जिसे लगातार आगर बढ़ाते रहने के साथ साथ किसानों की आमदनी बढाने के लिए स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम बेहद जरूरी है. कृषि क्षेत्र में सरकार की स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स (DEVELOPMENT PROGRAM) के बारे में हर किसान को जानकारी होनी चाहिए.

देश के कई राज्यों में अनगिनत किसान हैं, जिनमें युवा और बुजुर्ग दोनों ही किसान शामिल है. उन्होंने पिछले कुछ सालों में कई सरकारी स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स (SKILL DEVELOPMENT PROGRAM) में हिस्सा भी लिया और अपनी उपज और आमदनी दोनों बढ़ाई है.

भारत में सबसे महत्वपूर्ण कृषि क्षेत्र है. जहां करीब 50 फीसद आबादी काम के लिए खेती पर ही निर्भर है. ऐसे में मदद के लिए सरकार ने भी किसानों और उनकी उपज में सुधार लाने का जिम्मा उठाया है. ऐसे में किसान भाइयों के सामने भी चुनौतियां कम नहीं हैं. संसाधनों में कमी के साथ साथ पुराणी घिसी पीटी तकनीक और मौसम में बदलाव उनकी परेशानियों को बढ़ाने के लिए काफी हैं. इन्हीं कारणों की वजह से उन्हें आधुनिक खेती से जुड़ी तकनीकों के बारे में बताने के लिए इस तरह के प्रोग्राम्स की शुरुआत की गयी है. जिनक मुख्य लक्ष्य किसानों को खेती में नई तकनीक के इस्तेमाल और उनके विकास में मदद करना है.

हालांकि आधुनिक तकनीकों को अपनाने के लिए किसानों को खास तरह की मदद देना और उनकी आमदनी बढ़ाने में मदद करना का लक्ष्य भी इस प्रोग्राम के जरिये भारत सरकार ने रखा है.

यहां जानिए सरकार की 8 बड़े योजनाएं

प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना

साल 2015 में इस कार्यक्रम की शुरुआत कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने की थी. इस कार्यक्रम का लक्ष्य कई क्षेत्रों से करीब एक करोड़ लोगों को प्रशिक्षित करने का है. इस योजना से सम्बंधित जैविक खेती, डेयरी फार्मिंग और फूड प्रोसेसिंग (FOOD PROCESSING) से जुड़ी जानकारी दी जाती है. इसके अलावा ग्रामीण युवाओं को बिजनेस के लिए जरूरी स्किल सिखाकर रोजगार को बढ़ाना है.

दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना

इस योजना की शुरुआत साल 2014 में ग्रामीण विकास मंत्रालय ने की थी. इस प्रोग्राम का लक्ष्य ग्रामीण युवाओं के साथ साथ गरीब परिवारों को रोजगार के अवसर देने हैं. इसके अलावा खेती से सम्बंधित स्किल से जुड़े बागवानी और कृषि वानिकी और पशुपालन में ट्रेनिंग देने पर है.

कौशल भारत कार्यक्रम

साल 2015 में भारत सरकार ने इस कार्यक्रम की शुरुआत की थी. इसका लक्ष्य 2022 तक 40 करोड़ लोगों को स्किल की ट्रेनिंग देनी थी. इस कार्यक्रम के तहत खेती सही कई क्षेत्रों में ट्रेनिगं दी जाती है. इस प्रोग्राम का उद्देश्य प्रोडक्शन और आदमनी के स्तर में सुधार के लिए वर्कफोर्स तैयार करना होता है.

भारतीय कृषि कौशल परिषद

खेती के सेक्टर में सरकार ने एक नई पहल की शुरुआत की है. जिसमें वर्कफोर्स के स्किल्स में सुधार करना है. सरकार की यह योजना एक गैर-लाभकारी संगठन है. जिसे साल 2013 में खेती में कई तरह की नौकरी के लिए भूमिकाओं के लिए लायक मानकों को विकसित करने के लिए स्थापित किया गया था. इसके तहत किसानों को खेती के मामले में उनकी स्किल और नॉलेज में सुधार किया जाएगा साथ ही सर्टिफिकेट कोर्स भी करवाया जाएगा.

स्टार्ट अप विलेज एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम

साल 2015 में शुरू हुए इस प्रोग्राम का लक्ष्य उद्यमियों को खेती समेत कई क्षेत्रों में अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए मदद करना है और पैसे भी देना है. इस कार्यक्रम के तहत अपने व्यवसायों को बढ़ाने और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ाने हैं.

नेशनल सेंटर फॉर मैनेजमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन -हैदराबाद

सरकार द्वारा शुरू की गयी यह बेहद जरूरी पहल है, जिससे कृषि और किसानों के कौशल में सुधार हो सके. इस योजना को कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के तहत साल 1987 में स्थापित किया गया था. इस योजना के अंतर्गत किसानों के कौशल और ज्ञान को बढ़ाने के लिए प्रोग्राम्स किये जाते हैं.

परम्परागत कृषि योजना

साल 2015 में कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने इस कार्यक्रम की शुरुआत की थी. इसका उद्देश्य जैविक खेती करने के तरीकों के लिए किसानों की उचित मदद और आर्थिक मदद करना है. जिससे देश में जैविक खेती को बढ़ावा मिल सके.

राष्ट्रीय कृषि विकास योजना

साल 2007 में भारत सरकार ने राष्ट्रीय कृषि विकास योजना की शरुआत की थी. इस योजना के अंतर्गत कृषि विकास में तेजी लाने के साथ साथ किसानों की इनकम बढ़ाना है. साथ ही अन्य राज्यों और केंद्र शाशित प्रदेशों को मदद करना है. इसके अलाव सरकार की इस योजना का उद्देश्य कृषि के अलावा सम्बद्ध क्षेत्रों में सार्वजिनक निवेश को बढ़ाना है.

इन बातों को समझना सबसे ज्यादा जरूरी

- किसान भाई चाहें तो अपनी फसलों के साथ साथ कृषि उत्पादों का डाइवर्सिफिकेशन कर अपनी इनकम बढ़ा सकते हैं.
- नई खेती की तकनीकों को इन प्रोग्राम्स के माध्यम से सीखकर कई बड़ी गलतियों से बचा जा सकता है.
- आजकल का समय बदल रहा है, ऐसे में इस बदलते हुए समय में आपको हर सरकारी योजनाएं और सरकारी कि तरफ से मुहैया कराई जा रही सब्सिडी के बारे में जानकारी ले सकते हैं.
- आप चाहें तो एग्रीकल्चर और हार्टीकल्चर की बढ़ती डिमांड को देखते हुए प्रोडक्ट प्लानिंग कर सकते हैं.

जानें किस वजह से धनिए के भाव में हुई 36 रुपए की बढ़ोत्तरी, फिलहाल क्या हैं मंडी भाव

जानें किस वजह से धनिया के भाव में हुई 36 रुपए की बढ़ोत्तरी, फिलहाल क्या हैं मंडी भाव

जानकारों ने बताया है, कि फिलहाल बाजार में मजबूती के रुख और उत्पादक क्षेत्रों से सीमित आपूर्ति की वजह से विशेष रूप से धनिया वायदा भावों में वृद्धि हुई है ।

वर्तमान बाजार में मजबूती के रुख के चलते हुए सटोरियों ने अपने सौदों का आकार बढ़ाने से वायदा कारोबार में सोमवार को धनिया की कीमत 36 रुपये की वृद्धि के साथ 6,942 रुपये प्रति क्विंटल तक पहुंचा दिया है । एनसीडीईएक्स में धनिया के अप्रैल माह में आपूर्ति वाले अनुबंध का मूल्य 36 रुपये या 0.52 फीसद की वृद्धि के साथ 6,942 रुपये प्रति क्विंटल पहुंच गया है । इसमें 11,095 लॉट के लिए कारोबार हुआ है । बाजार जानकारों ने बताया है, कि हाजिर बाजार में मजबूती के रुख तथा उत्पादक क्षेत्रों से सीमित आपूर्ति की वजह मुख्यत: धनिया वायदा कीमतों में वृद्धि हुई है ।

साथ ही, इंदौर में मौजूद स्थानीय खाद्य तेल बाजार में सोमवार को पाम तेल की कीमत में पांच रुपये प्रति 10 किलोग्राम की गिरावट शनिवार की तुलना में हुई है। आज सरसों 100 रुपये प्रति क्विंटल सस्ती बेची गई है ।

तिलहन की मंडी में कितनी कीमत है

- सरसों (निमाड़ी) 5800 से 5900 रुपये प्रति क्विंटल ।
- सोयाबीन 4800 से 5400 रुपये प्रति क्विंटल ।

तेल

- मूंगफली तेल 1690 से 1700 रुपये प्रति 10 किलोग्राम ।
- सोयाबीन रिफाइंड तेल 1105 से 1110 रुपये प्रति 10 किलोग्राम ।
- सोयाबीन साल्वेंट 1075 से 1080 रुपये प्रति 10 किलोग्राम ।
- पाम तेल 1025 से 1030 रुपये प्रति 10 किलोग्राम ।

कपास्या खली

- कपास्या खली इंदौर 1800 60 किलोग्राम बोरी ।
- कपास्या खली देवास 1800 60 किलोग्राम बोरी ।
- कपास्या खली खंडवा 1775 60 किलोग्राम बोरी ।
- कपास्या खली बुरहानपुर 1775 रुपये प्रति 60 किलोग्राम बोरी ।
- कपास्या खली अकोला 2700 रुपये प्रति क्विंटल ।

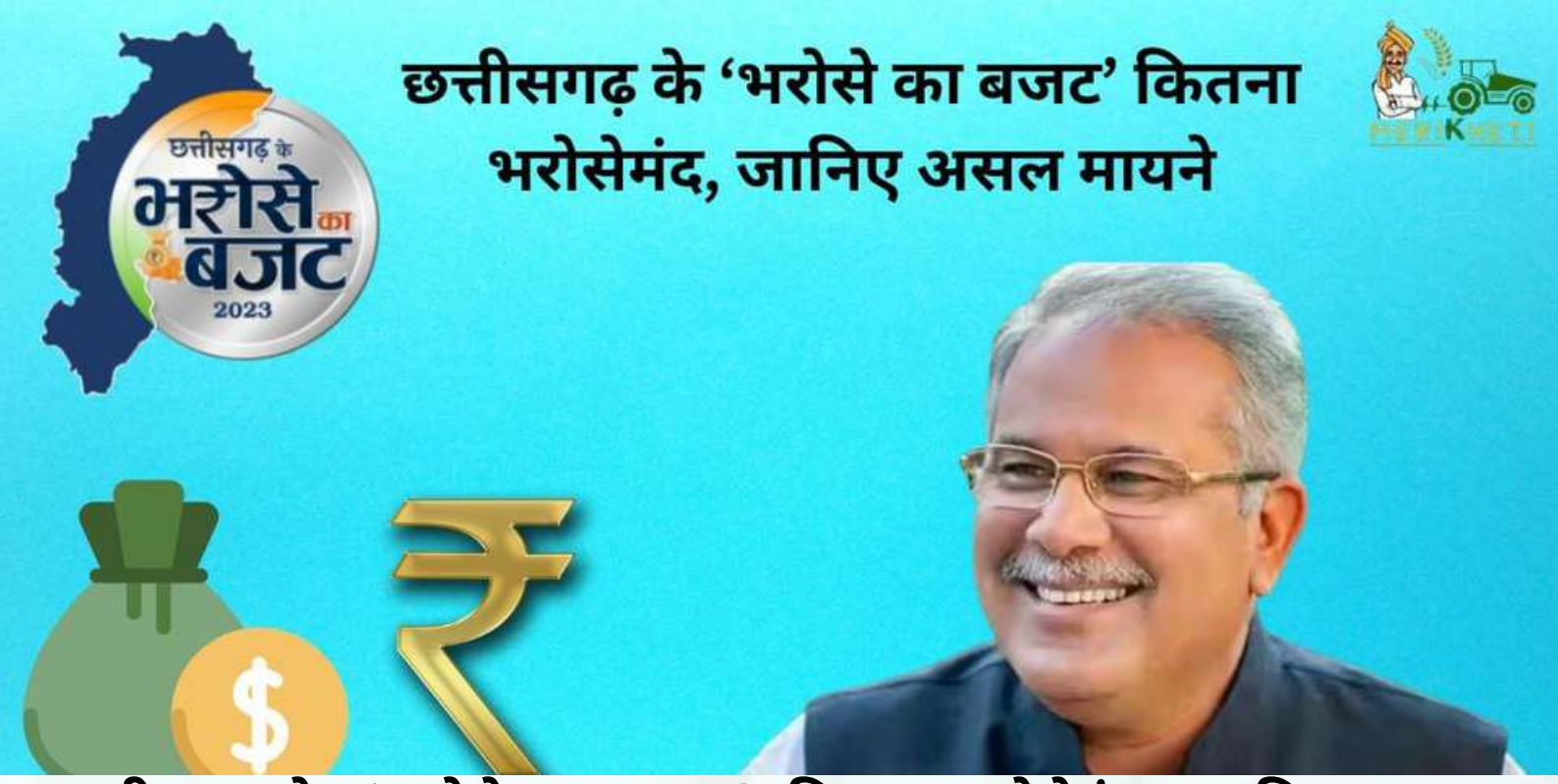

छत्तीसगढ़ के 'भरोसे का बजट' कितना भरोसेमंद, जानिए असल मायने

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश सिंह बघेल जल्द ही बजट पेश करने वाले हैं. उन्हों इस बजट को भरोसे का बजट नाम दिया है, हालांकि सीएम के पिटारे से जनता के लिए क्या कुछ निकलने वाला है,न और क्या यह बजट जनता की कसौटियों पर उतर पाएगा, इस बात से पर्दा तो बजट पेश होने के बाद ही उठेगा. लेकिन इससे पहले सीएम ने जनता के नाम संबोधन दिया. जिसमें उन्होंने कई अहम बातों का जिक्र किया.

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस बार के बजट को भरोसे का बजट कहा है. उन्होंने बजट को यह नाम प्रदेश की जनता जो संबोधन करते वक्त दिया. बजट में क्या ख़ास है, और इसके मायने क्या हैं, इसका बेसब्री से जनता को इन्तजार है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सीएम ने गृह विभाग, कृषि विभाग, सिंचाई विभाग, स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग, रोजगार विभाग और सड़क विभाग से जुड़े अलग अलग मंत्रियों के साथ साथ अफसरों से भी चर्चा की और उसी के आधार पर बजट की रूप रेखा को तैयार किया.

सीएम के कार्यकाल का आखिरी बजट बेहद ख़ास

बताया जा रहा है कि, भूपेश सिंह बघेल सीएम और वित्त मंत्री दोनों का जिम्मा खुद उठा रहे हैं. उनके कार्यकाल का यह आखिरी बजट है. जिस वजह से इस बजट को बेहद खास बताया जा रहा है. विधानसभा चुनाव साल 2023 के चलते हर वर्ग और हर तबके के लोगों को साधने की तैयारी है. वहीं जो कर्मचारी सरकार की नीतियों से रूठे हैं, उन्हें मनाने की कोशिश भी इस बार के बजट में की जाएगी. इसके अलावा सालों से लम्बित पड़ी मांगों को भी पूरा किया जा सकता है.

वहीं छत्तीसगढ़ के इस साल के बजट में नियमित समय कई तरह की जनता से जुड़ी घोषणाएं की जा सकती हैं.

बजट में किसानों को मिल सकती है सौगात

किसानों के जरिये सत्ता हासिल करने वाली कांग्रेस सरकार किसानों के हित में बजट के पिटारे से कुछ खास घोषणाएं कर सकती है. हालांकि राज्य में धान की खेती सबसे ज्यादा की जाती है, जिसपर राजनीती भी केन्द्रित रहती है. बताया जा रहा है कि, धान पर बोनस को लेकर केंद्र से लेकर राज्य सरकार के बीच हमेशा से ही खींचतान रहती है. जिस बझ से छत्तीसगढ़ सरकार किसानों के हित में बड़ा ऐलान कर सजती है. खबरों के मुताबिक धान के अलावा अन्य खाद्यान के समर्थन मूल को लेकर बड़ा तोहफा दिया जा सकता है. वहीं खेती और किसानी से जुड़े उपकरणों में करों में छूट देने के साथ सब्सिडी को बढ़ाया जा सकता है.

अनियमित संविदा कर्मचारियों के सपने हो सकते हैं पूरे

छत्तीसगढ़ के बजट में अनियमित संविदा कर्मचारियों को अच्छी खबर मिल सकती है. बजट के जरिये उनका सपना पूरा हो सकता है. बताया जा रहा है कि, कर्मचारियों के संविलियन की राह आसान हो सकती है. इसके अलावा युवाओं के लिए नौकरी, पुलिस में भर्ती और और शिक्षक में भर्ती समेत कई अहम ऐलान हो सकता है.

युवाओं और महिलाओं के लिए भी खास है बजट

इस बजट में युवाओं और महिलाओं के लिए भी काफी कुछ हो सकता है. जिसमें स्टार्टअप योजना से लेकर इनोवेशन सेंटर खोलने और महिलाओं को सेल्फ डिपेंड बनाने को लक्सर बड़ा ऐलान किया जा सकता है.

यहां पर भी सरकार की नजर

अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग और आदिवासी वर्ग को वोट को साधने का सरकार का सबसे बड़ा मास्टर प्लान है. जिसके लिए सरकार कई बड़े ऐलान कर सकती है.

जल्द ही पूरी तरह से खत्म हो सकता है महोबा का देशावरी पान

भारत में पान बहुतायत से उपयोग किया जाता है, जिसकी मांग को पूरा करने के लिए भारत के कई राज्यों में पान की खेती की जाती है। लेकिन पिछले कुछ समय से देखा गया है कि पान के किसान बाजार में घटती हुई मांग और मौसम की मार के कारण कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। जिसके कारण पान किसानों का पान की खेती की तरफ से रुझान कम होता जा रहा है और पान की बहुत सारी किस्में बुरी तरह से प्रभावित हुई हैं।

इसी तरह की पान की एक किस्म है देशावरी। यह किस्म मुख्यतः उत्तर प्रदेश के महोबा में उगाई जाती है। अन्य किस्मों की की तरह यह किस्म भी मौसम के प्रतिकूल प्रभाव और खेती की बढ़ती लागत एक कारण विलुप्त होने की कगार पर है। महोबा के पान की खेती करने वाले किसान बताते हैं कि पान की खेती के लिए एक निश्चित तपमान और मौसम की जरूरत होती है, लेकिन पिछले कुछ सालों से भीषण शीतलहर और गर्मी के कारण यह फसल बुरी तरह से प्रभावित हो रही है।

महोबा में पिछले 1000 सालों से ज्यादा समय से पान की खेती हो रही है। जिसके कारण इस क्षेत्र को अलग पहचान मिली है। पान की खेती चंदेल राजवंश के दौर में सबसे ज्यादा की जाती थी।

अगर अब वर्तमान के आंकड़ों पर गौर करें तो साल 2000 से लेकर साल 2022 तक महोबा में पान की खेती में 95 प्रतिशत से ज्यादा की गिरावट आ चुकी है। इस दौरान पान की खेती करने वाले लगभग 75 प्रतिशत किशानों ने यह खेती करना छोड़ दी है। इसका कारण किसान पान की खेती में बढ़ती हुई लागत को जिम्मेदार बताते हैं। किसान बाताते हैं कि अब बरेजा (पान की खेती के लिए बनाए गए अस्थायी ढांचे) बनाने की कीमत बहुत बढ़ गई है। पान के बरेजा में इस्तेमाल होने वाला बांस, बल्ली, तार, घास, सनौवा आदि की कीमतें पिछले कुछ सालों में अप्रत्याशित रूप से बढ़ी हैं। इनकी कीमतें चार से पांच गुना तक बढ़ गई हैं। जो किसानों को इस खेती को करने के लिए हतोत्साहित करता है।

देशावरी पान के विशिष्ट गुणों के कारण ही पिछले दिनों भारत सरकार ने पान की इस किस्म को जीआई (ज्योग्राफिकल इंडीकेशन) टैग दिया था। यह पान विलक्षण गुणों वाला है और अपने करारेपन और स्वाद के लिए लोगों के बीच हमेशा लोकप्रिय रहा है। इसकी विशेषता है कि यह पान मुंह में डालते ही पूरी तरह घुल जाता है। यह गुण इस किस्म के पान के अलावा अन्य किस्म के पान में नहीं पाया जाता है।

यह गुण इस किस्म के पान के अलावा अन्य किस्म के पान में नहीं पाया जाता है। किसान बताते हैं कि जीआई टैग मिलने के बावजूद पान की इस किस्म की खेती में कोई सुधार नहीं हुआ है। पिछले दिनों उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने देशावरी पान का उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकारी सहायता की घोषणा की थी, लेकिन उन घोषणाओं का अभी तक धरातल पर उतारा जाना बाकी है।

पान के किसानों ने बताया है कि यह एक जोखिम भरी खेती है। जिसमें किसानों को फायदा के साथ ही बड़ा घाटा लगने की पूरी संभावनाएं बनी रहती हैं। इस साल ज्यादा ठंड पड़ने के कारण कई किसानों की फसल चौपट हो गई जिसके कारण किसानों को लाखों रुपये का नुकसान हुआ है। महोबा में पान की खेती पर नजर रखने वाले सरकारी अधिकारियों ने बताया है कि इस साल पान की लगभग 80 प्रतिशत खेती चौपट हो गई है।

सरकारी अधिकारी बताते हैं कि प्रतिकूल मौसम में पान की खेती करना अब चुनौतीपूर्ण होता जा रहा है। उन्होंने बताया कि पान की खेती कृत्रिम और संतुलित जलवायु में की जाती है जहां खेती के लिए गर्मियों में 45 डिग्री सेल्सियस तापमान तथा सर्दियों में 6 डिग्री सेल्सियस तापमान उपयुक्त होता है। लेकिन इस बार सर्दियों में तापमान माइनस 2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था, जिसके कारण फसल बुरी तरह से प्रभावित हुई है।

किसानों का कहना है कि इस घाटे से उबारने के लिए पान का मूल्यवर्धन जरूरी हो गया है। लेकिन सरकार इस ओर अभी ध्यान नहीं दे रही है। चूंकि यह 12 महीने की फसल है, जो जनवरी से लेकर दिसम्बर का उगाई जाती है। इस कारण से सरकार ने अभी तक इस फसल को किसी भी योजना में शामिल नहीं किया है। हालांकि सरकार ने पान का बरेजा लगाने के लिए किसानों को सीधे सरकारी मदद देना शुरू कर दी है। किसानों का कहना है कि पान की मांग गुटखा के चलन के बाद बुरी तरह से प्रभावित हुई है, क्योंकि बड़ी संख्या में पान खाने वाले लोग गुटखा की तरफ शिफ्ट कर गए हैं।

पान के तेल की बाजार में भारी मांग है और यह बेहद महंगा भी बिकता है। अगर आज के भाव की बात करें तो बाजार में पान के तेल की कीमत एक लाख रुपये प्रति किलो है। इसका उपयोग आयुर्वेदिक दवाओं, पान कैंडी, पान कंद, पान आइसक्रीम के अलावा कई मिठाइयों में होता है। इस तरह के वैकल्पिक रास्ते खोजकर किसान भाई पान की खेती से भी अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं।

पशुपालन-पशुचारा

राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र ने मोटे अनाजों के उत्पादों को किया प्रोत्साहित

राजस्थान में मोटे अनाजों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। राज्यपाल कलराज मिश्र ने बताया है, कि मोटे अनाज कुटकी, संवा, कंगनी, चेना, कोदो, बाजरा, ज्वार, रागी पारम्परिक रूप से भारतीय भोजन का भाग रहे हैं।

राजस्थान राज्य के राज्यपाल कलराज मिश्र ने भारत की बढ़ती जनसंख्या को पोषण युक्त भोजन मुहैय्या कराने के लिए मोटे अनाजों की कृषि को समस्त स्तरों पर बढ़ावा दिए जाने के लिए पहल की जा रही है। उनका कहना है, कि पोषण की प्रचूर मात्रा से युक्त मोटे अनाजों के समयानुसार सेवन से शरीर की प्रतिरोधक क्षमता सुदृण बनती है। इस वजह से मोटे अनाजों को आम जनता में प्रचलित एवं लोकप्रिय बनाने के खूब प्रयास किए जा रहे हैं।

जोबनेर के श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह को गुरुवार को राजभवन से डिजिटल माध्यम से संबोधित करते हुए मिश्र ने कहा है, कि मोटे अनाज संवा, कंगनी, चेना, कोदो, बाजरा, ज्वार, रागी एवं कुटकी परंपरागत रूप से भारतीय भोजन का अभिन्न हिस्सा रहे हैं। राजस्थान के अधिकांश इलाकों में फिलहाल भी मोटा अनाज आम लोगों के भोजन का महत्वपूर्ण भाग है।

कृषि शिक्षा को एक नई दिशा देनी की बेहद आवश्यकता है

राज्यपाल ने बताया कि यह दौर विवेकपूर्ण कृषि का है। आपको बतादें कि बदलते समय में रोबोटिक्स, बिग डाटा एनालिटिक्स, रिमोट सेन्सिंग, आईओटी एवं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने कृषि क्षेत्र में एक नई क्रांति का स्वागत किया है। उन्होंने बताया है, कि कृषि विश्वविद्यालयों को स्मार्ट कृषि से संबंधित नई तकनीकों के लिए किसान भाइयों को जागरूक किया जाएगा। मिश्र ने बताया है, कि खराब होते मौसमिक तंत्र, जैव विविधता पर चुनौती एवं सिंचाई के साधनों के अभाव के संबंध में बेहतर सोच रखी है। कृषि शिक्षा को नई दिशा देनी की बेहद आवश्यकता है।

विद्यार्थियों को स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया है

राज्यपाल जी ने प्राकृतिक आपदा बारिश एवं ओलावृष्टि से कृषि पर पड़ रहे दुष्प्रभावों की ओर संकेत करते हुए कृषि विज्ञान केन्द्रों के अंतर्गत जलवायु बदलाव का विस्तृत अध्ययन किए जाने की राय दी गई है।

राज्यपाल ने बताया है, कि कृषि पद्धतियों के पुराने एवं नए ज्ञान का बेहतर उपयोग करते हुए किसान भाइयों के लिए प्रभावी पद्धतियां तैयार करने की जरूरत है, जिससे कि कृषि पैदावार में वृद्धि, खाद्य सुरक्षा के लिए खाद्य उत्पादन एवं भंडारण, पर्याप्त पोषण युक्त खाद्य मुहैय्या कराने के वांछित लक्ष्यों को हांसिल किया जा सके। इस उपलक्ष्य पर 3 विद्यार्थियों को समेकित कृषि स्नातकोत्तर उपाधियां, 985 विद्यार्थियों को कृषि स्नातक उपाधियां, 32 विद्यार्थियों को पीएचडी, 75 को स्नातकोत्तर तथा आठ विद्यार्थियों को स्वर्ण पदक प्रदान किए गए।

संयुक्त राष्ट्र ने 2023 को मोटा अनाज दिवस के रूप में मनाया है

आपको हम बतादें कि भारत सरकार के निवेदन पर संयुक्त राष्ट्र द्वारा 2023 को मोटा अनाज वर्ष की घोषणा की गई है। साथ ही, केंद्र सरकार भी भारत के अंदर मोटे अनाज की किस्मों की खेती को प्रोत्साहन देना चाहती है। इसके लिए वह किसान भाइयों को प्रेरित कर रही है। विगत माह मोटे अनाज की कृषि को बढ़ावा देने के लिए संसद भवन के अंदर बाजरे से निर्मित व्यंजन प्रस्तुत किया गया था। जिसका पीएम मोदी सहित अन्य मंत्रियों एवं सांसदों ने भी स्वाद चखा था।

प्राकृतिक खेती से किसानों को होगा फायदा, जल्द ही देश के किसान होंगे मालामाल

वर्तमान में केमिकल युक्त खेती के दुष्परिणामों की देखते हुए सरकार प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दे रही है। इसके लिए सरकार ने इस साल के बजट में प्राकृतिक खेती के लिए अलग से प्रावधान किया है। केंद्र सरकार के साथ-साथ हरियाणा की सरकार भी प्राकृतिक खेती को लेकर बेहद जागरुक है। इसके साथ ही हरियाणा की सरकार ने किसानों को जागरुक करने के लिए प्रोत्साहन योजना शुरू की है। इसके अंतर्गत राज्य सरकार ने साल 2022 में छह हजार एकड़ में किसानों से प्राकृतिक खेती कराई है। इसको राज्य के 2238 किसानों ने अपनाया है।

किसानों के रुझान को देखते हुए हरियाणा सरकार ने साल 2023 में राज्य में 20 हजार एकड़ में प्राकृतिक खेती कराने का लक्ष्य रखा है। हरियाणा की सरकार ने किसानों के बीच प्राकृतिक खेती को प्रचारित करने के लिए 'भरपाई योजना' को भी लागू किया है। इसके अंतर्गत प्राकृतिक खेती अपनाने वाले हर किसान को प्रति एकड़ के हिसाब से प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी। सरकार ने 'भरपाई योजना' को इसलिए लागू किया है क्योंकि प्राकृतिक खेती करने वाले किसानों को शुरुआत में उत्पादन कम प्राप्त होता है। लेकिन प्राकृतिक खेती करने से भूमि की उत्पादन क्षमता में भी बढ़ोतरी होती है। जो किसानों के लिए लंबे सामयांतराल में फायदेमंद होता है।

किसान भाइयों को प्राकृतिक खेती की ट्रेनिंग देने के लिए हरियाणा की सरकार ने राज्य में कई ट्रेनिंग सेंटर स्थापित किए हैं।

इसके लिए फिलहाल कुरुक्षेत्र गुरुकुल और करनाल के घरौंडा में बड़े ट्रेनिंग सेंटर स्थापित किए हैं। इसके साथ ही सरकार ने राज्य में 3 और ट्रेनिंग सेंटर स्थापित करने का निर्णय लिया है। इन ट्रेनिंग सेंटरों का मुख्य उद्देश्य प्राकृतिक खेती के लिए किसानों को प्रशिक्षित करना है।

राज्य सरकार के अधिकारियों ने बताया है कि प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए सरकार जागरूकता अभियान शुरू करने जा रही है। इसकी शुरुआत सिरसा जिले से होगी। सिरसा जिले में यह अभियान पायलट प्रोजेक्ट के तहत शुरू किया जा रहा है। यदि यहां पर यह अभियान सफल रहता है तो बाद में इसे चरणबद्ध तरीके से पूरे राज्य में लागू किया जाएगा। इस जागरूकता अभियान में किसानों को उर्वरकों व कीटनाशकों के उपयोग, पानी का समुचित उपयोग, फसल स्वास्थ्य निगरानी, मृदा स्वास्थ्य निगरानी, कीट निगरानी, सौर ऊर्जा का उपयोग और सूक्ष्म सिंचाई तकनीक के माध्यम से पानी के समुचित उपयोग के बारे में विस्तार से बताया जाएगा।

इन दिनों भारत में किसानों के द्वारा प्राकृतिक खेती तेजी से अपनाई जा रही है। जिसके कई स्वदेशी रूप हैं। प्राकृतिक खेती का प्रचार प्रसार सबसे ज्यादा दक्षिण भारतीय राज्यों में है।

दक्षिण भारत के राज्य आंध्र प्रदेश में प्राकृतिक खेती बेहद लोकप्रिय है। आंध्र प्रदेश के साथ ही प्राकृतिक खेती छत्तीसगढ़, केरल, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, ओडिशा, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु के अलावा कई राज्यों में की जा रही है। यह खेती प्राकृतिक या पारिस्थितिक प्रक्रियाओं (जो खेतों में या उसके आसपास मौजूद होती हैं) पर आधारित होती है जो पेड़ों, फसलों और पशुधन को एकीकृत करती है। वैज्ञानिकों का मानना है कि प्राकृतिक खेती से किसानों की आय में तेजी से बढ़ोत्तरी हो सकती है।

नेपियर घास को खिलाने से बढ़ती है पशुओं की दूध देने की क्षमता

नेपियर घास को खिलाने से बढ़ती है पशुओं की दूध देने की क्षमता

पशुओं की दूध की क्षमता बढ़ाने के लिए किसान एवं पशुपालक काफी प्रयासरत रहते हैं। इसी विषय से संबंधित हम आज आपको बताने जा रहे हैं, नेपियर घास के बारे में। इस घास को पशुओं को खिलाते ही पशुओं में दूध देने की क्षमता 10 से 15 फीसद तक बढ़ जाती है। इस परिस्थिति में पशुपालक अत्यधिक दूध विक्रय कर अच्छी आय अर्जित कर सकते हैं।

जैसा कि हम जानते हैं, कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। यहां पर 75 फीसद जनसँख्या आज तक भी गांव में ही रहती है, जो कि खेती एवं पशुपालन से संबंधित हुई है। इसका जीवन यापन भी कृषि एवं पशुपालन के माध्यम से ही चलता है। साथ ही, बहुत सारे किसान गांव में ऐसे भी मौजूद होते हैं, जो पूर्णतय भूमिहीन होते हैं। ऐसी स्थिति में वह पशुपालन करके स्वयं के घर का खर्च चलाते हैं। इसके लिए वह दूध सहित मक्खन एवं घी विक्रय करते हैं, जिससे उनको मोटी आय होती है।

विशेष बात यह है, कि पशुपालन से संबंधित बेहतरीन आय तभी की जा सकती है, जब उनके पशु ज्यादा दूध दें। इसके लिए पशुओं से अधिक दूध निकालने हेतु उन्हें बेहतरीन एवं पौष्टिक आहार भी देना आवश्यक होगा। ऐसी स्थिति में हरी- हरी घासें पशुओं की सेहत और दूध वृद्धि में कारगार भूमिका निभाएंगी। आपको बतादें कि, हरी- हरी घास का सेवन करने से पशुओं की दूध देने की क्षमता में बढ़ोत्तरी हो जाती है। इस वजह से बरसीम, जिरका, गिनी एवं पैरा जैसी घास पशुओं को खिलाना उत्तम रहता है। हालाँकि, इन समस्त घासों में नेपियर घास सर्वाधिक अच्छी मानी जाती है।

निरंतर पांच वर्ष तक घास की कटाई कर सकते हैं

जानकारों के अनुसार, नेपियर घास की खेती हर प्रकार की मृदा में की जा सकती है। इस वजह से अत्यधिक परिश्रम करने की भी आवश्यकता नहीं होती है। विशेष बात यह है, कि इसकी सिंचाई भी काफी कम करनी पड़ती है। इस वजह से इसकी लागत में काफी कमी आती है। नेपियर की सबसे बड़ी विशेषता यह है, कि इसकी एक बार रोपाई के उपरांत आप पांच वर्ष तक हरा चारा काट सकते हैं। इसकी प्रथम कटाई खेती शुरू करने के 65 दिन उपरांत की जाती है। इसके उपरांत आप 35- 40 दिनों के समयांतराल पर निरंतर पांच वर्ष तक कटाई की जा सकती है।

किसान दूध विक्रय से बेहतर आय अर्जित कर सकते हैं

आपको बतादें कि नेपियर घास को हम बंजर भूमि पर भी उगा सकते हैं। साथ ही, किसान खेत की मेढ़ पर भी इसको रोप सकते हैं। जानकारी के लिए बतादें कि नेपियर की रोपाई फरवरी से जुलाई माह के मध्य की जाती है। इसके खेत में जल निकासी हेतु बेहतरीन सुविधा होनी आवश्यक है । मीडिया खबरों के अनुसार, इस घास में 10 फीसद तक प्रोटीन रहता है। साथ ही, रेशा 30 प्रतिशत, जबकि कैल्सियम 0.5 फीसद होता है। इसको दलहन के चारे सहित मिश्रण कर पशुओं को खिलाना चाहिए। इसके सेवन से पशुओं में दूध देने की क्षमता 10 से 15 फीसद तक वृद्धि हो जाती है। ऐसी स्थिति में पशुपालक अधिक दूध विक्रय कर बेहतरीन आय अर्जित कर सकते हैं।

छुट्टा गौवंश से परेशान किसान ने अपनी सात बीघा भूमि में खड़ी फसल पर चलाया ट्रैक्टर

उत्तर प्रदेश राज्य के अंतर्गत आने वाले बिजनौर जनपद में आवारा पशुओं से दुखी होकर एक किसान ने खेत में खड़ी गेहूं की फसल पर ट्रैक्टर चला दिया। कहा गया है, कि ग्रामीण एवं किसान छुट्टा गोवंश से बेहद दुखी हैं। इसी कारण किसान ने अपने खेत में खड़ी फसल को जोत डाला। किसान सुनील कुमार ने सात बीघा में खड़ी फसल को उजाड़ा

बिजनौर के गंज दारानगर में निराश्रित पशुओं से परेशान किसान ने गेहूं की फसल जोत डाली। जानकारी के अनुसार गांव शांहपुर में एक किसान ने अपने करीब सात बीघा गेहूं की फसल ट्रैक्टर से जोत डाली। किसान सुनील कुमार का आरोप है कि छुट्टा पशु फसलों को बर्बाद कर रहे हैं। शासन-प्रशासन इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा। इसीलिए उसने अपनी गेहूं की खड़ी-फसल को ट्रैक्टर से जोत दिया।

बिजनौर के ग्राम शाहपुर में हुई यह घटना

ग्राम शाहपुर निवासी सुनील कुमार ने सात बीघा गेहूं की फसल आवारा पशु से हताश होकर फसल जोत डाली। पशु गेहूं की फसल को काफी प्रभावित कर रहे हैं। किसान पूरी-पूरी रात जागकर फसल की निगरानी करते रहे हैं एवं निराश्रित पशुओं को खेतों से भगाते हैं। इसके उपरांत आवारा पशुओं ने गेहूं की फसल को काफी हानि पहुंचाई है। इससे हताश होकर किसान सुनील कुमार ने मंगलवार को सात बीघे में गेहूं की फसल को जोत दिया है।

क्षेत्र में भारी तादात में पशु घूम रहे हैं, जो फसल को काफी हानि पहुंचा रहे हैं। जब तक आवारा पशुओं को पकड़कर गौशालाओं में नहीं पहुँचाया जाता, तब तक फसल की सुरक्षा करना काफी दुर्लभ सा काम हो गया है। किसानों ने आवारा पशुओं को पकड़ कर गौशाला में भेजने की मांग जाहिर की है।

योगी सरकार का निराश्रित गौवंश के लिए क्या कर रही है

हालाँकि, राज्य सरकार गौवंश के बेहतर प्रबंधन के लिए कई सारे अहम कदम उठा रही है। योगी सरकार गौ-आधारित कृषि को प्रोत्साहन देने का कार्य कर रही है। जिसके लिए राज्य सरकार ने काफी मोटी धनराशि आवंटित की है। साथ ही, तारबंदी कराने के लिए भी किसानों को अनुदान भी मुहैय्या कराया जाता है।

जाने कैसे लेमन ग्रास की खेती करते हुए किसानों की बंजर जमीन और आमदनी दोनों में आ गई है हरियाली

जाने कैसे लेमन ग्रास की खेती करते हुए किसानों की बंजर जमीन और आमदनी दोनों में आ गई है हरियाली

आजकल किसान खेती में अलग-अलग तरह के प्रयोग कर रही हैं. पारंपरिक फसलों की खेती से हटकर आजकल के साथ ऐसी फसलें उगा रहे हैं जो उन्हें इनके मुकाबले ज्यादा मुनाफा देती हैं और उनकी आमदनी बढ़ाने में भी मदद करती हैं. इसी तरह की फसलों में बागवानी सच में काफी ज्यादा चलन में हैं.

आज हम लेमन ग्रास/ मालाबार ग्रास या हिंदी में नींबू घास के नाम से जाने वाली फसल के बारे में बात करने वाले हैं जिसे उगा कर आजकल किसान अच्छा खासा लाभ और मुनाफा कमा रहे हैं.

इस फसल की सबसे अच्छी बात यह है कि इसे बंजर जमीन में भी आसानी से उगाया जा सकता है और इसे बहुत ज्यादा सिंचाई की जरूरत नहीं पड़ती है. इसके अलावा इस फसल को उगाने में बहुत ज्यादा कीटनाशक दवाइयां वेतनमान नहीं करनी पड़ती हैं. यह एक औषधीय फसल मानी जाती है और पशु लेमन ग्रास को नहीं खाते हैं इसलिए आपको अपने खेतों में पशुओं से बचाव करने की भी जरूरत नहीं है. आप बिना कोई बाड़ा बनाई भी खुले खेत में नींबू घास की फसल आसानी से उग सकते हैं.

बिहार सरकार दे रही है लेमन ग्रास की फसल उगाने पर सब्सिडी

लेमन ग्रास की फसल से जुड़ी हुई एक बहुत बड़ी खबर बिहार राज्य सरकार की तरफ से सामने आ रही है. बिहार सरकार किसानों को नींबू घास की खेती करने पर सब्सिडी दे रही है.

पिछले साल ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड में बहुत ही महिला किसानों की तारीफ भी की थी जो उच्च स्तर पर लेमन ग्रास की खेती कर रही है.इसी झारखंड के साथ-साथ बिहार में भी यह फसल उगाने का चलन पिछले कुछ समय में बहुत बढ़ गया है. बिहार के बांका, कटोरिया, फुल्लीडुमर, रजौन, धोरैया, सहित अन्य जिलों के किसान में नींबू घास की खेती कर रहे हैं.

प्रति एकड़ लेमन ग्रास की फसल पर दी जाएगी ₹8000 की सब्सिडी

जैसा कि पहले ही बताया जा चुका है कि नींबू घास की खेती बंजर जमीन पर भी की जा सकती है. ऐसे में बिहार सरकार बंजर जमीन का इस्तेमाल करने के लिए किसानों को प्रोत्साहित कर रही है और इसी कड़ी में अगर किसान बंजर भूमि में लेमन ग्रास की खेती करते हैं तो उन्हें प्रति एकड़ की दर से ₹8000 की सब्सिडी बिहार सरकार द्वारा दी जाएगी. अब वहां पर आलम ऐसा है कि कई वर्षों से खाली पड़ी हुई बंजर जमीन पर किसान बढ़-चढ़कर नींबू घास की खेती कर रहे हैं और इससे पूरे राज्य भर में हरियाली तो आई ही है साथ ही किसानों की आमदनी में भी अच्छा खासा इजाफा हुआ है.

लेमन ग्रास का इस्तेमाल कहां किया जाता है?

यह एक औषधि है और लेमन ग्रास का तेल निकाला जा सकता है जो कई तरीकों से इस्तेमाल किया जा सकता है. इसके तेल से बहुत ही दवाइयां, घरेलू उपयोग की चीजें, साबुन तेल और बहुत से कॉस्मेटिक प्रोडक्ट (COSMETIC PRODUCT) भी बनाए जा सकते हैं. नींबू घास की फसल से बनने वाले तेल में पाया जाने वाला सिट्रोल उसे विटामिन ई का एक बहुत बड़ा स्त्रोत बनाता है.

कम पानी में भी आसानी से उगाई जा सकती है यह फसल

अगर आपके पास पानी का स्रोत नहीं है तब भी आप आसानी से लेमन ग्रास की खेती कर सकते हैं. इसके अलावा इस फसल को बहुत ज्यादा कीटनाशक या उर्वरक की भी जरूरत नहीं पड़ती है. जानवर एक खास को नहीं खाते हैं इसलिए किसानों को जानवरों से भी फसल को किसी तरह के नुकसान होने का डर नहीं है. एक बार लगाने के बाद इस फसल की बात से छह बार कटाई की जा सकती है.

कितनी लगती है लागत?

शुरुआत में अगर आप 1 एकड़ जमीन में है फसल उगाना चाहते हैं तो लगभग बीज और खाद आदि को मिलाकर 30 से 40,000 तक खर्च आ सकता है. 1 एकड़ के खेत में यह फसल उगाने के लिए लगभग 10 किलो बीज की आवश्यकता पड़ती है. बीज लगाने के बाद 2 महीने के अंदर-अंदर इसके पौधे तैयार हो जाते हैं. अगर किसान चाहे तो किसी नर्सरी से सीधे ही लेमन ग्रास के पौधे भी खरीद सकते हैं

1 साल में नींबू घास की फसल की 5 से 6 बार कटाई करके पत्तियां निकाली जा सकती हैं.

अगर आप इस फसल को किसी बंजर या कम उपजाऊ जमीन पर भी लगा रहे हैं तो एक बार लगाने के बाद यह लगभग अगले 6 सालों तक आपको अच्छा खासा मुनाफा देती है.

एक्सपर्ट बताते हैं कि अगर आप नींबू घास की अच्छी पैदावार करना चाहते हैं तो खेत में गोबर और लकड़ी की राख डालते रहें.

बिहार में बनवाए जा रहे हैं लेमन ग्रास का तेल निकालने के लिए प्रोसेसिंग यूनिट

बिहार में राजपूत और कटोरिया में लेमन ग्रास तेल निकालने के लिए प्रोसेसिंग यूनिट बनाई जा चुकी है. इसका तेल निकालने के लिए काम में आने वाली मशीन लगभग ₹400000 की आती है. नींबू घास के 1 लीटर तेल की कीमत बाजार में 1200 से ₹2000 तक लगाई जाती है. इस तरह से किसान कुछ एकड़ में यह फसल उगा कर लाखों का मुनाफा थाने से कमा सकते हैं. अगर 1 एकड़ में भी है फसल लगाई जाती है तो उसमें इतनी फसल आसानी से हो जाती है कि उससे 100 लीटर के लगभग तेल की निकासी की जा सके. यहां के किसानों से हुई बातचीत में पता चला है कि कृषि विभाग भी इस फसल को उगाने में किसानों की आगे बढ़कर मदद कर रहा है. किसानों का कहना है कि इस फसल की मदद से उनकी बंजर भूमि में तो हरियाली आती ही है साथ ही उनकी आर्थिक स्थिति में भी हरियाली आई है.

सामान्य लेख

अब भारतीय किसानों की आजीविका सुधारने के लिए काम करेगा वॉलमार्ट WALMART, 10 लाख किसानों को होगा फायदा

भारत में वॉलमार्ट (WALMART) अब छोटे किसानों की आजीविका को सुधारने का काम करने जा रहा है। इसके लिए वॉलमार्ट फाउंडेशन ने बुधवार को अपनी नई पंचवर्षीय रणनीति की घोषणा की। इसके साथ ही फाउंडेशन ने 2 अन्य अनुदानों की भी घोषणा की है। वॉलमार्ट फाउंडेशन का कहना है कि इस रणनीति के जरिए वह देश के 10 लाख छोटे किसानों तक पहुंच सुनिश्चित करना चाह रहा है। इसमें 50 फीसदी महिला किसानों को भी शामिल किया जाएगा। इस रणनीति के तहत उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा सहित कई राज्यों के छोटे किसानों की आय बढ़ाने पर फोकस किया जाएगा। इसके लिए वॉलमार्ट फाउंडेशन अनुदान भी प्रदान करेगा।

वॉलमार्ट फाउंडेशन (WALMART FOUNDATION) अपनी इस पहल से महिला किसानों को सशक्त करना चाह रहा है, साथ ही खेती में आधुनिक उपकरणों को बढ़ावा देना उसका अगला लक्ष्य है। बकौल वॉलमार्ट फाउंडेशन (WALMART FOUNDATION), छोटे किसानों के बीच पर्यावरण के अनुकूल खेती को प्रोत्साहित करना उनका मुख्य लक्ष्य है।

इन किसानों को मिलेगा अनुदान

वॉलमार्ट फाउंडेशन (WALMART FOUNDATION) ने कहा है कि महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में छोटे किसानों के लिए 30 लाख अमेरिकी डॉलर का अनुदान दिया जाएगा। इसका फायदा 30 हजार छोटे किसानों को होगा, जिनमें आधी महिला किसान भी शामिल होंगी। साथ ही ओडिशा में 1 हजार महिला किसानों को 5 लाख 33 हजार 876 डॉलर का अनुदान दिया जाएगा। इसके साथ ही महिला किसानों को 2 उत्पादक संगठनों से जोड़ा जाएगा। इससे महिला किसानों की आय में इजाफा हो सकता है।

वॉलमार्ट (WALMART) की रणनीति से इन राज्यों के किसानों को होगा फायदा

वॉलमार्ट फाउंडेशन (WALMART FOUNDATION) ने बताया है कि उनकी रणनीति मुख्य तौर पर आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, उड़ीसा, झारखंड एवं पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के किसानों पर केंद्रित रहेगी। इसके साथ ही इन राज्य के छोटे किसानों को अनुदान भी प्रदान किया जाएगा।

इस दौरान वॉलमार्ट (WALMART) के घोषणा कार्यक्रम में केन्द्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी मौजूद रहे। उन्होंने वॉलमार्ट के द्वारा छोटे किसानों और खास तौर पर महिला किसानों के सहयोग के लिए धन्यवाद दिया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार भी लगातार देश के किसानों के उत्थान के लिए काम कर रही है, इसके लिए सरकार ने कई योजनाएं चलाई हैं जिनसे देश के किसान लाभान्वित हो रहे हैं। इस घोषणा कार्यक्रम के दौरान वॉलमार्ट के कर्मचारियों ने बताया कि उनका फाउंडेशन आगामी साल 2028 तक 10 लाख किसानों की मदद करने जा रहा है।

वॉलमार्ट (WALMART) की इस पहल से छोटे किसानों को होगा फायदा

वॉलमार्ट (WALMART) की इस पहल से छोटे किसानों और मुख्य तौर पर महिला किसानों को फायदा होने वाला है। यह एक प्रकार से वॉलमार्ट की ओर से महिला सशक्तिकरण में एक नया कदम होगा। वॉलमार्ट से जुड़ने के बाद महिला किसान मुख्य धारा में आ जायेंगी और आधुनिक कृषि यंत्रों की सहायता से उन्नत खेती कर सकेंगी। इससे महिला किसानों की आय के साथ ही उनके जीवन जीने के तरीके में भी सुधार होगा।

यूपी के बरेली में मौजूद भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान केंद्र संस्थान ने सरोगेसी तकनीक का सफल परीक्षण किया

यूपी के बरेली में मौजूद भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान केंद्र संस्थान ने सरोगेसी तकनीक का सफल परीक्षण किया

उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद में मौजूद भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान केंद्र संस्थान के माध्यम से सरोगेसी तकनीक का सफल परीक्षण किया गया है। वैज्ञानिकों ने कहा है, कि सरोगेसी तकनीक के माध्यम से फिलहाल 26 बछड़ों का प्रजनन हो गया है। अब केवल इंसान ही नहीं गायें भी सरोगेसी तकनीक के माध्यम से बछड़े को जन्म देंगी। इसका सफलता पूर्ण परीक्षण उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद में मौजूद भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान में किया जा चुका है।

बताया जा रहा है, कि फिलहाल इंसानों के जैसे ही गायों से भी सरोगेसी तकनीक के माध्यम से बेहतरीन नस्ल के बछड़े प्राप्त किए जाएंगे। संस्थान के वैज्ञानिकों ने बताया है, कि सरोगेसी तकनीक के जरिए वैज्ञानिक अच्छी नस्ल के सांड के वीर्य को एकत्रित कर लेते हैं। उसके बाद में चयन की गई नस्ल के अंडे लेकर के भ्रूण तैयार किया जाता है। उसके बाद में भ्रूण को गाय के अंदर प्रत्यारोपित कर दिया जाता है। इसके परिणाम स्वरुप गाय अच्छी नस्ल के बछड़े को पैदा करती है। जो गाय काफी अधिक मात्रा में दूध देती है।

सरोगेसी तकनीक का क्या फायदा होता है

सरोगेसी तकनीक का उपयोग करके एक अच्छी दुधारू नस्ल की गाय को जन्म दिया जा सकता है। जिससे दूध की आपूर्ति सुनिश्चित होने के साथ-साथ पशुपालकों एवं किसान भाइयों की आमदनी भी काफी बढ़ेगी।
इस तकनीक के माध्यम से गायों के जन्म लेने से पशुपालकों को काफी आर्थिक सहायता प्राप्त होगी। क्योंकि पशुपालकों को अच्छी दूध देने वाली गायों की सहायता से मोटी कमाई हो जाती है।

सरोगेसी तकनीक से प्राप्त हुए पशुओं से पशुपालकों को काफी मात्रा में दूध प्राप्त हुआ है।

सड़क पर निराश्रित पशुओं की भी तादात में होगी कमी

आपको बतादें कि गायों को सड़कों पर छुट्टा छोड़ने के पीछे सबसे बड़ी वजह यह है, कि जब तक वह दूध देती हैं, तब तक उनका पालन पोषण किया जाता है। जब गायें दूध देना बंद कर देती हैं, तो उनको निर्ममता से खुला छोड़ दिया जाता है। आवारा पशुओं की वजह से आए दिन सड़क हादसों के बारे में भी सुनने को मिलता है। किसानों की फसल को भी निराश्रित पशु काफी नुकसान पहुंचाते हैं। ऐसे में सरोगेसी तकनीक अच्छी और दुधारू नस्ल की गायों को तैयार करके दूध की मात्रा को बढ़ाएगी। जब पशुपालकों को दूध अधिक मात्रा में मिलेगा तो उनके पास पशुओं को छुट्टा छोड़ने का कोई मूलभूत कारण ही नहीं बचेगा।

मिट्टी की सेहत - खाद

किसानों को जागरूकता और सूझ बूझ से खेती करने की अत्यंत आवश्यकता है : MeriKheti.com

मथुरा में बायोगैस प्लांट (BIOGAS PLANT) बनाने जा रहा है अडानी ग्रुप, साथ ही, गोबर से बनेगी CNG

किसान भाई बेहद समस्याओं का सामना करते हैं। कभी प्राकृतिक आपदाएं तो कभी निराश्रित पशुओं से होने वाली हानि तो कभी फसल का समुचित मूल्य ना मिल पाना। किसान हमेशा चुनौतियों से घिरे रहते हैं। साथ ही, हमारे किसान भाई फसल उत्पादन करने से पूर्व किस फसल का चयन करें और किस फसल का नहीं उनको इस बात की जानकारी का अभाव होता है। इसलिए, आज भी किसान भाई परंपरागत तरीके से कृषि करने में अधिक विश्वास रखते हैं।

भूमिगत तौर पर किसान फसल वहां की मृदा और जलवायु के अनुरूप उगाते हैं। लेकिन फायदेमंद और लाभकारी विकल्प को चुनने में मात खा जाते हैं। यूँ तो भारत में बहुत सी अनुपयोगी चीजों का भी विपणन कर किसान भाइयों को गुमराह किया जाता है। लेकिन कुछ फसलें ऐसी भी हैं जिनका उत्पादन समय की मांग के अनुरूप किया जाए तो किसान अच्छी आय कर सकते हैं। किसानों को अगर सुखी और समृद्ध बनना है, तो उनको काफी सजग और जागरूक होने की अत्यंत आवश्यकता है। किसानों की दयनीय स्थिति को देखकर मेरीखेती टीम को काफी हमदर्दी होती है।

आजकल किसान सड़कों पर ज्यादा खेत में कम दिखाई देता है, कभी फसल हानि के मुआवजे की गुहार करने तो कभी फसल के समुचित न्यूनतम समर्थन मूल्य की माँग के लिए किसान सड़कों पर मायूस घूमता रहता है। किसानों को अपनी स्थिति को बेहतर बनाने के लिए कृषि वैज्ञानिकों और कृषि विशेषज्ञों के संपर्क में रहने की आवश्यकता है। क्योंकि कृषि के क्षेत्र में शोधकर्ता और जानकारों को काफी अनुभव होता है। इस बात के बहुत से प्रमाण भी हैं, कि कृषि वैज्ञानिकों की सलाहनुसार किसानों ने खेती करके अच्छी आय और पैदावार हांसिल की है। इनकी सलाह से खेती करने वाले किसान काफी फायदे में रहते हैं। क्योंकि इनको कृषि क्षेत्र के विषय में काफी जानकारी होती है। तो मानी सी बात है, कि किसानों को इससे काफी लाभ मिलेगा।

MERIKHETI.COM किसानों के लिए लिए हर माह किसान पंचायत आयोजित कराती है

MERIKHETI.COM किसान और कृषि विशेषज्ञों को एक दूसरे से सवाल जवाब करने के लिए एक मंच प्रदान करता है। जहां किसान भाई कृषि समस्याओं से संबंधित समाधान प्राप्त कर सकते हैं। मेरीखेती द्वारा इस आयोजन को निःशुल्क तौर पर केवल किसानों के फायदे के उद्देश्य से कराया जाता है। मेरीखेती टीम किसानों को सजग और जागरूक करने के साथ-साथ उनको अच्छी जानकारी मुहैय्या कराने का कार्य पूरी लगन से करती है। मेरीखेती टीम का केवल एक ही उद्देश्य है, कि किसानों को प्रमाणित और बेहतर जानकारी प्रदान करके उनको एक लाभकारी कृषि प्रणाली की तरफ अग्रसर किया जा सके। केवल इतना ही नहीं देशभर में जहां कहीं भी कृषि से संबंधित एवं किसानों के हित में कोई कार्यक्रम होता है, तो मेरीखेती की टीम उसे कवर करने जरूर पहुँचती है। प्रति माह किसान पंचायत होने से पूर्व उसकी जानकारी मेरीखेती की आधिकारिक फेसबुक पर दे दी जाती है।

किसानों को जागरूक होने की बेहद आवश्यकता है

किसान भाइयों को जागरूक होना ही पड़ेगा अन्यथा उनके हालात बदल नहीं पाएंगे। किसान यदि सही सूझ-बूझ और बेहतर तरीके से कृषि करें तो उनको काफी उन्नति और प्रगति हांसिल हो सकती है। MERIKHETI.COM वेब पोर्टल पर हम कृषि से जुड़ी सही और सटीक जानकारी किसान भाइयों को प्रदान करते हैं। साथ ही, कृषि से संबंधित किसानों की समस्याओं का भी हल यथावत रूप से उनको देने का भी कार्य करते हैं। हम किसानों के लिए समर्पित भाव से कार्य करते आए हैं। किसानों के विकास को प्राथमिकता में रखते हुए हम किसानों को बेहतर जानकारी देने से लेकर प्रति माह किसान पंचायत का आयोजन एवं अन्य हितकर कार्य करते हैं।

MERIKHETI